हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार दिनांक 25 अगस्त, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर-शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

25.08.2026/1100/बी.एस./एच.के.-1

प्रश्न संख्याः 2267 (स्थगित)

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद, यह जो सभा पटल पर सूचना रखी गई है, इस संबंध में मैंने वर्ष 2024-25 और 2025-26 के सरकार के तथा इकनॉमिक सर्वे में दिए गए आंकड़ों का अध्ययन किया है। इस सरकार का 5 लाख नौकरियां देने का वायदा था और इसमें सरकारी क्षेत्र तथा प्राइवेट क्षेत्र दोनों में रोजगार देने की बात कही गई थी। मैं उस संबंध में कुछ आंकड़े सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने 13 मुख्य डिपार्टमैंट्स का अध्ययन किया है। उनमें कुल 37 प्रतिशत वैकेंसीज अभी तक नहीं भरी गई हैं। इसके अलावा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में 24,603 सैंक्शन पोस्टें हैं जिनमें से 11,610 खाली पड़ी हैं। यह अपने आप में सरकार के दावों को बताती है कि 46-47 प्रतिशत पोस्टें खाली पड़ी हैं। यह एक फंक्शनल डिपार्टमैंट है और सबसे जरूरी विभागों में से एक है। इस विभाग में इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसीज खाली रहना चिंता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो टेबल देखे हैं उनमें सारी-की-सारी वैकेंसीज क्लास-III, लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन, टीमेट और इसी तरह अन्य कर्मचारियों की हैं जो लोग बिजली उपलब्ध करवाने के लिए धरातल पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी और रोजगार के मामले में सरकार का जो रिकॉर्ड है उसे मैं इकनॉमिक सर्वे के आधार पर बता रहा हूं। आपने जो लेटेस्ट इकनॉमिक सर्वे दिया है उसमें स्किल डवलपमैंट अलाउंस स्कीम में 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आपका बहुत बड़ा उद्देश्य सरकारी नौकरियों के साथ-साथ प्राइवेट सैक्टर में नौकरी देने का था इसके लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया लेकिन इसमें भी केवल 33 लाख रुपये दिए गए हैं और इसमें केवल 2764 बेनेफिशियरी हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी कल माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर कह रहे थे कि अभी हमारा साल पड़ा हुआ है और हम बहुत कुछ करने वाले हैं। आपकी सरकार का पिछले चार सालों का जो रिकॉर्ड है वह तो देखने वाली बात है। इसके अलावा स्किल डवलपमैंट अलाउंस देने की बात है जिसमें 94 लोगों को 4 लाख रुपये दिए गए हैं।

25.08.2026/1100/बी.एस./एच.के.-2

इसी तरह अनएम्प्लॉयमैंट अलाउंस की बात करें तो 3717 लोगों को वर्ष 2025-26 में 57 लाख रुपये दिए गए हैं। एम्प्लॉयमैंट एक्सचेंज के लाइव रजिस्टर में 5,18,807 लोग हैं। यह भी देखने वाली बात है कि इसमें से नौकरी कितने लोगों को मिली? केवल मात्र 375 लोगों को नौकरी मिली।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या पूछना चाहते हैं, कृपया उसी प्रश्न को पूछिए।

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि नौकरियों से संबंधित स्थगित प्रश्न पिछले एक साल से चला हुआ है। उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए?

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं कि आपकी राजीव गांधी रोजगार स्टार्टअप योजना है। इसमें 56 एप्लीकेशन्स थीं जिसमें आपने 600 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान करने की बात की है।

अध्यक्ष महोदय, ये सारी चीजें अपने आप में स्थिति बयां कर ही है। सरकार इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करे। साथ ही अपने विभाग को आदेश करे कि वे आंकड़ों का टोटल भी किया करें।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

25.08.2026/1105/DT/एचके-1

प्रश्न संख्या 2267... जारी

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रशासनिक सेवा में रहे हैं और ये प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छी तरह से जानते हैं। हमने कहा कि आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं तो आप कुल नौकरियों का टोटल खुद कर लेते तो अच्छा रहता। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो बातें कही हैं। पहली बात स्किल डवलपमैंट की है। स्किल का सीधा संबंध रोजगार से नहीं होता बल्कि इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि मैं यह कहूं कि स्किल के अंतर्गत वितरित धनराशि में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है तो यह भी गलत नहीं होगा। मैं अभी उस विषय को खोलना नहीं चाहता क्योंकि फिर कहा जाएगा कि इनक्वायरी करवाई जाए और मुझे वह भी करवानी पड़ेगी। स्किल कार्यक्रम के अंतर्गत आपने अनेक संस्थानों को परमिशनें दे दीं और कहा कि उन्हें प्रशिक्षण देना है तथा इसके लिए स्टाइपैंड भी दिया जाएगा। जहां 15 बच्चे भी नहीं थे वहां आपने 50 बच्चों का स्टाइपैंड दिया और कहीं-कहीं 500 बच्चों तक का स्टाइपैंड जारी कर दिया गया। इसलिए स्किल के विषय को फिलहाल वहीं रहने दीजिए। जहां तक रोजगार का प्रश्न है, हमारी सरकार का उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा करना है। सरकारी नौकरी एक अलग विषय है और रोजगार एक अलग विषय है। रोजगार के अवसर किस प्रकार उपलब्ध करवाए जाएं, इसके लिए हमने व्यवस्था परिवर्तन किया है। आपने एक और बात गलत कही कि हमने 'राजीव गांधी स्टार्टअप योजना' के तहत केवल 50 लोगों को सब्सिडी दी है। मैं बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार द्वारा जब प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था तो उसमें 'राजीव गांधी स्टार्टअप योजना' आरम्भ की गई थी जिसमें 680 करोड़ रुपये का प्रावधान था। इसके कई भाग थे और इसका उद्देश्य बड़े स्तर पर रोजगार सृजित करना था। योजना के पहले भाग में ई-टैक्सी कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इसके अंतर्गत लगभग 100 ई-टैक्सियां हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में लगाई गईं। 30 लाख रुपये की ई-टैक्सी पर 15 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई, 20 लाख रुपये की ई-टैक्सी पर 10 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई तथा 15 लाख रुपये की ई-टैक्सी पर साढ़े सात लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई। आज ये सभी टैक्सियां विभिन्न विभागों में संचालित हो रही हैं। यह इस योजना का पहला पार्ट था जिसमें 100 के करीब ई- टैक्सियां लगाई गई। अध्यक्ष महोदय, सब्सिडी केवल टैक्सियों तक सीमित नहीं थी। हमारा उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना तथा हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण का संरक्षण करना

25.08.2026/1105/DT/एचके-2

भी था। दूसरा, हमने यह भी कहा कि 15 लाख रुपये वाली टैक्सी पर पांच वर्ष तक प्रति माह 50,000 रुपये की एश्योर्ड आय प्राप्त होगी। 20 लाख रुपये वाली टैक्सी पर लगभग 65,000 रुपये प्रतिमाह तथा 30 लाख रुपये वाली टैक्सी पर लगभग 75,000 रुपये प्रतिमाह की एश्योर्ड आय का प्रावधान किया गया। ई-टैक्सी योजना के दूसरे चरण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इसमें भी 50 प्रतिशत तक सहायता प्रदान करके वाहनों को सरकारी विभागों में लगाया जाएगा। इससे सरकार को दो प्रकार के लाभ होंगे। एक ओर सरकार का खर्च कम होगा, क्योंकि न वाहन खरीदना पड़ेगा, न ड्राइवर रखना पड़ेगा और न ही मेंटेनेंस का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हमने 'राजीव गांधी सोलर पावर योजना' प्रारम्भ की है। इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति सोलर पावर प्रोजैक्ट स्थापित करेगा, उसे स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। ट्राइबल क्षेत्रों में ऐसे प्रोजैक्टों के लिए 4 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने 2 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजैक्ट लगाने के लिए 9 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण लिया है तो उसे निर्धारित दर के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। नॉन-ट्राइबल क्षेत्रों के लिए भी इसी प्रकार की सहायता का प्रावधान किया गया है। यह भी 'राजीव गांधी स्टार्टअप योजना' का ही एक भाग है। तीसरा, जो किसान प्राकृतिक खेती अपनाएगा और बिना यूरिया के खेती करेगा उसे भी 'राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना' के अंतर्गत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज सरकार गेहूं 80 रुपये प्रति किलो, मक्की 50 रुपये प्रति किलो, अदरक 30 रुपये प्रति किलो तथा हल्दी 150 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद रही है। ये सभी स्टार्ट-अप योजना से संबंधित योजनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश में कोई भी सरकार आए वे लोगों को कितना रोजगार दे सकती है? यानी हम सरकारी रोजगार के नाम पर लोगों या अपने युवाओं को धोखा नहीं दे सकते। अगर वे सोचते हैं कि वे 5000 रुपये, 12,000 रुपये या 15,000 रुपये की नौकरी के लिए बद्दी जा रहे हैं तो उससे अच्छा तो यह है कि वे अपने घर पर रहकर प्रतिवर्ष 4 से 5 लाख रुपये की आय अर्जित कर सके और अपनी आजीविका चला सके तो वही वास्तविक रोजगार है। हमारी सरकार ऐसी योजनाओं और ऐसे रोजगार के अवसरों पर कार्य कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आने वाले सयम में पाँच लाख से अधिक रोज़गार सृजित होंगे। यह व्यवस्था परिवर्तन का परिणाम है। मैं यह

भी कहना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में जो अनेक फंक्शनल पोस्टों की बात की जा रही है वे केवल हमारे समय की नहीं हैं। आपकी सरकार के समय में भी अनेक पद रिक्त रहे थे और उन्हें नहीं भरा गया था। लेकिन हमने पोस्टों का रैशनलाइजेशन

25.08.2026/1105/DT/एचके-3

किया है। जब किसी स्कूल में बच्चे ही नहीं हैं और वहां तीन-तीन अध्यापक तैनात हैं तो ऐसे स्कूलों का रैशनलाइजेशन करके उन तीन अध्यापकों को उन स्कूलों में भेजा जाए जहां बच्चे हैं।

श्री एन0 जी0द्वारा जारी

25.08.2026/1110/वाई.के.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या-2267............जारी मुख्य मंत्री.......... जारी

हमारी सरकार ने इस प्रकार से कार्य किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में तो मैंने आपको बताया है कि आपकी सरकार के समय में अस्पताल 35 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी पर चल रहे थे। लेकिन आज 65 प्रतिशत पर चल रहे हैं। 500-600 के करीब असिस्टेंट स्टाफ नर्सिज़ लग गई हैं और 400 का इंटरव्यू होने वाला है। **हमारा एक विचार है कि अगले मार्च और जून तक पूरे मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल स्टाफ की जो पोस्ट हैं, वे सारी भर देंगे ताकि हॉस्पिटल में पैरामेडिकल और डॉक्टरों की कोई कमी न रहे।** डॉक्टरों की कमी तो 40 साल से है और हमें तो 3.5 साल ही हुए हैं। अस्पतालों में 19 साल पुरानी मशीनें लगी हैं, उनसे लोगों का हम इलाज कहां कर पाते हैं?

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने राजीव गांधी मत्स्य योजना शुरू की है। यह योजना भी माननीय सदस्य के क्षेत्र में है। कभी यह

नहीं सोचा गया था कि जो मछुआरे सुबह उठकर सतलुज में या बांध में जाकर मछलियां पकड़ते हैं, उनसे 15 प्रतिशत सरकार रॉयल्टी लेती थी। हमने उसे 1 प्रतिशत पर लाया और कहा कि बरसात के समय जब दो महीने बंद होते हैं, उनको हर महीने का 3,500/- रुपये देंगे। अभी उस योजना को हमने शुरू किया है। वह भी स्टार्टअप योजना है, वह भी रोजगार है। उनको बोला कि अगर आप बोट खरीदोगे तो 80 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। नेट खरीदोगे तो उसमें भी सब्सिडी मिलेगी। हमने इसके संदर्भ में बजट के दौरान भी घोषणा की थी। हमारी सरकार रोजगार के पांच लाख से ज्यादा अवसर हम पैदा करने की कोशिश कर रही है और इसमें हमें सफलता भी मिल रही है। ऐसे कार्यों में थोड़ी अड़चनें होती हैं और समय लगता है। जब किसी व्यवस्था में ट्रांज़िशन होता है और व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में ट्रांज़िशन हुआ है तथा हमने नई सोच विकसित की है। किसी ने नहीं सोचा था कि किसी सरकार के दौरान इलेक्ट्रिकल टैक्सी चलेगी। आज मैं भी इलेक्ट्रिकल टैक्सी में जाता हूं। यह व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है और इसमें रोजगार

25.08.2026/1110/वाई.के.-एन.जी./2

के अवसर लोगों को मिलेंगे। अभी तो स्टार्टअप हो रहा है और लोग अपने आप काम करेंगे, फिर दूसरों को रोजगार देंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं है।

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया हुआ है और मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत सारी बातें बताईं हैं। मुझे भी कुछ इस पर अगर संशय होगा तो प्रश्न करना मेरा अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह 5 लाख रोजगार वाला जो मैयरमेंट होता है न, हर एक चीज का आपको पांच साल का मैयरमैंट है। आपने पांच सालों में बोला था, उसके बारे में भी स्पष्ट करें। आपका जवाब परसों आया है और मैं

फिगर्स बोल रहा हूं कि विभिन्न विभागों में 37 प्रतिशत पोस्टें खाली हैं। बिजली बोर्ड में 47 प्रतिशत पोस्टें खाली हैं। मैं सरकार के जवाब से देख कर ही बोल रहा हूं।

सेकेंडली, आप जो मछुआरों की बात कर रहे हैं, उसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार की जो स्कीम है, 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना', उसमें एक पूरा सर्किल है। उसमें प्रत्येक मछुआरे को 3,000/- रुपये और 1,500 रुपये का कंट्रीब्यूशन देते हैं। 3000/- रुपये में से 600/- रुपये प्रदेश सरकार देती है और 2,400/- रुपये केंद्र सरकार देती है। हर एक मछुआरे को 4,500/- रुपये का पैकेज दिया जाता है और आप एक परिवार को दे रहे हैं। अभी आपने मेरे चुनाव क्षेत्र में फंक्शन किया था और , मैंने भी आपका स्वागत किया था।

25.08.2026/1110/वाई.के.-एन.जी./3

मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने पूरे हिमाचल प्रदेश से कुल 1499 परिवार छांटे हैं। जबकि वे 40 हज़ार से ज्यादा परिवार हैं। यह हर एक चीज का मैयरमेंट होता है। आपने बोला था कि पांच सालों में पांच लाख नौकरियां देंगे। अभी आप बोल रहे हैं कि विजिबल-इनविजिबल सारे रोजगार हम दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो कहीं दिखा दीजिए। अगर टाइम लगने की बात है तो पांच साल के टाइम के अंतराल के बीच में ये फैसले होते हैं। मैंने कहा कि राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के 56 केसिज़ आए हैं तो आप ही बताओ कि आपने कितने आदमियों को रोजगार दिया? सरकार के पास तो सब कुछ होता नहीं है और मैं यह जानना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य IAS ऑफिसर रिटायर्ड हुए हैं। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से कोई भी पैसा नहीं दिया गया। यह राजीव गांधी मत्स्य मछुआरा सम्मान निधि है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुन लीजिए।...(व्यवधान) आप जवाब सुन लीजिए।...(व्यवधान) आप बैठ जाओ।...(व्यवधान) आप एक दम से उठ मत जाया करो।...(व्यवधान)

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

25.08.2026/1115/YK/PB/1

प्रश्न संख्याः 2267 क्रमांगत... अध्यक्ष जरी...

पहले जवाब पूरा होने दीजिए। फिर आपका कोई अनुपूरक प्रश्न हो तो उसे लिख लीजिए मैं आपको प्रश्न पूछने के लिए बाद में इजाजत दूंगा। Please, take your seats. This is not proper. ...(Interruption)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मछुआरों की स्थिति को देखते हुए हमारी सरकार ने यह योजना बनाई है। इसमें प्रधान मंत्री मत्स्य योजना का एक भी पैसा नहीं है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार ने जो 3,500 रुपये दिए गए हैं, वह प्रदेश की संपदा को भ्रष्टाचार के रास्ते से बचाकर प्राप्त हुई राशि में से बांटा गया है। **माननीय सदस्य 1,500 रुपये की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 40,000 मछुआरों को योजना का लाभ नहीं मिला है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार अपने पैसे से 40,000 मछुआरों को भी यह राशि देगी।**

दूसरी बात, माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार ने केवल 37 प्रतिशत वैकेंसी भरी हैं। यह वैकेंसी पूर्व की भाजपा सरकार के समय से थी। हमारी सरकार ने 65 प्रतिशत तक रिक्तियां भर दी है। हमें 65 प्रतिशत तक पहुंचने में समय तो लगेगा। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि हम सारी भर्तियां राज्य चयन आयोग एवं लोक सेवा आयोग के माध्यम से कर रहे हैं। हमने राज्य चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों में पर्सनल इंटरव्यू बिल्कुल खत्म कर दिया है। जो अभ्यर्थी रिटन में राज्य चयन आयोग की मेरिट में होगा वही नौकरी लगेगा, बाकी कोई नहीं लगेगा। इस तरह से न पेपर लीक होंगे और न ही पेपर बिकेंगे।

तीसरी बात, लोक सेवा आयोग में भी पिछले 30-40 वर्षों से एक व्यवस्था चली हुई थी कि रिटन एग्जामिनेशन में अभ्यर्थी व युवा रिटन मेरिट पास कर देते थे। अगर किसी अभ्यर्थी के रिटन में 80 प्रतिशत अंक है तो वह अंक अंतिम परिणाम में नहीं जोड़े जाते थे। उनका सिर्फ साक्षात्कार लिया जाता था और उसके आधार पर 80 प्रतिशत अंक वाला अभ्यर्थी भी पास होता था तथा 50 प्रतिशत अंक वाला भी पास होता था। कई बार ऐसा भी हुआ है कि 50 प्रतिशत अंक वाले अभ्यर्थी लग गए और 80 प्रतिशत

25.08.2026/1115/YK/PB/2

अंक वाले, मेरिट वाले अभ्यर्थी नहीं लग पाए। सरकार ने उनके लिए भी नीति बनाई है कि रिटन प्लस पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा।

सरकार ने रोजगार के अवसरों में एक और व्यवस्था परिवर्तन किया है ताकि मेरिटोरियस युवाओं के साथ अन्याय न हो। एस0सी0 कैटेगरी के 30 प्रतिशत अंक पास मार्क्स थे और जनरल कैटेगरी के 35 प्रतिशत अंक पास मार्क्स थे। सरकार की मंशा राज्य चयन आयोग और लोक सेवा आयोग में क्वालिटी इम्प्रूव करने की है इसलिए हमने पास मार्क्स बढ़ाए हैं क्योंकि अध्यापकों, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति हो रही है। ये वे चीजें हैं जहां हमें क्वालिटी चाहिए। हमने एस0सी0 के लिए 40 प्रतिशत और जनरल के लिए 45 प्रतिशत पास मार्क्स किए हैं। यह व्यवस्था परिवर्तन हर जगह हुआ है। यह रोजगार सरकार ने पैदा किया है।

माननीय सदस्य जो 37 प्रतिशत और 47 प्रतिशत की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हमने हेल्थ में 37 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत तक रिक्तियां भर दी हैं। आने वाले समय में भी जो फंक्शनल पोस्ट होगी और जहां पोस्ट की जरूरत होगी, वहां उस पोस्ट को भरा जाएगा। मैं माननीय सदस्य को यह भी कहना चाहता हूं कि आप निश्चित रहिए। हमारी सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी में विश्वास करती है।

अध्यक्ष महोदय, इस मंच के माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहता हूं।...(व्यवधान) माननीय सदस्य बिक्रम जी आप बैठ जाइए, अभी मुझे बोलने दीजिए फिर आप बोल लेना। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आउटसोर्स को कम करने के लिए एक नीति पर काम कर रही है और आउटसोर्स में लगे कर्मचारियों के भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाए उस नीति पर भी हमारी सरकार कार्य कर रही है।...(व्यवधान)

25.08.2026/1115/YK/PB/3

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी कुछ कहना चाहते हैं।...(व्यवधान) इस प्रश्न पर अभी आगे चर्चा भी होनी है।...(व्यवधान) कोई बात नहीं, जब चर्चा होगी आप तब अपनी बात रखना।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि इस व्यवस्था परिवर्तन के दौर में सारी व्यवस्थाएं तहस-नहस हो गई हैं। यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं, व्यवस्था पतन है।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं पहले एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमें प्रश्न के उत्तर एक घंटा पहले मिलते थे। अब व्यवस्था परिवर्तन का दौर आया है और हमें प्रश्न के उत्तर 15-20 मिनट पहले मिल रहे हैं। हमें अध्ययन करना होता है कि प्रश्न का उत्तर क्या आया है और उसमें क्या आंकड़े दिए हैं। मैं समझता हूं कि इसको ठीक करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष जी, मैं इसे ठीक करवा दूंगा।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, अगला विषय यह है कि मेरा प्रश्न गायब है। इसमें मेरे प्रश्न का पूरा कचरा कर दिया, कचूमर निकाल दिया है।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष जी, आप अलग से सप्लीमेंटरी के तौर पर प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री जय राम ठाकुर श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

25.08.2026/1120/ए0जी0/ए0पी0-01

प्रश्न संख्या 2267 जारी ......

अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न था वो तो गायब है। मेरे प्रश्न का पूरा कचरा कर दिया है, कचूमर निकाल दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो सही बात है पक्ष उसका जवाब दे। मुझे लगता है कि आप बात का सही जवाब देंगे। सत्ता में आप आए हैं और आपने दस गारंटियां दी है। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण गारंटी यह है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पहली कैबिनेट की बैठक में एक लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी जोकि पक्की नौकरियां होगी, 58 साल वाली नौकरियां होगी और पेंशन वाली नौकरियां होगी। उसके बाद एक गारंटी यह भी थी कि पांच सालों में पांच लाख नौकरियां भी देंगे। यह आपका लोगों के बीच एक कमिटमेंट है। जिसकी वजह से आप इस समय सत्ता पक्ष में बैठें हैं। सत्ता में आने के बाद अभी तक आपका पौने चार साल का कार्यकाल बीत चुका है। अगर हम आपके कार्यकाल की ओर नजर करें तो अभी तक हिमाचल प्रदेश में चार लाख के करीब नौकरियां आपकी सरकार को दे देनी चाहिए थी। लेकिन आज स्थिति क्या है? आप मुझे बताएं जरा, आपकी सरकार में कितने पद खाली हैं? मैं सभी का जिक्र नहीं कर रहा हूं। पुलिस विभाग में 3,753 पद विभिन्न श्रेणी के खाली हैं। जल शक्ति विभाग जो हमारे उप-मुख्यमंत्री जी के पास है उसमें 517 पद खाली हैं। राज्य विद्युत निगम बोर्ड में 3,635 पद खाली हैं। यह ऐसे विभाग हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग में देखे तो इसमें 2,768 पद खाली हैं। इसके बाद उच्च शिक्षा (हायर एजुकेशन) 3,432 पद खाली हैं। प्राइमरी एजुकेशन में 10,853 पद खाली हैं। उसके बाद हम देखें तो माननीय सदन में नियम-130 के अंतर्गत बेहतर स्वास्थ्य की चर्चा हो रही है। High-end Health services मुहैया करवाने की आज बातें की जा रही हैं। अगर में स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग में 1,298 पद खाली है, यानी लगभग 1,300 के करीब पद खाली हैं। हम जिक्र करें तो किस-किस बात का जिक्र करें? इसलिए हम मुख्य मंत्री जी से बार-बार बात कर रहे हैं। आपके चार साल होने जा रहे हैं लेकिन आप काम शुरू कब करेंगे?

दूसरा मैं इस माननीय सदन में मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमने हिमाचल प्रदेश में मुख्य मंत्री स्वाबलंबन योजना को शुरू किया था। इस योजना का क्या

25.08.2026/1120/ए0जी0/ए0पी0-02

क्या स्टेटस है? मुख्य मंत्री जी ने एक काम जरूर किया है वह यह है कि जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में चलाई गई थी। वे सभी योजनाएं तो लगभग वैसी ही हैं। थोड़े-सा परिवर्तन किया है, इस व्यवस्था परिवर्तन के दौर में आपने जो करना था वो ये किया। लेकिन एक काम आपने ज़रूर किया कि कोई योजना ऐसी नहीं छोड़ी, जिस योजना के पीछे या आगे या तो आपने अपना नाम जोड़ दिया है या फिर गांधी का नाम जोड़ दिया। दो ही नाम हैं इस देश में, एक श्री सुखविंदर सिंह सुखु जी के नाम से चलती है मुख्य मंत्री सुख आश्रय योजना जिसका हमेशा जिक्र होता है या फिर वह योजनाएं जिनमें राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का जिक्र होता है। इसके अतिरिक्त किसी योजना का जिक्र ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी हमें बातए की जो प्राकृतिक खेती का हमने शुरू किया था, उसका क्या स्टेटस है, उसका बजट प्रोविजन आपने क्या रखा है? मुख्य मंत्री स्वाबलंबन योजना को बदल कर राजीव गांधी जी के नाम पर कर दिया गया। उस योजना का क्या स्टेटस है? आप नाम बदल करके राजीव गांधी के नाम पर लिखिए, राजीव गांधी जी का योगदान क्या रहा है। आप यह स्पष्ट करें और उसमें कितने लोगों को आपने रोजगार दिया। प्रश्न तो हमने बहुत पूछे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक-एक योजना को या तो इस सरकार के समय बंद कर दिया या फिर उस योजना का नाम बदल दिया गया या फिर अपने नाम पर या तो गांधी जी के नाम पर कर दिया गया। आप इन सारी बातों को स्पष्ट करेंगे कि मुख्य मंत्री स्वाबलंबन योजना के अंतर्गत कितने लागों को रोजगार मिला था, उसमें वर्तमान में क्या स्टेट्स है। अपनी सरकार के समय में हमने 3,950 बेरोजगार नौजवानों को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए सहायता की थीं, इस योजना का स्टेट्स क्या है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

25.08.2026/1125/AT/AG/01

प्रश्न संख्या 2267 जारी......

श्री जय राम ठाकुर जारी...

या तो उस योजना को बंद कर दिया या फिर उस योजना का नाम या तो अपने नाम पर, या गांधी जी के नाम पर कर दिया। आप इस सारी चीज़ को स्पष्ट करेंगे। आप इस बात को लेकर स्पष्ट करेंगे कि मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला था और उसका वर्तमान में स्टेटस क्या है? ...(व्यवधान) 3,950 यानी कि लगभग चार हज़ार नौजवानों को अपने पांव पर खड़े होने के लिए मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना का स्टेटस क्या है? उस योजना को आपने बंद कर दिया? उसका नाम बदलकर कुछ और कर दिया?...(व्यवधान)

Speaker : Let the Hon'ble Chief Minister reply.

श्री जय राम ठाकुरः तमाम सारी चीज़ों का सिलसिलेवार जवाब दें। आप सदन में मेहरबानी करके जो सत्य है, वह बोलें। सत्य बोलें, जो ठीक बातें हैं, वह बोलें। ये जो घुमा-फिराकर आप चीज़ों को रखने की कोशिश करेंगे, इससे सदन गुमराह होता है। सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। मेरा आपसे यही निवेदन है। आप सही जवाब देंगे तो हम यहां पर हाज़िर हैं।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री महोदय, नहीं-नहीं, ...(व्यवधान) तो कोई डिस्कशन थोड़ी है।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आठ मिनट का सवाल है। ...(व्यवधान)

अध्यक्षः पच्चीस मिनट हो गए?

मुख्य मंत्रीः आठ मिनट का तो सवाल इन्होंने किया और आज आपने व्यवस्था तार-तार की जगह तहस-नहस कर दी। मैं दो बातें पहले क्वेश्चन से संबंधित स्पष्ट कर दूं। मेरा नाम सुखविंदर सिंह है, सुख नाम नहीं है। सुख हैप्पीनेस है, जिस तरह जय हिंद, जय राम नहीं

है। इसलिए जय हिंद है, तो यह जय राम का नाम नहीं जी है, जय हिंद है। उसी तरह मेरा नाम सुखविंदर सिंह है, सही मायने में सर्टिफिकेट में। तो सुख नहीं है।...(व्यवधान)

25.08.2026/1125/AT/AG/02

अध्यक्ष : वैसे तो जय श्री राम है।

मुख्य मंत्री : सुख हैप्पीनेस को इंगित करता है। सुख नाम है मेरा। सुख राम जी थे, जैसे पंडित अनिल शर्मा जी के पिताजी हमारे कम्युनिकेशन मंत्री थे, उनका नाम था सुख राम जी। उनके नाम से भी तो हो सकती है यह योजना। अब ये उनके नाम से भी हो सकती है। इसलिए आप भी मेरे नाम से थोड़ी ज़्यादा लर्जर हैं। जैसे आपके नाम के आगे मैं बोलता हूं जय हिंद, तो आपका नाम थोड़ी ले रहा हूं। मैं हिंद का नाम ले रहा हूं। एक और बात...(व्यवधान) प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय तो भर्तियां हुई नहीं। इनके समय कोई भर्तियां नहीं हुईं। आपने अभी 130 के तहत डिस्कशन लगाया है, मैं अभी क्यों बोलूं? समय भी तो जवाब देना है इनको। अच्छा-अच्छा जवाब दूंगा उस समय। उस समय अपने पूछ लेना, पूरा अच्छी तरह जवाब दूंगा। ठोंक-बजा के देंगे। पर अभी मैं आपको बताना चाहता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : फंक्शनल पोस्ट का बता दो।

मुख्य मंत्री : फंक्शनल पोस्टें जितनी भी हैं, जब से सरकार आई है, कंप्यूटरीकरण पर ज़ोर दिया। जितनी भी फंक्शनल पोस्टें हैं, उसमें जो रिलेवेंट पोस्टें हैं, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। अब आपको एक मैं बताऊं, पिछले कई सालों से अभी इन्होंने इसमें उनका नहीं आया। जो असिस्टेंट स्टाफ नर्सेज हमने भरी हुई हैं, असिस्टेंट टीचर भरे हुए हैं, असिस्टेंट कई चीज़ें भर रही हैं, उनका कुछ नहीं आया।

पुलिस का एक उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि पुलिस में आपके समय सिर्फ एक बार भर्ती निकली, एक बार। जो बड़ी मुश्किल से, जिसमें पेपर लीक हो गया, पेपर लीक

होकर पेपर बांट दिए। हमारे समय अभी 1,350 पुलिस वालों की भर्ती हो चुकी है और मैं आपको कहना चाहता हूं कि पांच साल में इतनी भर्ती करेंगे, क्योंकि भर्ती इसलिए करनी पड़ रही है कि हमारे जो लोग हैं, अग्निवीर के चक्कर में जा नहीं रहे। तो पुलिस में भर्ती कर रहे हैं और एक हज़ार ...(व्यवधान) आपको पता नहीं क्या हो जाता है, ठाकुर साहब। अब बैठकर मत बोलिएगा, आप अच्छे नहीं लगते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, आपने खड़े

25.08.2026/1125/AT/AG/03

होकर आठ मिनट बोल दिया। . ...(व्यवधान)आप बोलते बहुत अच्छे लगते हैं खड़े होकर, पर आप गुस्से में जब ऐसे इशारे करते हैं, ज़ोर-ज़ोर से, तब नहीं अच्छे लगते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक हज़ार पुलिस की भर्ती और शुरू है। और मैं कहना चाहता हूं कि एक हज़ार भर्ती के बाद जितनी **और वैकेंसी पुलिस में होगी, क्योंकि वहां नेसेसिटी है, उनको भी हमारी सरकार भरेगी।** धन्यवाद।

अध्यक्षः नेक्स्ट क्वेश्चन 4038, माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल। ...(व्यवधान) आपका क्वेश्चन थोड़ी है इसमें। ...(व्यवधान) अभी बैठो एक मिनट। नियम 130 में भी यह इश्यू डिस्कशन पर है। आधा घंटा हो गया है,

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी ......

25.08.2026/1130/av/as/1

मैंने दूसरे प्रश्न भी लेने हैं। ...(व्यवधान) नहीं, नहीं, Shri Bikram Singh Jee, please take your seat now.

(विपक्ष की ओर से सभी माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर शोरगुल करने पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी कुछ माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीट पर खड़े हो गए।)

प्रश्न संख्या : 4038

अध्यक्ष : श्री इन्द्र दत्त लखनपाल अनुपस्थित है।

प्रश्न संख्या : 4415

अध्यक्ष : श्री सतपाल सिंह सत्ती, not interested.

...(व्यवधान) Nothing is going on record. …(Interruption) This, I have not permitted. यह इश्यू नियम-130 के अंतर्गत भी चर्चा हेतु लगा हुआ है। ...(व्यवधान) इसका नियम-130 के अंतर्गत जवाब आ जाएगा। ...(व्यवधान) …(Interruption) This, I have not permitted. …(Interruption) महत्वपूर्ण है, इसीलिए नियम-130 में लिस्टिड है। ...(व्यवधान) नहीं बैठेंगे तो यह आपकी इच्छा है परंतु मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। ...(व्यवधान) क्या हुआ, फिर आपने नियम-130 के अंतर्गत क्या चर्चा करनी है? ...(व्यवधान) You have raised a lot of queries that stand replied by the Hon'ble Chief Minister still you are insisting in the Question Hour whereas more than half an hour that has been exhausted on this Question. There are other questions from the Hon'ble Members also. They have also right to ask the questions. You are trying to dictate the Chair time and again. This is not proper way and I will not allow. All the time, I will not have your dictation. Now, this we will not permit. When there is a discussion proposed under Rule-130 and in any case if you are not satisfied, there is other rules also. ...(Interruption) Why should I permit? ...(Interruption) Why should I permit? Take your seats please. ...(Interruption) Please take your seats now. I am not permitting you. ...(Interruption) I am not permitting you. This is bad ...(Interruption) This is

25.08.2026/1130/av/as/2

bad. You have exhausted half an hour on the one question and time and again you are insisting and directing the Chair. This is not proper way. I don't like this kind of behaviour. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Mr. Vinod Kumar I am

likely to take a very strong action against you. Mr. Vinod Kumar, I am likely you to name you now. ...(Interruption) You just sit down. ...(Interruption) You all sit down please. ...(Interruption)There is a discussion under Rule-130. You will not be dictating me. ...(Interruption). These rules will be important. ...(Interruption) I will not have your dictation. ...(Interruption) I am likely to name three-four persons. ...(Interruption) Sit down please. ...(Interruption) Sit down please. ...(Interruption) Sit down please. ...(Interruption) Sit down please. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption). This will not go record. I am not permitting it because already we have taken more than 25 minutes' in discussing one question. There are other question of the Hon'ble Members also which have to be part of the proceedings. The protest is uncalled for, undesired and will not be the part of the record.

(सत्ता पक्ष के सभी सदस्य अपनी-अपनी सीट पर बैठ गए परंतु विपक्ष की तरफ से माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी शुरू की गई।)

प्रश्न संख्या : 4416

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि परौर से पधर तक फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री किशोरी लाल ने यह पूछा है कि परौर से पधर तक फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य कब तक कर दिया जाएगा? जिसके संदर्भ में मैं यह बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के क्षेत्रीय

25.08.2026/1130/av/as/3

कार्यालय, शिमला से प्राप्त सूचना के अनुसार परौर से पधर तक फोरलेन सड़क के निर्माण कार्य हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने का कार्य कंसल्टेंट को दिनांक 12.03.2026 को

अवार्ड कर दिया गया है तथा सड़क की अलाइनमैंट का कार्य अभी प्रारंभिक स्तर पर है। अतः सड़क निर्माण कार्य के प्रारंभ होने की समय-सीमा और वास्तविक स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र के संबंध में स्पष्ट जानकारी डी0पी0आर0 के तैयार एवं स्वीकृत होने के पश्चात ही उपलब्ध हो सकेगी।

टी सी द्वारा जारी

25.08.2026/1135/टी0सी0वी0/ए0एस0-1
प्रश्न संख्या : 4416... क्रमागत्
लोक निर्माण मंत्री ...जारी

इसके साथ ही राजमार्ग प्राधिकरण एन0एच0ए0आई0 के क्षेत्रीय कार्यालय शिमला से प्राप्त सूचना के अनुसार प्ररौर से चक्की तक की फोरलेन परियोजना का निर्माण कार्य पांच पैकेज में किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें से अभी तक एक पैकेज का कार्य पूर्ण हो चुका है व तीन पैकेज का कार्य प्रगति पर है तथा एक अन्य पैकेज में डी0पी0आर0 बनाने का कार्य भी प्रगति पर है। इस फोरलेन से अभी तक 5,764 परिवार प्रभावित हुए हैं। कार्य की अद्यतन स्थिति सहित पूर्ण ब्योरा लिखित उत्तर के साथ में संलग्न है।

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्ररौर से पधर तक जो कार्य शुरू किया गया है उसमें जो पुरानी अलाइनमैंट तथा पुराना सर्वे था, क्या नई सड़क उसी सर्वे के आधार पर बनाई जाएगी या उस सर्वे में परिवर्तन किया जाएगा?

दूसरा प्रश्न यह है कि प्ररौर से चक्की तक जो परिवार प्रभावित हुए हैं, क्या सरकार ने उन्हें मुआवजा दे दिया है और उनका पुनर्वास हुआ है या नहीं? मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने उत्तर में कहा है कि प्ररौर से पधर तक का जो पहला पार्ट है जिसके बारे में सदस्य ने कहा है because the DPR is in the consultation stage right now और इसकी अभी डी0पी0आर0 बनाई जा रही है। इसलिए

उसकी अलाइनमैंट की जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि वह नई अलाइनमैंट पर बन रही है या पुरानी अलाइनमैंट पर ही बन रही है।

दूसरा विषय मुआवजे का है। इसमें कहा गया है कि इस फोरलेन में अभी तक 5,734 परिवार प्रभावित हुए हैं। इसमें एन0एच0ए0आई0 का जैसा प्रस्ताव रहेगा उसके अनुसार भूमि अधिग्रहण होने पर मुआवजा दिया जाएगा और इसकी पूरी जानकारी सदस्य को लिखित रूप में उपलब्ध करवा दी जाएगी।

25.08.2026/1135/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए)

प्रश्न संख्या : 4417

अध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ0 हंस राज, are you not interested to ask the question? Okay.

प्रश्न संख्या : 4418

Revenue Minister : Sir, the reply is No. Government has not issued any orders or instructions for regularization of public path and roads being used by general public on the basis of adverse possession or Right of way.

श्री विनोद सुल्तानपुरी : स्पीकर सर, मैं सैप्लीमेंटरी करना चाहता हूं क्योंकि जिस तरह से सरकार ने म्यूटेशन को एक टारगेट-ओरिएंटेड काम किया था उसी तरह मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि गिरदावरी को टारगेट करके जो रास्ते लंबे समय से विद्यमान हैं और दस्तावेजों में दर्ज हैं उनकी भी गिरदावरी करवाई जाए क्योंकि विशेष रूप से कसौली निर्वाचन क्षेत्र में उन पर बहुत अधिक अतिक्रमण हो रहा है। यदि सरकार द्वारा हमारी गिरदावरी को टारगेट-ओरिएंटेड तरीके से किया जाए और जो रास्ते पहले से परिभाषित हैं तथा हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग कागजों में कहीं और हैं और

जमीनी स्तर पर कहीं और हैं तो इस प्रकार की मुहिम को मंत्री जी आगे बढ़ाएंगे तो यह बहुत बेहतर होगा।

इसी तरह टी0सी0पी0 के द्वारा जो सैटबैक्स रखे जाते हैं जिसमें सार्वजनिक रास्ता होता है उस रास्ते का बाद में सभी प्रकार की परमिशन्स मिलने के बाद किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग होने लगता है। मेरा केवल अनुरोध यह है कि सार्वजनिक उपयोग के जो रास्ते हैं या सड़कें हैं उनकी जमीनी स्थिति के अनुसार गिरदावरी होनी चाहिए। यह मैं अनुरोध करना चाहता हूं। धन्यवाद सर।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन ने यहां एक बहुत ही अहम मुद्दा प्रश्न के रूप में रखा है। इसमें विशेषकर लंबे समय से जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं जिसमें सड़कें

25.08.2026/1135/टी0सी0वी0/ए0एस0-3

भी शामिल हैं उनमें लोगों ने किसी समय स्वेच्छा से भूमि दी थी। परंतु समय के साथ संबंधित डिपार्टमेंट्स ने उस भूमि को अपने नाम पर दर्ज नहीं किया। इसी का फायदा उठाकर कई सौ केसिस हाई कोर्ट में पेंडिंग हो गए हैं जहां अब ये लोग कम्पेनसेशन की मांग कर रहे हैं क्योंकि जमीन की वैल्यू बढ़ गई है।

एन0एस0 द्वारा .. जारी

25-8-2026/1140/NS-DC/1

प्रश्न संख्या : 4418-----क्रमागत

राजस्व मंत्री ------जारी

क्योंकि जमीन की वैल्यू बढ़ गई है। इसके लिए माननीय सदन में सरकार एक बिल लाई थी 'The Himachal Pradesh Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2025'. इस बिल के माध्यम से जो भी लंबे समय से पब्लिक यूटिलिटीज हैं विशेषकर रोड्स, फुटपाथ्स या कोई भी स्ट्रक्चर्स जो पब्लिक के यूज में रहे हैं या बीन्ग यूज्ड हैं उन पर कोई भी व्यक्ति दोबारा क्लेम नहीं कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह बिल माननीय सदन से तो

पास हो गया है लेकिन अभी प्रेजिडेंशियल असेंट के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है। यह कानून अभी आया नहीं है। जब आएगा तो हमें इसका बहुत फायदा होने वाला है। जहां तक खसरा गिरदावरी की बात है तो हमने इंस्ट्रक्शन्स दी है कि जो भी खसरा गिरदावरी है वह मौके पर की जाए और मौके पर जो भी स्ट्रक्चर, पाथ या मौके के हिसाब से वहां की जो सिचुएशन है वह रेवेन्यू में एंटर होनी चाहिए और इसकी हिदायत हमने दे रखी है। अगर कोई एन्क्रोचमैंट करता है तो उसके लिए एन्क्रोचमैंट एक्ट या पब्लिक प्रीमिसिस एक्ट के तहत प्रावधान है। **माननीय सदस्य, आप हमें स्पेसिफिक मामला दीजिए हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे।**

श्री संजय अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंटरी क्वैश्चन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अर्की डिवीजन में भी कुछ ऐसे रोड्स हैं जो विभाग के नाम नहीं हुए हैं। अभी हाल ही में वहां भराड़ीघाट से पिपलूघाट होते हुए फोरलेन बन रहा है। इस गलती का नुकसान मेरे क्षेत्रवासियों को सहना पड़ रहा है जिनकी जमीनें उस अधिग्रहण में गई हैं जहां नेशनल हाईवे पर यह फोरलेन बनना है। कागजों में रोड न होने की वजह से उनको पूरा रेट जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि ऐसे लोग, जैसे कोटला और बहल गांव के लोगों को अधिग्रहित जमीन का कंपन्सेशन बहुत कम मिला है। मेरा निवेदन है कि वहां इस गलती को सुधार कर उनको पूरा मुआवजा दिया जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विषय को लेकर एक कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है। मेरी अध्यक्षता में इस कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं। इसमें खासकर पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जितनी

25-8-2026/1140/NS-DC/2

भी सड़कें हैं उनकी खसरा गिरदावरी करके रेवेन्यू एंट्रीज की जाएं। जहां एंट्रीज नहीं हुई हैं उसमें मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे करेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंट्रीज के माध्यम से एंट्रीज करवा सकते हैं। अगर किसी जमाने से रोड बनी हुई है तो उसकी एंट्री कर सकते हैं ताकि लोगों को उसका लाभ हो और सरकार भी अननैसेसरी लिटिगेशन से बच सके।

श्री विनोद सुल्तानपुरी : सर, इसमें हमने कई बार पाया है कि मेरे स्पेसिफिक कांस्टिच्यूएंसी में सड़क में एन्क्रोचमैंट होने पर वे उसकी कंप्लेंट भी करते हैं और पुलिस रिपोर्ट भी करते हैं परन्तु अल्टिमेटली पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा उसको रिमूव करने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है और वे बेचारे धरे-के-धरे रह जाते हैं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि इसे इफैक्टिव बनाया जाए कि अगर वहां कहीं कोई एन्क्रोचमैंट पाई जाती है तो उसको तुरन्त रिमूव करने के लिए सरकार को इस तरह का प्रावधान करना चाहिए। जब वे वहां कंटिन्यूटी में रहते हैं तो उनका एडवर्स पोजेशन हो जाता है और उसके बाद उनका फिर क्लेम भी बन जाता है। मेरा अनुरोध है कि जैसे ही एन्क्रोचमैंट पाई जाए उसको तुरन्त रिमूव किया जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर किसी सड़क पर कोई एन्क्रोचमैंट हो रही है तो यह वहां के पी0डब्ल्यू0डी0 के अधिकारियों की जिम्मेवारी है। इसके लिए रोड साइड कंट्रोल एक्ट है। उस एक्ट के तहत, पब्लिक प्रीमिसिस एक्ट के तहत या बहुत सारे एक्ट्स के तहत उन्हें तुरन्त संज्ञान लेकर एक्शन लेना चाहिए। माननीय सदस्य अगर बताएंगे कि किस रोड में एन्क्रोचमैंट हुआ है और एक्शन नहीं हुआ है? हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरा, यह एडवर्स पोजेशन सरकार के खिलाफ है तो इसके लिए लगभग 30 वर्षों का समय चाहिए क्योंकि कोर्ट में प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। यह बात ठीक है कि अधिकारियों की नालायकी की वजह से रोड की एंट्रीज नहीं हो रही हैं और माननीय हाई कोर्ट में लगभग 1000 केसिज पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनमें 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कंपन्सेशन मांगा जा रहा है। इसके लिए **कैबिनेट सब-कमेटी ने सभी एक्सिअन को डिवीजनवाइज निर्देश दिए हैं कि वे एक निश्चित समय में अपनी सभी रोड्स की रेवेन्यू एंट्रीज करवाएं अन्यथा उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।**

श्री मलेन्द्र राजन ----आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

25.08.2026/1145/RKS/DC-1

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। इसी विषय पर मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक मुख्य सड़क इंदौरा से डमटाल वाया मोतली है, जिसके संबंध में मैंने विधान सभा प्रश्न भी लगाया था और शून्यकाल में भी यह विषय उठाया है। यह मुख्य सड़क पिछले लगभग दो

माह से बंद पड़ी है जिससे लगभग 10 पंचायतें प्रभावित हो रही हैं। इस विषय में वर्ष 2012 में वहां के कुछ भूमि मालिकों ने उच्च न्यायालय में रिट की थी। अब उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय दिया है और उन्हें भूमि का कब्जा भी दे दिया गया है। इंदौरा को डमटाल से जोड़ने वाली इस मुख्य सड़क को अब उन्होंने मोतली में बंद कर दिया है। यह सड़क गत दो माह से बंद पड़ी है। माननीय राजस्व मंत्री और लोक निर्माण मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस सड़क को पुनः खोलने के लिए कोई विकल्प निकाला जाए। मेरे संज्ञान में यह बात आई है कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद भूमि मालिकों को कब्जा दे दिया गया है। मेरा आग्रह है कि इस विषय की अर्ली हियरिंग करवाई जाए या ऐसा कोई विकल्प निकाला जाए जिससे भूमि मालिकों को मुआवजा देकर उस सड़के को खोल दिया जाए। मेरा यह भी सुझाव है कि वहां से एक दूसरी सड़क भी जाती है अगर उसे प्रोपरली बनवा दिया जाए तो इससे लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने वैसे तो इस विषय पर विस्तृत उत्तर दिया है। इन्होंने बताया है कि ऐसे एक हजार से अधिक मामले उच्च न्यायालय में लंबित हैं। माननीय मंत्री जी दूसरी बात यह है कि हमने जो एक्ट इस विधान सभा में पारित किया था उसे पारित हुए एक वर्ष से अधिक का समय हो गया है लेकिन उस पर अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उस एक्ट को पुनः विधान सभा में लाएगी because as per the reference of the Supreme Court there is no need of any assent; either of the Governor or of the President. माननीय मंत्री जी।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी भी चाह रहे हैं कि जो एक्ट लगभग एक वर्ष से स्वीकृति के लिए लंबित है, यदि उसकी शीघ्र स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तो उसे पुनः सदन में लाया जाएगा। माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, हमने ऐसी बातों को एड्रेस करने के लिए यह बिल लाया था लेकिन केंद्र सरकार इस विषय

25.08.2026/1145/RKS/DC-2

पर निर्णय नहीं ले रही है जिससे प्रदेश को नुकसान हो रहा है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद स्थिति और अधिक विवादास्पद हो गई है। पहले तो हाई कोर्ट का यह फैसला था कि तीन महीने के भीतर गवर्नर या प्रेजिडेंट की स्वीकृति हो जानी चाहिए। लेकिन अब यह मसला और भी विवाद में डाल दिया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान भाजपा सरकार जनहित के कानूनों को लागू ही नहीं करना चाहती है।

अध्यक्ष : प्रश्न संख्या : 4419. माननीय सदस्य श्री पूर्ण चन्द ठाकुर।

श्री पूर्ण चन्द ठाकुर : उपस्थित नहीं।

25.08.2026/1145/RKS/DC-3

प्रश्न संख्या : 4420

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने नालागढ़ में विद्युत बोर्ड के एस0सी0 कार्यालय को खोलने की घोषणा की थी। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यालय है। हमारी दोनों विधान सभा क्षेत्रों के मध्य एक स्थान हैं जहां आर0टी0ओ0 का कार्यालय भी स्थापित है। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी घोषणा के अनुसार वहां इस कार्यालय को कब तक खोल दिया जाएगा? मेरा आग्रह है कि इस कार्यालय को दोनों विधान सभा क्षेत्रों के मध्य ही खोला जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह एक अच्छा सुझाव है लेकिन उस क्षेत्र में विद्युत मीटरिंग बहुत अधिक है। सोलन के आस-पास बिजली की बहुत ज्यादा खपत है। मैं कहना चाहूंगा कि **दोनों माननीय विधायक जहां भी आपसी सहमति बना लेंगे, वहां इस कार्यालय को स्थापित कर दिया जाएगा।** सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राम कुमार : मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस कार्यालय को कितने माह के भीतर फंक्शनल कर दिया जाएगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, **हम इस कार्यालय को समय के अनुसार खोल देंगे।**

प्रश्न संख्या : 4421

श्री दलीप ठाकुर : उपस्थित नहीं।

अगला प्रश्न श्री बी0एस0द्वारा जारी

25.08.2026/1150/बी.एस./ एच.के.-1

प्रश्न संख्याः 4422

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब तो बड़े विस्तार से आया है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि चाहे हमारा टाण्डा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे मण्डी का नेरचौक मेडिकल कॉलेज हो, चाहे चम्बा का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारा शिमला का आई0जी0एम0सी0 हो या चमियाणा हो। मेरा प्रश्न उपकरणों के बारे में था कि जो नई मशीनरी आई है उनमें कौन-कौन सी नई मशीनरी और नए उपकरण खरीदे गए हैं? और सभी मेडिकल कॉलेजों में कितने समय से कितनी पुरानी मशीनरी थी? क्या उन पुरानी मशीनों की लाइफ पूरी हो चुकी थी और किन-किन स्थानों पर यह नई मशीनरी खरीदी गई है?

दूसरा, रोबोटिक सर्जरी के संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन सी ऐसी मशीनें खरीदी गई हैं जो हिमाचल प्रदेश में पहली बार लगाई गई हैं। चाहे वह टाण्डा हो या चमियाणा हो। इसके बारे में मैं मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजिज हैं और मुख्य मंत्री महोदय ने अन्य आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में भी उपकरण लिए हैं उनमें ऐसी कितनी धनराशि इन मशीनों पर खर्च की गई है। पहली बार कौन-कौन से नए उपकरण खरीदे गए हैं? और इसके साथ-साथ आने वाले समय में चाहे वह टाण्डा हो, चाहे हमारा चमियाणा हो चाहे और चम्बा का मेडिकल कॉलेज हो उनके बारे में भी मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीन-चार महत्वपूर्ण बातें पूछी हैं। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज में कितनी पुरानी मशीनें थीं? इसके बारे में बताना चाहूंगा। हमारा शिमला का ही प्रीमियम इंस्टिट्यूट, आई0जी0एम0सी0 है वहां 19 वर्ष पुरानी एम0आर0आई0 थी और उसको हमारी सरकार ने बदला है।

उसी तरह एम0आर0आई0 थ्री टेस्ला भी हमने चमियाणा में आई0जी0एम0सी0 में नेरचौक में टाण्डा में मण्डी में और हमीरपुर में खरीदी है। ये सब भारत सरकार की केंद्रीय कंपनी एच0एल0एल0 के द्वारा खरीदी गई हैं। पहले पूरे मेडिकल कॉलेजों और जोनल हॉस्पिटल में मशीनरी की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया गया और न ही कभी डॉक्टरों ने हमारे ध्यान में यह बात लाई जबकि टेक्नोलॉजी का मेडिकल हेल्थ में बहुत ज्यादा

25.08.2026/1150/बी.एस./ एच.के.-2

योगदान हो गया है।पहली बार हिमाचल प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की गई है और रोबोटिक सर्जरी की जो गाइडलाइन्स थीं उनको एम्स की गाइडलाइन्स के अनुसार अपनाया गया है। एम्स में रोबोटिक सर्जरी हमसे एक करोड़ रुपये महंगी है और उससे अच्छी क्वालिटी क्वालिटी की मशीनें हैं। हमने रोबोटिक सर्जरी की सुविधा चमियाणा में आई0जी0एम0सी0 में हमीरपुर में टाण्डा में और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में शुरू कर दी है।

खुशी इस बात की है कि पिछले दिनों मैं नेरचौक में भी देख रहा था। उन्होंने भी इसकी बहुत खुशी मनाई कि हमने 100 के करीब ऑपरेशन कर दिए हैं। अभी वहां गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन किए जा रहे हैं लेकिन आई0जी0एम0सी0 में पेडियाट्रिक का जो ऑपरेशन हुआ है वह रोबोटिक सर्जरी से हुआ है। यह एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन लैप्रोस्कॉपी से भी हो सकते हैं और एक रोबोटिक सर्जरी का खर्चा सरकार को करने के लिए लगभग 1,40,000 रुपये आता है। माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर जी बोल रहे हैं कि 1,40,000 रुपये हो गए हैं और उसमें एक रोबोटिक सर्जरी करने का खर्चा 1,30,000 रुपये आता है जो सरकार की तरफ से खर्च होता है। यानी कि एक रोबोटिक सर्जरी के बाद उसके सारे इंस्ट्रुमेंट चेंज करने पड़ते हैं और नया जो 1.30,000

रुपये के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वे भी लगाने पड़ते हैं। इसलिए हम आम आदमी से 30 हजार रुपये में रोबोटिक सर्जरी करवा रहे हैं और एक लाख रुपये की सब्सिडी हम दे रहे हैं।

दूसरा जो स्पेशल वार्ड लेता है उसके बारे में मैंने अभी भी बताया है कि हम चमियाणा में केवल 80 हजार रुपये ले रहे हैं और बाकी जगह हम 50 हजार रुपये ले रहे हैं। चमियाणा में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है ताकि एक हॉस्पिटल बेस्ट हो जाए। इसी तरह अभी हम जो

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

25.08.2026/1155/DT/HK-1

प्रश्न संख्या 4422 जारी....मुख्य मंत्री जारी..

क्रस्ना लैब है या लालपैथ लैब है उसके लिए हमने ऑटोमेशंस लैब के लिए टेंडर कर दिया है और उसके लिए प्रदेश सरकार ने एक सौ पच्चीस करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा भारत सरकार से जाइका के थ्रू तीन हजार करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट भी अप्रूव करवाया है। लेकिन इसकी फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती हैं। इनके साथ जो हमारे ई0ए0पी0 के प्रोजैक्ट हैं उनमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन हमारा मानना है कि हेल्थ सैक्टर में हम बहुत तेजी से इस पर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में बेस्ट डायग्नॉस्टिक सिस्टम नॉर्थ इंडिया में हिमाचल प्रदेश में ही हमें मिलेगा। मैं इस सदन में यह भी कहना चाहता हूं कि रोबोटिक सर्जरी की सुविधा अभी हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं है लेकिन हिमाचल प्रदेश नॉर्थ इंडिया का पहला प्रदेश है जहां सारे मेडिकल कॉलेजों में हमने रोबोटिक सर्जरी उपलब्ध करवा दी है। टांडा में दस साल पुरानी एक्स-रे मशीनें हैं और जनरल हॉस्पिटल में उससे अच्छी मशीनें नहीं हैं। लेकिन अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के लिए हम सीटी स्कैन की लेटेस्ट मशीनें ले रहे हैं। अभी हम 64-स्लाइस सीटी स्कैन मशीन ले रहे हैं जबकि मेडिकल कॉलेजों में 128-स्लाइस सीटी स्कैन के अलावा सभी मेडिकल कॉलेजों में हम 256-स्लाइस सीटी स्कैन मशीन भी लेने जा रहे हैं। हस्पतालों में में मरीजों की जो वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि छह महीने की वेटिंग पेंडिंग है और पेट स्कैन की वेटिंग है। अब हमारे यहां वेटिंग की जो लिस्ट है वह 30 दिन की रह गई

है। मैंने जीरो वेटिंग की तरफ काम करना शुरू किया है और इस दिशा में भी हम जल्दी आगे बढ़ेंगे।

प्रश्न संख्या : 4423 श्री जीत राम कटवाल अनुपस्थित।

25.08.2026/1155/DT/HK-2

प्रश्न संख्या 4424

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का बहुत धन्यवादी हूं कि सरकार ने यह एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिससे लोगों की भूमि की निशानदेही अब रूटीन में हो रही हे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो पार्टिशन और निशानदेही के बहुत ही डिसप्यूटेड और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं , क्या सरकार इस पर विचार कर रही है की उनका निपटारा करने के लिए कोई विशेष कमेटी बनाने का प्रावधान क्या जाए?

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लंबे समय से पेंडिंग मामलों को ध्यान में रखते हुए एच0पी0 लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो संशोधन किया गया है उसमें पहली मर्तबा हमने टाइम लाइन फिक्स की हुई है। जैसे डिमार्केशन है वह तीन महीने में होगी और पार्टिशन नौ महीने में होगा। अगर उससे ज्यादा समय कोई अधिकारी लेते हैं तो उनको रीजन लिखना पड़ेगा कि किस कारण से वे तीन महीने का अतिरिक्त समय ले रहे हैं। उसके बाद भी अगर वे अपने केसिज को निपटाने में सफल नहीं होते हैं तो उनके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन करने का भी प्रावधान रखा हुआ है। हमने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को यह कहा है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो संशोधन हुआ है उसको सख्ती से जारी किया जाए ताकि चाहे पार्टिशन हो या डिमार्केशन हो या चाहे फिर राजस्व रिकार्ड में करेक्शन हो, या किसी भी किस्म के अन्य रेवेन्यू केसिज हों उनका एक समय-सीमा के अंदर ही निपटारा हो और लोगों को न्याय मिले।

प्रश्न संख्या 4425 —श्री सुधीर शर्मा, अनुपस्थित।

25.08.2026/1155/DT/HK-3

प्रश्न संख्या 4426

श्री हरदीप सिंह बावा : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012 से 2017 में जब प्रदेश में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी उस समय हमने नालागढ़ रूरल एरिया से संबंधित फेज़-1, फेज़-II और फेज़-III के अंतर्गत ग्राम पंचायत किरपालपुर, गागूवाल और नडयाली को नगर परिषद में शामिल करने के लिए एरिया एक्सटेंशन की फाइल चलाई थी। मुझे जो जवाब उपलब्ध हुआ है उसमें सरकार ने लिखा है कि नगर परिषद नालागढ़ में नए क्षेत्रों को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान सरकार में विचाराधीन नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह फाइल हमने तैयार की थी और इसकी ऊपर जो भी औपचारिकताएं होनी थी वह सभी पूरी कर दी गई थी। परंतु वर्ष 2017 से 2022 की सरकार के समय इसे पुट डाउन कर दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से भी और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि नालागढ़ का एरिया एक्सटेंशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। लगभग 100 से 150 नई कॉलोनीज नालागढ़ के इर्द-गिर्द बन गई हैं।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

25.08.2026/1200/वाई.के.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या-4426............जारी श्री हरदीप सिंह बावा.......... जारी

और वह पीड़स्तान तक हमारा ऐरिया फैल गया है। वहां के लोग टैक्स देने के लिए भी तैयार हैं। अगर यह ऐरिया नगर परिषद में आ जाता है तो मैं समझता हूं कि नगर परिषद को काफी राजस्व प्राप्त होगा। इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री ने वहां के लिए एक

घोषणा भी की है कि रडयाली पंचायत के हाउसिंग बोर्ड ऐरिया को नगर परिषद में शामिल किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि इस घोषणा को भी पूरा किया जाए।

(विपक्ष के अधिकतर माननीय सदस्य सदन में वापिस आए।)

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने म्युनिसिपल काउंसिल नालागढ़ के संबंध में विषय रखा है। जैसा उन्होंने अभी खुद कहा है कि इस संदर्भ में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और वर्ष 2009 में तत्कालीन विधायक नालागढ़ ने जिला प्रशासन सोलन के माध्यम से नगर परिषद नालागढ़ के जो आठ क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को नगर परिषद में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था, मगर अभी तक उसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। कुल मिलाकर हम इनके साथ एग्री करते हैं, क्योंकि नालागढ़ एक बड़े शहर में तब्दील हो रहा है। उस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया भी है। जिस कारण वहां पर इंडस्ट्रीज़ भी हैं और हाउसिंग कॉलोनियां भी बढ़ रही हैं। **यह प्रस्तावित है कि इसको हम आने वाले समय में विचार करेंगे।** इसमें जो सबसे ज्यादा विरोध होता है, वह उन्हीं पंचायतों का होता है, जिनका इसमें मर्जर होना है। Due process has to be followed. The recommendations has to be brought from the Municipal Council, further to the Deputy Commissioner and from the Deputy Commissioner further to the Directorate तो जैसे ही यह प्रस्ताव आने वाले समय में आएगा, तो **निश्चित तौर से माननीय मुख्य मंत्री और सरकार तथा संबंधित विभाग इसको पॉजिटिवली आने वाले समय में देखेंगे।** सवाल यह है कि वहां की पंचायतों को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी

25.08.2026/1200/वाई.के.-एन.जी./2

चाहिए। मेरा माननीय विधायक जी से निवेदन रहेगा कि वे सकारात्मक रूप से जिन पंचायतों का इसमें मर्जर होना है, उनके साथ ड्यू डिलिजेंस और डायलॉग करें। धन्यवाद।

प्रश्न काल समाप्त।

अध्यक्ष : मेरे पास प्रतिपक्ष के बहुत सारे माननीय सदस्यों से मांग आई है कि दिनांक 21 अगस्त, 2026 की कार्यवाही की वीडियो क्लिप उपलब्ध करवाई जाए। मैं इनकी मांग को एग्ज़ामिन कर रहा था और मैंने इस मांग को मंजूर कर दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि दिनांक 21 अगस्त, 2026 की कार्यवाही की वीडियो क्लिप्स की जो-जो भी मांग करता है उन्हें उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री), क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्न काल के दौरान जो भी हुआ है, वह निंदनीय है। हम कह रहे थे कि विपक्ष सदन से भगाना चाहता है और सदन की कार्यवाही को नहीं चलाना चाहता, यह आज साबित हो गया है। सभी माननीय सदस्यों के जो क्वेश्चन हैं, वे इंपोर्टेंट होते हैं। आप समय-समय पर अपनी बात रखने का पूरा समय देते हैं और आप सप्लीमेंट्री का भी पूरा समय देते हैं। एक क्वेश्चन पर आधा घंटा हो जाए ...(व्यवधान)

Speaker : Let him complete, thereafter, I will allow you.

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन पर आधा घंटा हो जाए, यह कहां तक जायज़ है? आपने विपक्ष के सभी माननीय विधायकों को मौका दिया और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सदन में जो और सदस्य बैठे हैं, उनके क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट होंगे? Only your questions are not important. अध्यक्ष महोदय ने आपको उचित समय दिया।

25.08.2026/1200/वाई.के.-एन.जी./3

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का व्यवहार भाजपा के सीनियर विधायक कर रहे हैं, वह निंदनीय है। यहां पर भाजपा के सीनियर विधायक बैठे हैं। श्री बिक्रम सिंह जी भी वरिष्ठ सदस्य हैं और ये मंत्री भी रहे हैं तथा चार बार के विधायक हैं।...(व्यवधान)

Speaker : No interruption please. श्री बिक्रम सिंह जी, मैं आपको समय दूंगा, आप तब बोल लेना। ...(व्यवधान) No interruption please. ...(Interruption) मैं आपको समय दूंगा, अभी आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान) Thereafter, you can explain yourself. आप ऐसे खड़े मत हो जाया करो। You cannot gag others mouth. He has also right to speak.

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अगर पहली बार का विधायक ऐसा व्यवहार करे तो माना जा सकता है। लेकिन जो काफी समय से इस माननीय सदन के सदस्य रहें हैं, माननीय मंत्री रहे हैं, वे ऐसा व्यवहार करेंगे तो निंदनीय है। हम जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, हम अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम एक आदर्श होते हैं। आप भी आदर्श हैं और श्री जय राम ठाकुर भी आदर्श हैं। आज इस माननीय सदन को देखने के लिए विभिन्न स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं और ये बच्चे क्या मैसेज लेकर जाएंगे? अध्यक्ष महोदय, जब पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू हुई...(व्यवधान)

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

25.08.2026/1205/YK/PB/1

अध्यक्ष जारी...

...(व्यवधान) आप (विपक्ष) सत्र के पहले दिन की बात को रहने दीजिए। ...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि...(व्यवधान)

Speaker : This House has taken a note whatever you have said. We have taken a note of it.

Parliamentary Affairs Minister : In proceedings, it should not happen in the House. हम सभी से अनुरोध करते है कि सदन सुचारू रूप से चलने दीजिए। मुख्य मंत्री जी ने दस दिन का मानसून सत्र रखा है और यह सत्र पूरी तरह चलना चाहिए। आप सभी सदन के अंदर अपनी जो भी बात रखना चाहते हैं सरकार उनका जवाब देने को तैयार है। ...(व्यवधान) सदन के अंदर तर्क-वितर्क होना चाहिए।...(व्यवधान)

25.08.2026/1205/YK/PB/2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह, क्या आप कुछ कहना चाहते है? ...(व्यवधान) माननीय सदस्यगण, कृपया बीच में न बोला करें। ...(व्यवधान) जहां मुझे लगेगा। I will allow everybody.

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में अगर कोई कनिष्ठ या वरिष्ठ सदस्य आपके आगे निवेदन करता है कि मुझे सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए तो यह उसके व्यवहार के ऊपर नहीं जाना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री हमारे वरिष्ठतम् सदस्य है और मेरे मित्र है। मैं इनके खिलाफ बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि मुख्य मंत्री जी पहले ही कहते है कि उद्योग मंत्री और मैं मिले हुए है। लेकिन आप भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है और न ही किसी के बारे में ऐसी बात कही है। मैं तो केवल अनुरोध कर रहा था कि आप मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बीच में उठ गए थे इसलिए मंत्री महोदय ने आपको यह कहा है।

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, बीच में उठना और सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछना मेरा धर्म है।

अध्यक्ष : जब मैं इजाजत दूंगा तभी उठना आपका धर्म है।

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात पूछना चाहता था आपने मुझे वह पूछने की अनुमति नहीं दी। मुख्य मंत्री जी कहते है कि बिक्रम जी, आपकी तरफ के लोग हर समय यही बोलते रहते हैं कि मुख्य मंत्री जी झूठ बोलते है, लेकिन सच्चाई यही है। मुख्य मंत्री जी कई बार ऐसी बात करते है। इन्होंने कहा है कि मैं व्यवस्था परिवर्तन के तहत यह कर रहा हूं, सबऑर्डिनेट सर्विसिज के माध्यम से यह हो रहा है और मैंने इंटरव्यू लेना बंद कर दिया है। यह अच्छी बात है लेकिन आप जनता-जनार्दन को यह भी बताएं कि आउटसोर्स पर जो लोग और पदाधिकारी रखे हुए हैं तथा जिनको ड्यूटियां लगाई हैं कि सौ नर्सें तुम्हें भरनी हैं और दो सौ तुम्हें भरनी हैं, क्या आप इसकी जांच करवाएंगे? मैंने क्या गलत कहा है? इसलिए संसदीय मंत्री जी जो कह रहे है, वह बिल्कुल गलत हैं। हम आपका सम्मान करते है। यह हमारी आदत है कि हम रिएक्शनरी बोलने लगते है। बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं, धन्यवाद। ...(व्यवधान)

25.08.2026/1205/YK/PB/3

अध्यक्ष : मेरा सभी से आग्रह है ...(व्यवधान) एक मिनट ...(व्यवधान) मेरा सभी से आग्रह है...(व्यवधान) मुझे तो बोलने दीजिए...(व्यवधान) Pay attention to me. ऐसा है I am here to watch your interest. I have to watch everybody's interest, all Hon'ble MLAs' interests is to be watched by me as a custodian of this House. That is my concern only. एक प्रश्न पर आधा घंटा चर्चा हुई। ...(व्यवधान) Mr. Rakesh Jamwalji, you have no faith on me. Again, when the Speaker is speaking, everybody is supposed to listen. Still you are speaking in between, that is a bad habit. You must correct yourself. We have been a Member of this House for many years. I have been the members of this House from 1985 onwards and many times remained in Opposition and Ruling side. But I am noticing for the first time this. Everybody starts speaking. If somebody is speaking, the other one will just stand and will try to gag his mouth. Can you do that? Whatever issue you have, I will be giving you time to explain yourself. In any case, if I find there is any reason for that. If there is no reason, certainly I have a right and powers with me not to allow. इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि जब मुझे लगेगा

तब मैं समय दूंगा। मुझे लगा कि प्रश्न की चर्चा में आधा घंटा हो गया है और सभी बातें जवाब के रूप में आ गई हैं तथा अभी नियम-130 में फिर से यही विषय आएगा तो ये सभी मुद्दे वहां भी उठाए जा सकते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा स्पष्ट प्रश्न पूछने के बाद और माननीय सदस्य श्री जीतराम कटवाल द्वारा सारी बातें कहने के बाद मुख्य मंत्री जी ने उनका जवाब दे दिया है। अब फंक्शन पोस्ट इत्यादि पर आप नियम-130 में चर्चा कर सकते है। हमारे समय में अध्यक्ष एक सप्लीमेंटरी के बाद दूसरे सप्लीमेंटरी प्रश्न की अनुमति नहीं देते थे। फिर हम नियम-61 के अंतर्गत आधे घंटे की चर्चा में अपना विषय रखते थे। You should resort to that method. अब हमने एक ही प्रश्न नहीं लेना है बल्कि एक घंटे में 68 माननीय विधायक हैं and the Government is liable for every MLA, it is not for the Opposition only. So, every MLA has a right to ask the question, that

25.08.2026/1205/YK/PB/4

was my concern only. हमने प्रश्न ले लिए। आपने (विपक्ष) अपने प्रश्न छोड़ दिये।...(व्यवधान) फिर इसमें शून्यकाल चला जाएगा...(व्यवधान) शून्यकाल में आपके (विपक्ष) ही सारे मुद्दे हैं...(व्यवधान) और ये सभी मुद्दे रह जाएंगे।...(व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष, कुछ कहना चाहते है।

श्री जय राम ठाकुर श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

25.08.2026/1210/ए0जी0/ए0पी0-01

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले कल भी कह रहा था कि आजकल श्री हर्षवर्धन जी ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। हम आपके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं लेकिन हम व्यवस्था से संबंधित जरूर कहना चाहते हैं। अगर प्रश्न का उत्तर स्पेसिफिक मिले, संक्षिप्त मिले और जिस रिलेवेंट पोर्शन को हमने पूछा है, उस पर रिलेवेंट जवाब आ जाए तो दिक्कत कहां आएगी। यहां जो प्रश्न पूछा गया वह पोस्टपोन क्वेश्चन था। माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी ने

पूछा था तो उस प्रश्न में 20 मिनट का भाषण हो गया। 15 मिनट का भाषण एक बार दिया गया। मैंने जो आज प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का अभी तक उत्तर नहीं आया है और यह सच्चाई बता रहा हूं। मैं सच बोल रहा हूं कि अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, लेकिन मुख्य मंत्री जी का भाषण में देंखे तो वे बातों को लेकर कहां-से-कहां पहुंच जाते हैं। आप नादौन से सिरमौर तक पहुंच जाते हैं। मेरा मतलब है कि आप भटक जाते हैं। मेरा कहना का अभिप्राय यह है कि मिनिस्टर्स को जिम्मेवारी के साथ जवाब देना चाहिए लेकिन जब संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो उस समय प्रश्न पैदा होता है। हमारे माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी सीनियर मेंबर हैं। हम इनको बहुत सम्मान देते हैं। इनके मन में जो प्रश्न मुख्य मंत्री जी के जवाब के बाद खड़े हुई, जिसे हम कह सकते है कि इनके मन में उस प्रश्न के जवाब को लेकर आशंकाएं पैदा हूई। उनका निवारण करना भी बहुत जरूरी है। आपने विपक्ष के सदस्यों को तो कह दिया कि सबको मौका देना चाहिए, थोड़ा पूछना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष को भी बोला जाए कि जवाब सही दिया करें। उन्हें कहा जाए कि भाषण मत दीजिए, जवाब दीजिए। बस यह अगर होगा तो मुझे लगता है, सब ठीक हो जाएगा।

25.08.2026/1210/ए0जी0/ए0पी0-02

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बड़ी विचित्र बात है। सवाल माननीय सदस्य श्री कटवाल जी ने पूछा, सप्लीमेंटरी उसके बाद पूछा गया और मुझे बोलतें है कि आपने जवाब के लिए आधे घंटा का समय लिया। मैं आपको बता दूं कि आठ मिनट का तो अपने क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद मैंने रिप्लाई दिया और मैं दूसरी बात व्यवहार की करना चाहता हूं। जिस प्रकार का व्यवहार अपनाया जा रहा है कि नहीं, हमने बोलना ही है। अध्यक्ष से बात की जाती है कि हमें बोलने का मौका दीजिए। इस तरह का व्यवहार नहीं चलेगा। विधान सभा रूल के हिसाब से चलेगी, व्यवस्था के हिसाब से चलेगी। अगर आपने मन बना ही लिया है कि हमने इस तरह का व्यवहार रखना है और हमने लड़ना है तो कोई पक्ष कम नहीं है। कानूनों के अनुसार, संविधान के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई करनी पड़ती है। आप बार-बार बोल रहे हैं कि मैंने आठ मिनट बोला और आप बोल रहे हैं कि हम जवाब नहीं दे रहे।

मैंने पूरा जवाब दिया है। मैंने पुलिस भर्ती के बारे में बोला की अभी है और उसके बाद मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। ऐसा की अगर आप नहीं बोलने देंगे तो मैं बोलता रहूंगा। क्वेश्चन आवर स्टार्ट हो गया, आप क्या कर सकते हो, यह हमारा अधिकार है। माननीय श्री सतपाल सिंह सत्ती जी से भी मैं इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं चाहता हूं, जिस तरह से वे जोर-जोर से टेबल बजा रहे थें। यह व्यवहार की बात है, सवाल की बात नहीं है। हम सब चुनकर आए हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो पहली बार चुनकर नहीं आया, उसको भी एक लाख जनता ने चुनकर भेजा है। मैं यह कहूंगा कि आपकी व्यवस्था में हम सब लोगों को सहयोग करना है। आप किसी कानून के अनुसार कोई आपकी बात नहीं मानता और धमकाने की बात करता है तो उसके लिए रूल बने हैं। आप रूल के अनुसार हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं। रूल पर एक्शन लेना भी चाहिए। मेरा कहना है कि अगर रूल के अनुसार देखा जाए तो कई बार व्यवधान डाला गया है। मैं चाहूंगा कि आप वरिष्ठ नेता हैं आगे से इस बात का भी ख्याल रखें। यही मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

25.08.2026/1210/ए0जी0/ए0पी0-03

अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री जी।

राजस्व मंत्री : स्पीकर साहब, धन्यवाद। आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया है। आजकल एक सुखद घटना यह है कि नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि सरकार संविधान से चलती है। मानते नहीं थे, पर आजकल मान रहे हैं।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

25.08.2026/1215/AT/AG/01

राजस्व मंत्री जारी....

दूसरी बात यह है कि महात्मा गांधी जी के सामने जाकर अकल मांग रहे हैं, यह भी बड़ी अच्छी बात हुई। तीसरी बात यह है कि जब संविधान से हमारा देश चलता है, हमारी विधान सभा भी जो रूल्स और नियम बनाए हुए हैं, उसी से चलती है। अब इसको भी मानना है। इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है अगर इस रूल्स और नियम को ये नहीं मानेंगे, जिस तरह से वे व्यवहार करते हैं, तो यह सदन कैसे चलेगा? और इसमें जो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन पूछना रूल 57 में पूरा दिया हुआ है, **Supplementary questions.** The member in whose name a question is listed for oral answer or any other member, when called by the Speaker आपके पास पावर है, सर। आप जिसको चाहे दे सकते हैं, नहीं दे सकते। और दूसरी बात मानें, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि क्वेश्चन का रिप्लाई इनके मर्जी के आने चाहिए। यह कहाँ लिखा हुआ है? ये तो सैटिस्फाई कभी नहीं होंगे। ये देखना आसन का काम है कि इस क्वेश्चन का मंत्री ने जवाब सही दिया या नहीं दिया है। इसलिए आप आसन पर हैं कि हम दोनों पक्षों के बीच में आपने फैसला करना है और आप हमेशा करते आ रहे हैं। पर ये इस बात को मानते ही नहीं हैं यह कहते हैं कि मेरी मर्जी का उत्तर आना चाहिए। ऐसा कहाँ हो सकता है?....(व्यवधान) may ask a supplementary question for the purpose of further elucidating any matter of fact regarding which an answer has been given पैरा सेकंड में कहते हैं, A supplementary question shall be disallowed by the Speaker, if in his opinion आपके ओपिनियन में आ गया। नेता प्रतिपक्ष ने आठ मिनट का समय उस प्रश्न के लिये लिया। अब जब नेता प्रतिपक्ष ने सारा टाइम ले लिया, तो सप्लिमेंटरी आपके ओपिनियन में ठीक था कि अब आना कहाँ से? क्योंकि आठ मिनट का क्वेश्चन पूछना, वह भी अपने आप में गलत है। दूसरों के क्वेश्चन का समय ले रहे हैं। आपको तो सबका सम्मान करना है। नेता प्रतिपक्ष की उतनी-सी जिम्मेदारी है कि सभी

25.08.2026/1215/AT/AG/02

को मौका मिले। ये किसी को मौका ही नहीं देते। ये इनको भी नहीं देते। बेचारे जो यहां बैठे हैं, इनको भी क्वेश्चन लगाकर उम्मीद थी कि कुछ करें पर नेता प्रतिपक्ष सारा क्वेश्चन भी खराब कर गए, सप्लिमेंटरी भी खराब कर गए।

मेरा इनसे इतना कहना है कि जब देश संविधान से चलता है, हमारी विधान सभा भी विधान सभा के रूल्स से चलती है। और जब ये इस रूल को बदलना चाहते हैं, जिसमें लिखा जाए कि बार-बार ये प्रस्ताव लाएं हैं, उत्तर इस किस्म का आना चाहिए कि मैं बार-बार खड़ा होऊंगा, नेता प्रतिपक्ष को कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, मैं बेलगाम हो जाऊं, तो ऐसा रूल बना दीजिए ना। धन्यवाद।

25.08.2026/1215/AT/AG/3

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री महोदय स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय,मन में मैं इस मानसून सत्र के पहले कि सदन के माध्यम से एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं-हमारी सरकार में न तो गरीब की मजबूरी का सौदा होने दिया जाएगा, न सरकारी मुआवजे की बंदरबांट होने दी जाएगी और न ही प्रभावशाली लोगों को कानून से ऊपर समझने की इजाजत दी जाएगी। पिछले सत्र में श्री राकेश कालिया द्वारा गगल एयरपोर्ट हेतु भूमि अधिग्रहण/खरीद तथा प्रभावित व्यक्तियों को दिए गए मुआवजे का विषय इस सदन में उठाया गया था। चर्चा के दौरान यह गंभीर आरोप सामने आया कि गग्गल एयरपोर्ट के लिए प्रस्तावित भूमि के आसपास एवं गगरेट में कुछ व्यक्तियों द्वारा गरीब एवं साधारण लोगों से जमीन अपेक्षाकृत कम दरों पर खरीदकर, बाद में उसके अधिग्रहण के माध्यम से अधिक मुआवजा प्राप्त करने का प्रयास किया गया। साथ ही यह बात भी उठाई गई कि इन भूमि सौदों में हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों का विधिवत पालन हुआ अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने उसी समय इस सदन में स्पष्ट कहा था कि यदि किसी ने नियमों को दरकिनार कर भूमि खरीदी है, यदि किसी सौदे के पीछे बेनामी स्वामित्व छिपा है, यदि गरीब व्यक्ति से सस्ती जमीन लेकर सरकारी अधिग्रहण के माध्यम से अनुचित लाभ कमाने की कोशिश हुई है, तो चाहे उसके पीछे कोई भी व्यक्ति क्यों न हो-कानून अपना काम करेगा। मैंने सदन को केवल आश्वासन नहीं दिया था; मैंने SIT गठित कर मामले की तह तक जाने का वचन दिया था। और हमारी सरकार की कार्यशैली का अंतर

देखिए घोषणा 17 फरवरी को हुई और अगले ही दिन, 18 फरवरी 2026 को पुलिस महानिदेशक, ने आदेश जारी कर DIG धर्मशाला की अध्यक्षता में चार सदस्यीय Special Investigation Team (SIT) गठित की गई। अब तक SIT द्वारा 09 अलग-अलग Status Reports प्रस्तुत की जा चुकी हैं। इन रिपोर्टों में गगल एयरपोर्ट के आसपास हुए भूमि सौदों, संदिग्ध बेनामी स्वामित्व और संबंधित बैंक लेन-देन की जांच की गई है। 4 मामलों में SIT द्वारा SV&ACB में आपराधिक मामले दर्ज किए गए है। तथा SIT द्वारा रिपोर्टों में उल्लिखित भूमि खरीद मामलों को धारा 118 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित जिला कलेक्टरों को भेजी जा चुकी है।

25.08.2026/1215/AT/AG/04

अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं सरकार की नीयत भाषणों से नहीं, फैसलों से परखी जाती है। सवाल सदन में उठा तो हमने उसे दबाया नहीं। आरोप लगे तो हमने फाइल बंद नहीं की। जांच की मांग हुई तो हमने समय नहीं काटा। यही हमारी सरकार और केवल आरोपों की राजनीति करने वालों के बीच का फर्क है-वे सवाल उठाकर राजनीति करते हैं, हम सवाल की तह तक जाकर कार्रवाई करते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि न कोई कितना प्रभावशाली है, यह देखा जाएगा, न सकी राजनीतिक पहचान देखी जाएगी न उसका पद और पहुंच देखी जाएगी। केवल तथ्य, साक्ष्य और कानून देखा जाएगा। मेरी सरकार गरीब की जमीन की भी रक्षा करेगी, सरकारी धन की भी रक्षा करेगी और हिमाचल के हितों की भी रक्षा करेगी।

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी ......

25.08.2026/1220/av/as/1

शून्य काल

अध्यक्ष : जीरो आवर के अंतर्गत मेरे पास कुल 8 मुद्दे हैं जबकि अब केवल 10.00 मिनट्स का समय शेष रहता है। जिन माननीय सदस्यों का पिछले तीन दिनों के अंदर कोई विषय नहीं लगा आज मैं उनको अपना विषय रखने हेतु प्राथमिकता दे रहा हूं।

माननीय सदस्य श्री डी0एस0 ठाकुर, raise your issue under Zero Hour. आपने अपना विषय दिया है न?

श्री डी0एस0 ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि बनीखेत कॉलेज के साथ हमारा भलई कॉलेज है तथा उसके साथ हमारे दो और कॉलेज भी हैं। माननीय शिक्षा मंत्री ने यह कॉलेज बीच में ही बंद कर दिया। मगर जब वहां पर लोगों और बच्चों ने हड़ताल की तो 16 लोगों पर एफ0आई0आर0 दर्ज कर दी गई। उसके पश्चात आनन-फानन में शिक्षा मंत्री जी ने उस कॉलेज को दोबारा नोटिफाई किया। लेकिन तब तक बच्चे दूसरे कॉलेज में चले गए थे। इन्होंने वहां पर कॉलेज तो रीनोटिफाई कर दिया परंतु अब वहां पर न कोई एसिस्टेंट प्रोफैसर है और न ही कोई दूसरा स्टाफ है। यहां पर शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं और मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या हमारे बच्चे, बच्चे नहीं हैं? वे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। वहां पर हमारी बच्चियां दूरदराज के क्षेत्रों से पढ़ने के लिए आती हैं मगर अब उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। वहां पर कॉलेज के लिए टेंडर हुआ तो माननीय शिक्षा मंत्री ने उस टेंडर को ही कैंसिल कर दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमारे डलहौजी निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे चला गया है। अतः शिक्षा मंत्री जी बताएं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया?

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्य श्री डी0एस0 ठाकुर ने अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित डीनोटिफाई हुए कॉलेज के बारे में बात रखी है। यह फैसला मात्र इनके विधान सभा क्षेत्र के लिए नहीं अपितु पूरे प्रदेश के लिए एक नीतिगत फैसला लिया गया था। इस बारे में मुख्य मंत्री जी ने बजट में अनाउंसमैंट भी की थी, उसी के अनुरूप

जहां-जहां पर 75 से कम एनरोलमैंट थी उनको बंद किया गया था। उदाहरण के तौर पर अगर इनके भलई कॉलेज की बात की जाए तो वहां पर मात्र 19 बच्चे थे। मेरे

25.08.2026/1220/av/as/2

विधान सभा क्षेत्र में मात्र 6 बच्चे थे। मैं समझता हूं कि हम उसी दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़े थे। लेकिन इन सभी बातों को लेकर प्रदेश में जो कुल 10 कॉलेजिज डीनोटिफाई हुए थे उनमें से 9 कॉलेजिज फिर से नोटिफाई हो चुके हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र टिक्कर का कॉलेज अभी भी नोटिफाई नहीं हुआ है और उसके पीछे कम एनरोलमैंट ही कारण है। अतीत में चाहे आपकी सरकार रही हो या वर्तमान में हमारी सरकार है या फिर भविष्य में जो भी सरकार बनेगी; मैं समझता हूं कि सभी कॉलेजिज में सौ प्रतिशत स्टाफ देना कठिन है। इसलिए युक्तिकरण समय की आवश्यकता थी और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह कदम उठाया था। माननीय सदस्य ने भलई कॉलेज के बारे में बात रखी थी और पूर्व में रही प्राथमिक शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती आशा कुमारी जी ने भी मेरे संज्ञान में यह बात लाई थी। इसलिए इसको रीनोटिफाई किया गया है। परंतु जहां तक स्टाफ की बात है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें भविष्य में भी कोई ज्यादा अंतर आएगा। इसका कारण आप भी जानते हैं क्योंकि भर्ती में समय लगता है और **वर्तमान में कमीशन को लगभग 390 पोस्ट्स की रिक्विजिशन भेजी गई है। जब इस बारे में प्रक्रिया आरम्भ होगी तो उसके अनुरूप खाली पड़े पद भर दिए जाएंगे।**

25.08.2026/1220/av/as/3

श्री प्रकाश राणा : अध्यक्ष महोदय, हमारे जोगिन्द्रनगर निर्वाचन क्षेत्र में एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। वहां पर आज भी हजारों लोग आंदोलन कर रहे हैं तथा कुछ लोग अनशन पर बैठे हुए हैं।

टी सी द्वारा जारी

25.08.2026/1225/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

श्री प्रकाश राणा..जारी

यह किसी एक पार्टी का जन आंदोलन नहीं है बल्कि पूरा जोगिन्द्रनगर क्षेत्र इसमें साथ होकर आंदोलन कर रहा है। इनका विषय यह है कि आर0सी0एफ0सी0 यानी रिजनल-कम-फैसिलिटेशन सेंटर आयुष मंत्रालय के नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड यानी एन0एम0पी0बी0 का क्षेत्रीय केंद्र है। जोगिन्द्रनगर स्थित यह केंद्र नॉर्दर्न रीजन-वन के लिए है तथा औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती के संबंध में किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, सामग्री, उत्पादन तथा विपणन आदि में सहायता प्रदान करता है। इसमें मुख्य विवाद यह है कि वर्षों से जोगिन्द्रनगर में चल रहे इस केंद्र को अब नौणी सोलन स्थित डॉ0 वाई0एस0 परमार विश्वविद्यालय में शिफ्ट किया जा रहा है। जोगिन्द्रनगर की जनता की आपत्ति यह है कि जब यहां इस केंद्र का ढांचा और वर्षों का अनुभव पहले से मौजूद है तो इसे हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। यह केंद्र जोगिन्द्रनगर में वर्ष 2017 से सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जोगिन्द्रनगर में वर्षों से चल रहे आर0सी0एफ0सी0 को नौणी शिफ्ट करने का निर्णय हमारे क्षेत्र के साथ अन्याय है। यह केंद्र औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देकर किसानों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता रहा है। आज जोगिन्द्रनगर की जनता इसके विरोध में आंदोलन तथा क्रमिक भूख हड़ताल कर रही है। मेरा सरकार से स्पष्ट आग्रह है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए तथा केंद्र सरकार और आयुष मंत्रालय से तत्काल बात करके इस शिफ्टिंग को रोका जाए। यदि जोगिन्द्रनगर में कोई कमी है तो उसे दूर किया जाए और सुविधाएं बढ़ाई जाएं लेकिन एक स्थापित संस्थान को जोगिन्द्रनगर से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह केवल एक कार्यालय का मामला नहीं है बल्कि जोगिन्द्रनगर के किसानों, युवाओं और क्षेत्र के भविष्य का सवाल है। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि आर0सी0एफ0सी0 को जोगिन्द्रनगर में ही यथावत रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य मंत्री से भी निवेदन है कि इस शिफ्टिंग को रोका जाए ताकि जो इश्यू खड़ा हुआ है उसे रोका जा सके। धन्यवाद।

25.08.2026/1225/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

आयुष मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो बात जोगिन्द्रनगर के माननीय सदस्य ने सदन में रखी है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि आर0सी0एफ0सी0 सेंटर, केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रोजैक्ट्स के माध्यम से धनराशि दिल्ली से आयुष मंत्रालय द्वारा आती है। पिछले काफी समय से केंद्र सरकार इसके लिए धनराशि देने में आनाकानी कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य वहां के लोकल किसानों को आयुष विभाग के जितने भी आयुर्वेदिक पौधे हैं उनको उगाने तथा उनके बीजों से आजीविका कमाने में सहायता करना है जिससे विभाग को भी फायदा होता है और आर0सी0एफ0सी0 सेंटर को भी फायदा होता है। यह काफी समय से वहां चल रहा है और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि काफी समय से चलने के कारण लोग भी इससे जुड़े हुए हैं लेकिन यह प्रोजैक्ट बेस्ड कार्यक्रम है। जैसे ही प्रोजैक्ट आता है वैसे ही लोगों को हायर किया जाता है और इससे ही उनकी सैलरी निकलती है। जब वह प्रोजैक्ट समाप्त होता है तब उन लोगों को बाहर किया जाता है और पुनः प्रोजैक्ट आने पर उन्हें ले लिया जाता है। यह प्रोजैक्ट केंद्र के अधीन है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह प्रोजैक्ट हिमाचल प्रदेश सरकार या हिमाचल प्रदेश आयुष विभाग ने बंद नहीं किया है। इसे केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा बंद करके स्थानांतरित किया गया है। इसलिए इसके संबंध में जो जन भावना है उसके बारे में माननीय सदस्य ने मुझसे पहले भी बात की है। इसके अलावा वहां से जो कांग्रेस पार्टी समर्थित प्रत्याशी रहे हैं उनके सदस्यों ने भी इस विषय पर बात की है और हमने यह मामला केंद्र सरकार से भी उठाया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इसके बारे में कोई-न-कोई पॉजिटिव रिमार्क्स आएंगे। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है। माननीय सदस्य लोकेन्दर कुमार जी, एक मिनट बचा है और आपका बहुत ब्रीफ क्वेश्चन है।

25.08.2026/1225/टी0सी0वी0/ए0एस0-3

जल शक्ति विभाग द्वारा बिना मीटर पानी के बिल आने से संबंधित मामला

श्री लोकेन्दर कुमार : अध्यक्ष महोदय, शून्य काल में बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र आनी में निरमंड पंचायत है। मैंने पिछली बार भी आपके माध्यम से सदन में यह विषय रखा था कि

एन0एस0 द्वारा .. जारी

25-8-2026/1230/NS-DC/1

श्री लोकेन्दर कुमार ------जारी

मेरे विधान सभा क्षेत्र आनी में निरमंड नगर पंचायत बनी है। मैंने पिछली बार भी आपके माध्यम से माननीय सदन में यह बात रखी थी कि निरमंड नगर पंचायत के अंतर्गत जितने भी पानी के कनैक्शन्ज हैं उनके संबंध में आदरणीय उप-मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उस नगर पंचायत में सात वार्ड हैं और उन सात वार्डों में जल शक्ति विभाग द्वारा 1300 रुपये से 1500 रुपये तक पानी के बिल दिए जा रहे हैं जबकि वहां कोई मीटर नहीं लगा है। विभाग किस पैरामीटर के आधार पर लोगों को पानी के बिल दे रहा है? मैंने पिछली बार भी इस माननीय सदन में यह बात उठाई थी। विभाग अपने अंदाजे से वहां पानी के बिल दे रहा है। मैं चाहूंगा कि आप इसमें हस्तक्षेप करें क्योंकि यह नगर पंचायत बनी है और वहां काफी लोग बेरोजगार हैं। वहां सभी लोग नौकरीपेशा नहीं हैं। इसीलिए वहां के आम परिवारों को काफी दिक्कत आ रही है। मैंने पिछली बार भी माननीय सदन में यह बात रखी थी परन्तु उसके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, अभी मैं फिर से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का ब्लॉक निरमंड है। नगर पंचायत निरमंड में इस तरीके से जल शक्ति विभाग व उसके अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। यदि बिल लेना है तो यह स्पष्ट किया जाए कि किस पैरामीटर के हिसाब से बिल लिए जाएंगे? वहां पहले मीटर लगाए जाएं। बिना मीटर लगाए 1300 रुपये से 1500 रुपये पानी का बिल देना ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि आदरणीय उप-मुख्य मंत्री

महोदय इसमें हस्तक्षेप करें और वहां जो पानी के बिल अधिक आ रहे हैं उन्हें रिम्बर्स करें। लोगों को कम-से-कम मात्रा में और जितना पानी यूज़ हो रहा है उसी हिसाब से बिल दिया जाए। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय मेरे ध्यानार्थ लाया है उसकी पड़ताल करवाकर आपको सूचित कर देंगे।

शून्य काल समाप्त

Speaker: Now rest of the issues will be taken up tomorrow. I would request the Vidhan Sabha Secretariat to send the notices to the respective Ministries , portfolios or the Departments so that they are prepared to reply to the issues raised under the Zero hour tomorrow. अब कागजात सभापटल पर रखे जाएंगे।

25-8-2026/1230/NS-DC/2

कागज़ात सभा पटल पर

अब उद्योग मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का 55वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड का 48वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित)।

अध्यक्ष : अब शिक्षा मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 'हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 37(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला स्थित दाड़ी का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

25-8-2026/1230/NS-DC/3

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। अब श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

Shri Anil Sharma: Speake Sir, with your permission, I present and lay a copy of the documents mentioned below on the Table of the House:-

1. समिति का **45वां मूल प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) पर बने समिति के **111वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** पर आधारित तथा **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित है;
2. समिति का **122वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) पर बने समिति के **120वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) में

अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त "**अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण**" पर आधारित तथा **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित है; और

3. समिति का **162वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) पर बने समिति के **95वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त "**अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण**" पर आधारित तथा **बहुउद्देशीय परियोजनाए एवं ऊर्जा विभाग** से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब श्री किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

25-8-2026/1230/NS-DC/4

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, लोक उपक्रम समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(1) समिति का **35वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 36वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का **19वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) पर बने **55वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित "**अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण**" तथा **हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम सीमित** से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब श्री आशीष बुटेल, सभापति, जन प्रशासन समिति, जन प्रशासन समिति, **(वर्ष 2026-27)**, समिति का **18वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **गृह विभाग** से सम्बन्धित

आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री आशीष बुटेलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से **(वर्ष 2026-27),** समिति का **18वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **गृह विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब श्री राम कुमार, सभापति, ग्रामीण नियोजन, ग्रामीण नियोजन समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

(1) समिति का **22वाँ प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

25-8-2026/1230/NS-DC/5

(2) समिति का **23वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्याः 14- मत्स्य विभाग** की वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

आगे अध्यक्ष------ आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

25.08.2026/1235/RKS/DC-1

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होंगे। अब माननीय सदस्य, श्री कुलदीप सिंह राठौरअपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और माननीय बागवानी मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे। श्री कुलदीप सिंह राठौर जी अगर चाहें तो चेयर की अनुमति से

अपना स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। अब मैं श्री कुलदीप सिंह राठौर से आग्रह करूंगा कि वे नियम-62 के अंतर्गत अपना विषय रखें।

श्री कुलदीप सिंह राठौर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रदेश के बागवानों/ किसानों को उपलब्ध करवाए जा रहे फफूंदनाशकों (Fungicides) एवं कीटनाशकों (Insecticides) की गुणवत्ता सुनिश्चित करने बारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना विषय रखिए।

श्री कुलदीप सिंह राठौर : अध्यक्ष महोदय, यह विषय काफी समय से प्रदेश के बागवानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हमें लगातार घटिया तथा प्रभावहीन फंगीसाइड और पेस्टिसाइड की शिकायतें मिल रही हैं। हमारा कृषि और खासकर बागवानी क्षेत्र पहले ही आपदाओं और प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों से जूझ रहा है। लगातार प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों का उत्पादन कम हो रहा है और इस वर्ष तो हमारी उपज लगभग आधी रह गई है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को सेब राज्य के नाम से जाना जाता है। हमारी लगभग पांच हजार करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र पर आधारित है। कोरोना काल के दौरान जब सभी सैक्टर घाटे में जा रहे थे तब केवल यही क्षेत्र ऐसा था जिससे सरकार को लाभ हुआ। अब मौसम की बेरुखी और लगातार बढ़ती लागत के कारण बागवानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उत्पादन घट रहा है, मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ गई है और दवाइयां एवं रासायनिक खादें लगातार महंगी होती जा रही हैं जिससे मुनाफा कम होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त सेब के बागीचों में लगातार apple scab, marssonina blotch, alternaria leaf blotch,

25.08.2026/1235/RKS/DC-2

powdery mildew जैसी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिनका अभी तक विश्लेषण नहीं हो पाया है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है

कि संबंधित विभागों में इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। पिछले दिनों सेब को बेहतर आकार देने और गुणवत्तायुक्त विकसित करने के लिए पी0जी0आर0 (प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर) मार्किट में उपलब्ध करवाया गया। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इसके प्रयोग से कई स्थानों पर भारी नुकसान हुआ। जहां-जहां इसका प्रयोग किया गया, वहां फसलें बर्बाद हो गई और सेब झड़ गए। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि सेब का आकार अच्छा बने, सेब लंबोतरा बने और उसका रंग अच्छा हो लेकिन हुआ इसके विपरीत। यह रसायन लगभग 16,500 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा गया। हालांकि यह किसी विदेशी कम्पनी से भारत में आयात किया गया था लेकिन यह मालूम नहीं है कि यहां इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई या विदेश से ही इस प्रकार का रसायन हमारे प्रदेश में आया।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

25.08.2026/1240/बी.एस./एच.के.-1

श्री कुलदीप सिंह राठौर जारी...

अध्यक्ष महोदय, जब इस तरह का रसायन हमारे प्रदेश में आया और इसका दुष्प्रभाव हुआ तो बहुत शोर मचा तथा इसकी शिकायत विजिलेंस में हुई। अभी विजिलेंस की जांच चल रही है। मुझे मालूम नहीं कि विजिलेंस की जो जांच है वह कितनी आगे बढ़ी है? लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत हमारे बागवानी मंत्री, हमारे कृषि मंत्री तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री के ध्यान में भी यह बात लाना चाहता हूं कि जांच समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मार्सोनीना और वाल्टरनेरिया जैसी बीमारियां हो रही हैं। एक हैरानी का विषय यह भी है कि हमारा डॉ0 वाई0एस0 परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी का जो स्प्रे शेड्यूल है उस पर भी प्रश्नचिह्न लग रहे हैं। अभी पिछले दिनों डॉ0 विजय सिंह ठाकुर जो पूर्व में उस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं उन्होंने प्रश्नचिह्न लगाया कि पौध संरक्षण व्यवस्था में जो विदेशों में प्रतिबंधित दवाइयां हैं वे स्प्रे शेड्यूल में शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है। जो दवाइयां विदेशों में प्रतिबंधित हैं उनका यहां कैसे आयात हो रहा है? हमारे जो बागवान हैं हमारे जो फल उत्पादक संघ हैं हमारे तमाम जो शिमला क्षेत्र के विधायक हैं या जहां-जहां से सेब पैदा होता है। वे इस बात से चिंतित हैं।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : हम इस विषय पर आपके साथ हैं।

श्री कुलदीप सिंह राठौर : देखिए विपक्ष का भी समर्थन मिल रहा है वहां के विधायक भी इस विषय को उठा रहे हैं क्योंकि इनके क्षेत्र में भी सेब होता है। यह बहुत अच्छा विषय है कि कुछ विषयों पर हमें मिलकर बात करने की जरूरत है और मुझे खुशी है कि आपका भी इसमें समर्थन है।

अब नौणी विश्वविद्यालय ने इसकी जांच की और यह पाया, हो सकता है कि थोड़ा आपको कष्ट हो लेकिन शायद नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि जो कृषि और किसान

25.08.2026/1240/बी.एस./एच.के.-2

कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है वहां जो केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड है उसकी सर्टिफिकेशन से यह हुआ है। अगर उसकी सर्टिफिकेशन से हुआ है तो

यह और भी गंभीर बात है। मैं हिमाचल के बागवानों के विषय पर ही आ रहा हूं। I am coming to that point.

Speaker : Don't pay attention to him (towards Shri Deep Raj). Pay attention to the Chair.

श्री कुलदीप सिंह राठौर : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि विपक्ष है इसलिए आपकी मार्फत जवाब दे रहा हूं। अब यह बहुत चिंता का विषय है। आप बाहर से जो कीटनाशक और दवाइयां ला रहे हैं वे उन देशों से ला रहे हैं जहां से सेब पैदा होता है। एक चिंता का विषय यह भी है और मुझे यह भी लगता है कि वे ऐसी दवाइयां हमें क्यों देंगे जो लेटेस्ट हों?

कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बागवानी के साथ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा हो? अब कोरोना आया और आज तक पता नहीं लगा कि कैसे आया। उसके पीछे क्या कारण थे? कहीं इस तरह का वायरस जानबूझकर स्प्रेड तो नहीं किया जा रहा है, ताकि हमारी बागवानी तहस-नहस हो जाए? क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और बाहर के जो मुल्क हैं जहां से सेब पैदा होता है उनका सेब आकर यहां बिकेगा और उन्हें ओपन मार्केट मिलेगी। यह भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी भी जांच होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यहां मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। विदेशों से जो नर्सरी आ रही है उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल है। बाहर से नर्सरी आती हैं। मैंने श्री जगत सिंह नेगी जी जो हमारे माननीय मंत्री हैं उनके ध्यान में भी यह मामला लाया था और उन्होंने कार्रवाई भी की। बाहर से जब यहां आयात होता है तो क्वारंटीन की व्यवस्था है परंतु ऐसा कहीं नहीं होता और झूठे सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। अब यहां भी एक प्रश्न है कि कौन-सा देश अपनी लेटेस्ट वरायटी हमें देगा? कोई देश नहीं देगा। जो वरायटी वहां ऑब्सोलिट हो गई है उसे हमारे देश में डंप किया जा रहा है। तो क्या हमारा देश डंपिंग ग्राउंड बनकर रह गया है? अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है और मैंने पिछले सत्र में भी शायद एक बात कही थी।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

25.08.2026/1245/DT/HK-1

श्री कुलदीप सिंह राठौर जारी......

अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र में भी एक बात कही थी कि जो हमारा नौनी विश्वविद्यालय है वहां पर भी रिसर्च कहां हो रही है क्योंकि इतने वर्षों में हम आज तक कोई इंडिजिनस वरायटी तैयार नहीं कर पाए हैं। अब बाहर से जो नर्सरी ला रहे हैं उनके लिए जलवायु, उनके लिए सॉयल, बिल्कुल अलग है। जरूरी नहीं कि जो हम वहां से आयात करके मंगावा हैं वह वरायटी हमारी जलवायु के लिए ठीक हो। लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय ऐसा हो रहा है और बेरोकटोक हो रहा है। हमारे जो प्रगतिशील किसान और बागवान हैं वे

अक्सर मुझसे बात करते हैं। वे कह रहे हैं कि आयात के कारण अननोन वायरस हमारे देश में आ रहा है। यह बहुत चिंता का विषय है। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा बागवानी क्षेत्र है वह एक समय बहुत संपन्न था लेकिन आज धीरे-धीरे उसकी संपन्नता कम हो रही है। एक वक्त था जब लोगों की नौकरी में कोई निर्भरता नहीं होती थी और आज मैंने देखा है कि हमारे क्षेत्र के जो नौजवान हैं वे छोटी-छोटी नौकरियों के लिए भाग रहे हैं या नौकरी लेने का प्लान कर रहे हैं-यह बहुत चिंता का विषय है। चिंता इसलिए भी है कि जिस अंधाधुंध ढंग से कीटनाशकों का छिड़काव हो रहा है उससे कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि सबसे ज्यादा कैंसर के मामले कहां हैं, जो मुझे उत्तर मिला उसमें मंडी और शिमला जिला में सबसे ज्यादा केसिज थे। क्योंकि जब आप कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो कहीं-न-कहीं हमारा जो ग्राउंड लेवल वॉटर है वह प्रदूषित होता है और उस जल का हम उपयोग करते हैं। इसलिए ज्यादातर मैंने देखा है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पहले कहा जाता था कि स्वच्छ हवा है और स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, वहां भी लगातार कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय का जो कंसर्न है वह सबका कंसर्न है। यह अकेला मेरा कंसर्न नहीं है बल्कि यह सबका कंसर्न है। जितने भी सदस्य इस सदन में बैठे हैं, चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सबका कंसर्न है। मैं आपके माध्यम से सरकार से करबद्ध निवेदन करता हूं इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। मैं अपनी बात इसके साथ खत्म करना चाहता हूं कि जो हमारा विभाग है वह अभी तक जितने भी नमूनों एकत्र कर चुका है उसमें फेल नमूने और दोषी फर्मों के बारे में अपनी जानकारी स्पष्ट करे। जो मानकों पर खरे नहीं उतरते

25.08.2026/1245/DT/HK-2

हैं उन कंपनियों तथा आपूर्ति कर्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए और दवाइयों की बैच वाइज तथा नियमित क्वालिटी टेस्टिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त बागवानों की शिकायतों के लिए त्वरित शिकायत एवं समाधान व्यवस्था बनाई जाए। सरकार यह सुनिश्चित करे कि बागवानों को केवल गुणवत्तापूर्वक दवाइयां ही उपलब्ध हों और घटिया दवा से नुकसान होने पर जिम्मेवारी तय करके उचित कार्रवाई की जाए, यह मेरी कुछ मांगें हैं।

अंत में मैं सरकार से एक मांग करना चाहता हूं। बहुत अच्छा है कि सरकार ने अपने कृषि क्षेत्र में किसानों की बहुत ज्यादा मदद करने की कोशिश की है। हमारे जो मक्का है, जो गेहूं है और हमारी जो हल्दी है उनके समर्थन मूल्य बढ़ाए गए हैं। हम इसका स्वागत करते हैं और किसानों को भी इसका फायदा होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय मेरी एक मांग है कि हमारा जो समर्थन मूल्य है वह बहुत कम है और वर्तमान में यह 12 रुपये है। हम यह नहीं कहते कि इसे बहुत ज्यादा बढ़ाओ या तीन गुना करो या दो गुना करो। कम-से-कम तीन रुपये बढ़ाकर इसे 15 रुपये करने की हम किसान और बागवानों की तरफ से मांग करते हैं। यह बहुत छोटी मांग है। अभी एम0एस0पी0 के तहत जो सेब सरकार ने खरीदे है उसमें थोड़ा विवाद हुआ है।

अध्यक्ष महोदय कई जगह पर तो सरकार उसकी जांच कर रही है। कई जगह पर विवाद हुआ है कि बहुत ज्यादा बोरियां आई हैं। शायद हो सकता है कि उस पर भी हमें प्रयास करने की जरूरत है क्योंकि कोई भी अगर बेईमानी करता है तो वह चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे छोटे और मध्यम किसान हैं उनकी पेमेंट जल्दी से सुनिश्चित होनी चाहिए।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

25.08.2026/1250/वाई.के.-एन.जी./1

श्री कुलदीप सिंह राठौर.......... जारी

इस विषय पर माननीय राजस्व मंत्री, श्री जगत सिंह नेगी जी के साथ हमने बैठक भी की है और उसमें शिमला जिला के तमाम माननीय विधायक भी साथ बैठे थे। हम सभी ने इनके सामने एक सुझाव रखा था कि कम-से-कम जो 200 बैग की औपचारिकताएं हैं, वह बिल्कुल कम होनी चाहिए या होनी ही नहीं चाहिए।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैंने आज जो विषय रखा है, उसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश सरकार मामले की गम्भीरता को समझते हुए, निश्चित तौर पर त्वरित कार्रवाई करेगी। हमारा बागवानी क्षेत्र बिल्कुल कोलैप्स होने की कगार पर है और मेरा विश्वास है कि उसे बचाने की कोशिश होगी। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री, आप इसका उत्तर देने के लिए कितना समय लेंगे? अभी हमारे पास 10 मिनट का समय शेष है और उसके बाद दोपहर के भोजन के लिए कार्यवाही स्थगित की जाएगी।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के विषय का विस्तृत रूप से लिखित जवाब बना कर लाया हूं और मैं माननीय सदस्य को यह जवाब उपलब्ध भी करवा दूंगा। लेकिन माननीय सदस्य ने अपने विषय के अलावा भी कुछ मुद्दे उठाए हैं और मैं उनका जवाब 10 मिनट में दे दूंगा।

अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री, ठीक है, आप अपना वक्तव्य दीजिए।

25.08.2026/1250/वाई.के.-एन.जी./2

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने एक बहुत ही अहम मुद्दे को नियम-62 के तहत उठाया है और इसमें कई अन्य मुद्दे भी साथ में जोड़ दिए हैं। मैं समझता हूं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत शायद इनकी मुख्य मांग तो यह थी कि कीटनाशक और इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड्स की गुणवत्ता को किस प्रकार बढ़ाया जाए और ये उसी की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह वाकई चिंता का विषय है। जितनी भी दवाइयां हैं, उनके लिए केंद्र का बोर्ड हमें सर्टिफाइड करता है कि ये दवाइयां आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हीं दवाइयों को लाइसेंस दिया जाता है। आप जानते हैं कि ये तो दवाइयां हैं जबकि हिंदुस्तान में तो खाने की वस्तुओं में भी मिलावट होती है। उन दवाइयों में मिलावट को रोकना यह हमारे विभाग का काम है। हमने हिमाचल के लगभग 500 दवा विक्रेताओं, जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आदि बेचते हैं, को लाइसेंस दिया हुआ है। साथ में हमने सबसे बड़ा काम यह किया है कि हमने एक स्प्रे शेड्यूल भी बना कर दिया है। जिसमें कौन-कौन से महीने में कौन-कौन सी दवाइयां लगानी हैं और वह कौन-कौन सी दवाएं हैं, उसका भी हमने ब्रांड नेम/जेनरिक नाम आदि दे रखा है। परंतु हो क्या रहा है कि मार्केट में हजारों किस्म की दवाइयां आ रही हैं। व्यापारी लोग या जो विभिन्न फर्म्स हैं, वे किसानों को ललचाते/लुभाते हैं कि भाई, हमारा यह प्रोडक्ट है, यह बड़ा अच्छा है और इसे ले लीजिए। उन दवाइयों को बगैर कोई टेस्ट किए या बिना विभाग व यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन के बागवान उसको यूज़ कर रहे हैं। यूज़ करने के बाद बागवानों को लग रहा है कि उससे नुकसान हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? बागवानों को हिमाचल में सेब की पैदावार करते हुए कई दशक हो गए हैं। हमारे बागवानों को भी तो जागरूक होना चाहिए कि कौन-सी दवाई लगानी है या कौन-सी नहीं लगानी है। अभी ऐसा हो रहा है कि जो मर्जी मार्केट में आया, उसको लगा लो और अपना नुकसान करवा दो।

25.08.2026/1250/वाई.के.-एन.जी./3

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार बनी है, तब से हमने इसके ऊपर बहुत ही कठोर संज्ञान लिया है और हम कोशिश करते हैं कि जो स्प्रे शेड्यूल हमने यूनिवर्सिटी के द्वारा इज़ात किया है और जो दवाइयां सेंटर बोर्ड से रिकमेंड की जाती हैं, उन्हीं दवाइयों को लोग यूज़ करें। अभी वे हर कहीं से दवा ले लेंगे और बाद में पछताते रहेंगे तो उसका क्या करें?

दूसरी बात यह है कि बागवानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ है। हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग के जगह-जगह पर एस0एम0एस0 तैनात हैं। इसके साथ ही पैथोलॉजी जानने वाले लोग हैं। किसान/बागवान लोग उधर कभी नहीं जाते और सीधा नजदीकी मार्केट में जाते हैं और वहां से दवा उठा लाते हैं। यह पी0जी0आर0 का मामला है। हमारे बड़े बागवान लंबे समय से पी0जी0आर0 यूज़ करते रहे हैं। वह सारा का सारा, एक किस्म से ग्रे मार्केट से आता है। पहले तो केंद्र के बोर्ड ने रिकमेंड ही नहीं किया था और ये ग्रे मार्केट से लाते थे। शुरू-शुरू में शायद अच्छी क्वालिटी के आए होंगे। जो बड़े बागवान हैं, वे तो शायद डायरेक्ट स्मगल करके भी मंगवा रहे होंगे और उनके सेब में बहुत फर्क रहा है। छोटे बागवानों ने देखा कि इनके तो लगातार सेब आ रहे हैं, कलर भी बढ़िया आ रहा है और साइज भी बढ़िया आ रहा है। उसके बाद वे भी इनके पीछे चल पड़े। जब वे पी0जी0आर0 में गए तो, जो बीच में आप जानते हैं कि देश के अंदर हर व्यवस्था में कोई-न-कोई कमी छूट ही जाती है। अभी जो नकली पी0जी0आर0 है, उसमें असली डिब्बे की तरह लेबल लगाकर, बाहर से सारे स्टिकर्स लगाकर, यह दर्शाते हैं कि यह असली है और हमारे बागवान उससे धोखा खा जाते हैं। जब वे उसको लगाते हैं तो जो रिजल्ट अपेक्षित होता था, वह रिजल्ट नहीं मिलता। इसमें बागवानों को जागरूक होने की जरूरत है। आज तक ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका हमें न पता हो।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

25.08.2026/1255/YK/PB/1

राजस्व मंत्री जारी...

यह वही बीमारियां है जो आज से नहीं बल्कि तीस-चालीस वर्षों पहले अन्य देशों में लगी हैं। यह बात भी ठीक है कि हमें सारा-का-सारा प्लांट मटीरियल देश के बाहर से लाना पड़ता है। प्लांट मटीरियल को नियंत्रित करने का काम क्वारंटाइन एक्ट के तहत केंद्र सरकार करती है। क्वारंटाइन के लाइसेंस भी केंद्र सरकार ही देती है और इस संबंध में सारी प्रक्रिया भी वही करती है। इसके बाद भी हम अपने प्रदेश में यह कोशिश करते है कि बाहर से बिना क्वारंटाइन किए कोई पौधा न आए। परंतु आप जानते है कि हिमाचल एक बॉर्डर वाला प्रदेश नहीं है। हिमाचल में हजारों जगहों से एंट्री की जा सकती है। हमने कई कंटेनर वापस भेजे हैं। परंतु उसका नुकसान किसको हो रहा था? जिन बागवानों ने एडवांस में पैसे दिए थे उन्हें नुकसान हो रहा था। इसलिए हमें वहां थोड़ी सख्ती कम करनी पड़ी। क्वारंटाइन में जो सर्टिफिकेशन होता है कि यह पौधा वायरस फ्री और डिसीज़ फ्री है, उसकी जिम्मेवारी भी केंद्र सरकार की है। परंतु इन सारी चीजों के होते हुए भी हमने एक सिस्टम बनाया है जिसके तहत प्रदेश में ही अच्छी किस्म के ऐसे पौधे तैयार किए जा रहे हैं जो यूनिवर्सल है, जिनमें कम समय में अधिक फल लगते हैं। इनमें रूट स्टॉक की किस्म भी हैं।

हमने नर्सरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक सोसाइटी बनाई है। उस सोसाइटी में हम विदेश की कंपनी के साथ करार करके स्वयं भी नर्सरी तैयार कर रहे हैं। हमारे पास पहले का जो प्लांट मटीरियल है उसको भी हम तैयार कर रहे हैं। हम लगभग 5 लाख नई वराइटीज के रूट स्टॉक और कल्टीवर्स बागवानों को सप्लाई कर रहे हैं। परंतु हमारे पास डिमांड नहीं है। माननीय सदस्य सदन में जो कह रहे है उसमें कुछ बातें जानकारी के अभाव में भी कही जा रही हैं। जो भी बीमारियां लगी हैं उनमें अल्टरनेरिया कोई नई बीमारी नहीं है। यह बीमारी पहले से चली आ रही है। हमने यूनिवर्सिटी में पूरा दिन सेमिनार किया। मैं पूरा दिन वहां बैठा रहा। सारे बागवानों को बुलाया गया और सारे माननीय मंत्री तथा विधायकगण को भी न्यौता दिया गया लेकिन वहां कितने लोग आए? वहां जो बात सामने आई वह यह थी कि यह बीमारी पहले से मौजूद थी। परंतु समस्या यह है कि हम सही

समय पर और सही शेड्यूल के अनुसार स्प्रे नहीं करते हैं। इस बार क्या हुआ है? फसल कम लगी और मौसम भी हमारे खिलाफ रहा। जब सेब कम लगे तो बागवानों ने स्प्रे नहीं किया। जब स्प्रे नहीं किया तो अल्टरनेरिया की समस्या आ गई।

25.08.2026/1255/YK/PB/2

इसमें सबसे बड़ी बात, जिसे मैं कई बार कह चुका हूं कि हमें फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहिए। इसमें खासकर सेब के बागवानों के लिए बहुत बढ़िया प्रावधान है। एक पेड़ का इन्श्योरेंस 73 रुपये में करना है और यह इन्श्योरेंस 20 दिसंबर से पहले करना है। इसमें पहले प्रत्येक पेड़ का अधिकतम 700 रुपये मिलता था जिसे हमने बढ़ाकर 1,500 रुपये किया है। अगर आप समय पर इन्श्योरेंस करेंगे तो चिलिंग आवर्स कम हो जाने, रेनफॉल कम हो जाने, फ्लावरिंग कम हो जाने या सेब कम लगने की स्थिति में आपको वेदर बेस्ड इन्श्योरेंस स्कीम के तहत पूरा लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत मेरे छोटे से जिले में एक साल के भीतर 14 करोड़ रुपये बांटे गए। यह वर्ष 2023-24 का आंकड़ा है। उसके बाद कंपनियों ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। इसलिए हमने कंपनियों को कहा है कि अगर आप समय पर पैसे नहीं देंगे तो हम आपसे इंट्रस्ट लेंगे। हिमाचल में सेब के बागवान 2 लाख से ऊपर हैं लेकिन केवल 75 हजार से कम बागवानों ने इन्श्योरेंस करवाया है। इसलिए इन्श्योरेंस का फायदा उठाने की सबसे अधिक जरूरत है और हम बार-बार यही कह रहे हैं।

हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमैंट और यूनिवर्सिटीज जगह-जगह कैंप लगाते हैं। परंतु उन कैंप्स में हाजिरी कितने लोगों की होती है? गिने-चुने लोग ही उन कैंप्स में आते हैं। हम उनको लेटेस्ट जानकारी और तकनीकी जानकारी देने की कोशिश करते हैं लेकिन बागवान को खुद भी जागरूक होना चाहिए है। दूसरी बात यहां पर दवाइयों को लेकर आई है। हमने विशेषकर दवाइयों के संबंध में यह फैसला किया है कि विभाग खुद बागवानों को दवाइयां बेचेगा। हमने यह भी फैसला किया है कि यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेड ब्रांडेड और बेस्ट दवाइयां डायरेक्ट फर्म्स से डील करके एम0आर0पी0 से नीचे बागवानों को देंगे। अभी मेरे पास इसकी लिस्ट उपलब्ध नहीं है अन्यथा मैं आपको बताता कि किस दवाई के रेट में कितनी कमी है। कई दवाइयां तो एम0आर0पी0 से 300 रुपये तक

कम में दी जा रही है। लेकिन हमारे यहां से दवाइयां लेने के बजाय बागवान प्राइवेट दुकानों से दवाइयां लेते हैं। हम बागवानों को यह एश्योर करते हैं कि आप विभाग के सेल्स सैंटर्स से दवाई लें। वह दवाई मार्किट से सस्ती भी होगी और अगर उसमें कोई गुणवत्ता की कमी आएगी तो उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। परंतु इतनी बड़ी मार्किट में हर जगह से दो नंबर की दवाइयां आ रही हैं। उनको एक किस्म से कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं है। खाने की दवाइयों के

25.08.2026/1255/YK/PB/3

सैंपल रोज फेल हो रहे हैं। मैंने इन्सेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के संबंध में भी कहा है कि इनकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए।

सेब को सबसे ज्यादा खतरा कहां से हो रहा है? सेब को मौसम से खतरा हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा केंद्र सरकार द्वारा किए गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से है।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

25.08.2026/1300/ए0जी0/ए0पी0-01

राजस्व मंत्री जारी .....

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा खतरा यह है कि केंद्र सरकार ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। जिसके कारण अमेरिका से बिना टैक्स के सेब हिंदुस्तान में आएगा। न्यूज़ीलैंड के सेब पर 50 प्रतिशत टैक्स होना चाहिए था लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा उसे घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिनसे सेब की पैदावार में कमी भी हो रही है और बागवानों को नुकसान भी हो रहा है। बागवानी विभाग की तरफ से हमने इसमें कई रिफॉर्म किए हैं। जो हमारा यूनिवर्सल कार्टन है, केन्द्र में कांग्रेस के समय भी इसकी बात होती थी और इनके समय में भी हुई। हमारे ऊपर भारी दबाव था कि यूनिवर्सल कार्टन न लगाया जाए लेकिन हमने यूनिवर्सल कार्टन लागू किया। जिसका बागवानों को फायदा हो रहा है। हमने बाय वेट सेब बेचने की व्यवस्था की जिसका फायदा बागवानों को हो रहा है। अब

फिर से एम0आई0एस0 पर आ गए हैं। एम0आई0एस0 के लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है क्योंकि इसमें 50 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार को देना है। पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार हमें एम0आई0एस0 का शेयर नहीं दे रही है। एम0आई0एस0 में केंद्र सरकार ने यह कंपलसरी किया है कि किसान को एग्रीटेक में जुड़ना पड़ेगा। इसमें दिक्कत क्या है? हमने एक ऐप बनाया है जिसमें सिर्फ अपना नाम डालना है और बागवान आधार से लिंक हो जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अगर किसी को ऐप चलाना नहीं आता है तो वह 25 रुपये में लोकमित्र केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो हम खुद उनकी मदद करेंगे। हर रोज 600 से ज्यादा लोग इसमें रजिस्टर होते हैं। किसी जमाने एम0आई0एस0 में एक बहुत बड़ा करप्शन चल रहा था। उस करप्शन को खत्म करने के लिए हमने एम0आई0एस0 में एक नया सिस्टम शुरू किया है। इस सिस्टम का कुछ बड़े किसान इसका विरोध कर रहे हैं जो पांच-पांच हजार और तीन-तीन हजार बोरी लाते हैं। जबकि हमारे 45 हजार बागवान और 48 हजार बेनिफिशियरी एम0आई0एस0 में हैं। इनमें 25 हजार बागवान ऐसे हैं जिनके पास 100 से कम बोरियां हैं। सिर्फ 6-8 प्रतिशत लोग ही ऐसे हैं जो सारा-का-सारा एम0आई0एस0 का पैसा ले रहे हैं। हम पारदर्शी तरीके से काम करना चाहते हैं।

25.08.2026/1300/ए0जी0/ए0पी0-02

चाहे कोई भी बागवान हो, जिसका सेब है, चाहे एक बोरी ही हो, हम उसकी बोरी जरूर लेंगे। लेकिन उनको पहले रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और अपने आपको फार्मर तो घोषित करें। हम यह नहीं पूछ रहे हैं कि आपके पास कितनी जमीन है। हम तो केवल यह कह रहे हैं कि आप फार्मर हैं या नहीं, आप सिर्फ यह बताइए। इनके खाते नहीं- इनके खाते हैं। ये है ग्रीड़ और गरीब आदमी को पैसा नहीं मिला रहा। ये बड़े-बड़े ट्रांसपोर्टर और हमारे जो कर्मचारी इसमें मिले हुए हैं। मैं यह नहीं कहता कि हमारे लोग भी दूध के धुले हैं। प्रोक्योरमेंट सेंटर पर जब हम एजेंट लगाते हैं, वहां तीन-चार लोग मिलकर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये गरीब का लूट रहे हैं। हम इसको लूटने नहीं देंगे। हम इसको पारदर्शी

करेंगे और **मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं कि एक भी सेब की बोरी, किसी भी फार्मर को अगर जायज है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम उसे लेंगे और उसका पैसा भी समय पर देंगे।** यही मैं कहना चाहता हूं।

Speaker: House adjourned for lunch break. We will reassemble at 2'o Clock.

25.08.2026/1405/AT/AS/01

(सदन की बैठक भोजनावकाश उपरान्त 2.05 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरंभ हुई।)

Speaker : There is another issue under Rule-62 by the Hon'ble MLA श्री पवन कुमार काजल जी द्वारा एक अन्य विषय उठाया जाना है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री पवन कुमार काजल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि गग्गल में भूमि अधिग्रहण एवं विस्थापन से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष: अब इस पर माननीय उप-मुख्यमंत्री जी उत्तर देंगे। He has been authorized by the Hon'ble Chief Minister. काजल साहब को यदि कोई स्पष्टीकरण चाहिए होगा, तो I will allow that. अब माननीय श्री पवन कुमार काजल जी।

श्री पवन कुमार काजल : माननीय अध्यक्ष महोदय, गग्गल एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि वर्ष 1960 से 1970 के दौरान, जब विभाजन हुआ था, तब लगभग 60-70 परिवारों को तत्कालीन पंचायत ने वहां बसाया था। बसाने के समय उन्हें क्या पता था कि भविष्य में यहां एयरपोर्ट बनेगा और वे एयरपोर्ट की जद में आ जाएंगे। वर्ष 1960 से वर्ष 1970 के बीच आए इन लगभग 70 परिवारों को, करीब 60-65 वर्ष पहले, तत्कालीन पंचायत ने पांच-पांच मरले भूमि दी थी। इन पांच-पांच मरलों में उन्होंने अपने घर बनाए। आज 50-60 साल बाद, जिस घर में पहले एक परिवार रहता था, वहां

दो-दो, तीन-तीन और चार-चार परिवार हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि एयरपोर्ट बनने के कारण सभी को मुआवजा मिल गया है, लेकिन ये लगभग 70 परिवार पंचायत द्वारा आवंटित भूमि पर बसे हुए हैं। ये लोग आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय से भी मिले थे। मुख्य मंत्री महोदय जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इन 60-70 अथवा 70-80 परिवारों की पांच-पांच मरले भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और जिस प्रकार निजी भूमि का मुआवजा दिया गया है, उसी प्रकार इन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा

25.08.2026/1405/AT/AS/02

माननीय मुख्य मंत्री महोदय आज सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं कि ये परिवार मुख्य मंत्री महोदय से मिले थे। मेरी और इन परिवारों की चिंता यह है कि इन्हें क्या पता था कि 50-60 साल बाद यहां एयरपोर्ट बनेगा और इन्हें उजड़ना पड़ेगा। मेरी चिंता यह है कि जिस प्रकार पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) की व्यवस्था है, उसे परिवारों की संख्या के अनुसार दिया जाए। पहले एक परिवार था, लेकिन आज वहां तीन-तीन और चार-चार परिवार हो गए हैं। ये सभी विस्थापन झेल रहे हैं, इसलिए इन्हें परिवार के हिसाब से R&R तथा मुआवजा दिया जाए।

मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय जी से बार-बार यह कह रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इन सभी परिवारों को आश्वासन दिया था कि उन्हें उजड़ने नहीं दिया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो नियमों के विपरीत जाकर भी इनके बारे में विचार किया जाएगा। मैं आज इस सदन के माध्यम से माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि जो परिवार पांच-पांच मरले भूमि पर बसे थे और जिनमें आज तीन-तीन तथा चार-चार परिवार हो गए हैं, ऐसे लगभग 70 परिवारों को क्या अन्य लोगों की तरह R&R मिलेगा या नहीं मिलेगा?

Speaker : You can ask the clarification after the reply of the Hon'ble Minister. माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय।

उप-मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, गग्गल का हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश सरकार का एक महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसे धरातल पर उतारने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी ……

25.08.2026/1410/AV/AS/1

उप मुख्य मंत्री जारी

वैसे तो देश में हवाई अड्डों का निर्माण कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें बड़े खर्चे होते हैं और लैण्ड ऐक्विजिशन का ही बहुत ज्यादा खर्चा आता है। लेकिन हमारा एक छोटा राज्य है और हमारी राजनैतिक ताकत सशक्त नहीं है। हमारा राज्य चार सांसदों वाला है। इस बारे में काफी वर्षों से प्रयास हो रहे हैं कि हमारे प्रदेश में कोई-न-कोई बड़ा हवाई अड्डा बने। पूर्व में श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार भी मण्डी में हवाई अड्डा बनाने हेतु प्रयासरत थी। उसी क्रम में इस सरकार ने गगल हवाई अड्डे को प्राथमिकता दी है। लेकिन इस दफ़ा ग्राउंड पर काफी काम हो चुका है। ऐसी सम्भावनाएं हैं कि गगल में एक बड़ा हवाई अड्डा बनकर तैयार हो जाए। इसकी वस्तुस्थिति इस प्रकार से है :-

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा इस चर्चा का स्वागत करता हूं। मैं माननीय सदस्य को इस सदन में अवगत करवाना चाहूंगा कि गगल स्थित कांगड़ा हवाई अड्डे के प्रस्तावित विस्तार हेतु आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित एवं विस्थापित होने वाले व्यक्ति एवं परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की वैधानिक प्रक्रिया के साथ-साथ राहत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, जिसको कि माननीय सदस्य आर0 एण्ड आर0 कह रहे थे, से संबंधित कार्रवाई भी की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि परियोजना से प्रभावित प्रत्येक पात्र व्यक्ति एवं परिवार को लागू वैधानिक प्रावधानों तथा राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित आर0 एण्ड आर0 व्यवस्था के अनुरूप देय लाभ प्रदान किए जाएं। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु लगभग 157 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें से 26 हेक्टेयर सरकारी भूमि है और 131 हेक्टेयर निजी भूमि है। भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न सामाजिक प्रभावों के आंकलन हेतु दिनांक 28 फरवरी, 2023 को सोशल इंपैक्ट असेसमैंट (SIA) संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी। एस0आई0ए0 का कार्य हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान फेयरलॉन शिमला की एस0आई0ए0 इकाई के माध्यम से करवाया जाता है तथा बहुविषयक विशेषज्ञों-समूह

द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट को राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष 21.6.2023 को अनुमोदित किया गया। इसके पश्चात अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत दिनांक 7.7.2023 को प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई तथा धारा 19 के अंतर्गत दिनांक 16.8.2024 को घोषणा जारी की गई, जिसे

25.08.2026/1410/AV/AS/2

दिनांक 17.8.2024 को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। संभावित रूप से प्रभावित परिवारों को अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत आवश्यक नोटिस भी जारी किए गए। इस प्रकार सामाजिक प्रभावों के आंकलन तथा प्रभावित परिवारों की पहचान एवं उनके वैधानिक अधिकारों को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में समाहित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित आर0 एण्ड आर0 व्यवस्था के अंतर्गत भूमि के मुआवजे से पृथक पात्र प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के देय लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों के आवासीय, सामाजिक एवं आजीविका संबंधी हितों का संरक्षण करना है। इसके अंतर्गत प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों को पहचान एवं पात्रता का निर्धारण, देय आर0 एण्ड आर0 लाभों का निर्धारण एवं भुगतान तथा परियोजना के कारण उत्पन्न आवासीय एवं आजीविका संबंधी प्रभावों के निवारण हेतु देय सहायता प्रदान की जानी है। उपलब्ध वित्तीय आंकलन के अनुसार कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण की अनुमानित लागत 2680 करोड़ तथा आर0 एण्ड आर0 की अनुमानित लागत 661 करोड़ रुपये है। इस प्रकार भूमि अधिग्रहण एंड आर0 एण्ड आर0 कुल अनुमानित लागत 3349 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें 3349 करोड़ रुपये पूरा खर्चा होना है। जिसमें भूमि अधिग्रहण का 2688 करोड़ रुपये से ज्यादा है और आर0 एण्ड आर0 का 661 करोड़ रुपये है। इससे भूमि अधिग्रहण संबंधी देय मुआवजा तथा परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संबंधी देयताओं को शामिल किया गया है। आर0 एण्ड आर0 व्यवस्था के अंतर्गत अब तक 193.62 करोड़ रुपये के आर0 एण्ड आर0 अवार्ड घोषित किए जा चुके हैं।

एन एस द्वारा जारी

25-8-2026/1415/NS-DC/1

उप-मुख्य मंत्री -----जारी

जिनमें से 178.93 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। शेष मामलों में दावों, पात्रता तथा आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है और आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरांत पात्र मामलों में भुगतान की कार्रवाई कर दी जाएगी। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, गग्गल एयरपोर्टज्-कम-एस0डी0एम0, कांगड़ा द्वारा की जा रही है। अब तक कुल मूल्य 2579 करोड़ रुपये की भूमि के अवार्ड कर दिए गए हैं तथा लगभग 2463 करोड़ रुपये की भूमि मुआवजा राशि लाभार्थियों को वितरित की जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, लगभग 2579 करोड़ रुपये की राशि अब तक भूमि मालिकों को दी जा चुकी है। लगभग 1145 लाभार्थियों से संबंधित 347.51 करोड़ रुपये की राशि अभी वितरित नहीं की जा सकी है। लंबित भुगतान के प्रमुख कारणों में एक से अधिक दावेदारों के दावे, स्वामित्व संबंधी विवाद तथा बैंक खातों एवं आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित विषय सम्मिलित हैं। संबंधित दावों एवं अभिलेखों का परीक्षण किया गया है। पात्रता स्थापित होने एवं आवश्यक वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण होने पर भुगतान की कार्रवाई कर दी जाएगी। भूमि मालिकों एवं किरायेदारों के मध्य राशि के वितरण के अनुपात के संबंध में एक्ट 2013 के अंतर्गत परामर्शी विभागों के माध्यम से आवश्यक स्पष्टीकरण भी दिए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, परियोजना के लिए आवश्यक सरकारी भूमि पर प्रभावित व्यक्तियों एवं संरचनाओं के संबंध में भी राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है। कांगड़ा एवं शाहपुर तहसील के 14 गांवों में लगभग 26.08 हैक्टेयर सरकारी भूमि से संबंधित मामलों में उपायुक्त, कांगड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर 113 इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स के लिए 16.76 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के पत्र संख्या 8/2024 दिनांक 10 जून, 2026 के माध्यम से प्रस्तावित कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार हेतु अधिकृत की जाने वाली सरकारी भूमि पर विद्यमान राजस्व प्रविष्टियों एवं संरचनाओं के कारण प्रभावित परिवारों को बाजार दरों पर

लगभग 16.76 करोड़ रुपये की री-एलोकेशन स्थानांतरण सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की स्वीकृति से अवगत करवाते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। पात्र लाभार्थियों को

25-8-2026/1415/NS-DC/2

अनुमोदित राशि स्थानांतरण सहायता के रूप में वितरित करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी आप यहां पर चिंता जता रहे हैं।

इसके अतिरिक्त प्रस्तावित विस्तार से संबंधित 14 चिन्हित मुहल्लों में छूटे हुए खसरा नंबरों की लगभग 9.23 हैक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत दिनांक 23 मार्च, 2026 को प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा दिनांक 25 मई, 2026 को आवश्यक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई तथा सरकार द्वारा दिनांक 6 जून, 2026 के पत्र के माध्यम से धारा 19 के अंतर्गत आगे की कार्रवाई हेतु आवश्यक अनुमोदन प्रदान कर दिए गए हैं। उक्त भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पात्र प्रभावित व्यक्तियों के आर0 एण्ड आर0 संबंधी दावों का निर्धारण लागू वैधानिक प्रावधानों एवं अनुमोदित व्यवस्था के अनुसार कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं समग्र रूप से यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ प्रभावित एवं विस्थापित व्यक्तियों एवं परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन को राज्य सरकार द्वारा एक पृथक एवं आवश्यक वैधानिक दायित्व के रूप में संबोधित किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण एवं आर0 एण्ड आर0 के लिए कुल अनुमानित वित्तीय आवश्यकता 3349 करोड़ रुपये है। आर0 एण्ड आर0 के अंतर्गत अब तक 193.62 करोड़ रुपये मूल्य के अवार्ड घोषित हो चुके हैं तथा 178.93 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। सरकारी भूमि पर प्रभावित 113 इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स के संबंध में 16.76 करोड़ रुपये की स्थानांतरण सहायता के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शेष पात्र मामलों का आवश्यक दस्तावेजों, दावों एवं पात्रता के परीक्षण के उपरांत समयबद्ध रूप से निपटारा किया

जाएगा तथा पात्र प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों को उनके वैधानिक एवं अनुमेय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन लाभ प्रदान कर दिए जाएंगे।

अंत में, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से प्रभावित परिवारों के हितों का संरक्षण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। भूमि अधिग्रहण के

25-8-2026/1415/NS-DC/3

साथ-साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की कार्रवाई निर्धारित वैधानिक प्रावधानों एवं मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित व्यवस्था के अनुसार की जा रही है

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

25.08.2026/1420/RKS/DC-1

उप-मुख्य मंत्री जारी

सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि शेष पात्र मामलों का समयबद्ध निपटारा कर दिया जाए और किसी भी पात्र प्रभावित परिवार के वैधानिक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिकारों से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अतः माननीय विधायक से मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार हवाई अड्डे के विस्तार का कार्य चल रहा है उसके लिए वर्तमान सरकार द्वारा लगभग 3500 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जा चुकी है। आप आर0 एण्ड आर0 के अंतर्गत जिन मुद्दों को उठाने के लिए कह रहे हैं उन्हें भी सरकार अड्रेस कर रही है। किसी भी पात्र व्यक्ति को कोई नुकसान न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारी भूमि पर रहने वाले लोगों के संबंध में भी सरकार नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। मुझे

विश्वास है कि माननीय सदस्य और उस क्षेत्र से संबंधित विधायक सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से संतुष्ट होंगे। जब इतना बड़ा कार्य प्रगति पर है और सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है तब इस क्षेत्र को हवाई अड्डे की सुविधा मिलने के बाद इसकी महत्ता और जिला कांगड़ा की महत्ता में भी वृद्धि होगी। मुझे आशा है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से एक बड़ा हवाई अड्डा विकसित करने के लिए जो कदम उठा रही है, उनकी आप सराहना करेंगे। जिन लोगों की सहायता किए जाने की आवश्यकता है, उनकी चिंताओं को भी हम अड्रेस करेंगे। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि प्रदेश के विकास हेतु सरकार द्वारा आरम्भ किए गए इस महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट को देखते हुए नियम-62 के अंतर्गत प्रस्तुत अपने प्रस्ताव को वापस लेने पर विचार करें। यह प्रदेश के विकास की दिशा में एक अत्यंत बड़ा कदम है।

अध्यक्ष : माननीय उप-मुख्य मंत्री जी इस विषय को वापिस लेने की आवश्यकता नहीं होती। Hon'ble Deputy Chief Minister has replied very exhaustively so all issues stands covered. क्या इसमें कोई माननीय सदस्य स्पष्टीकरण लेना चाह रहा है? श्री पवन कुमार काजल जी क्या आप स्पष्टीकरण लेना चा रहे हैं? Hon'ble Member Sh. Kewal Singh Pathania ji also want some clarification on this issue. श्री पवन कुमार काजल जी।

श्री पवन कुमार काजल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि एयरपोर्ट का जो विस्तार होना है वह सरकार का ड्रीम प्रोजैक्ट है और

25.08.2026/1420/RKS/DC-2

मैं इसका स्वागत करता हूं। एक समय था जब हम हजारों लोगों के बेघर होने की आशंका को लेकर इसका विरोध करते थे। किन्तु अब मेरी चिंता गगल के उन लगभग 70 परिवारों को लेकर है जो पिछले 60-70 वर्षों से सरकारी भूमि पर बसे हुए हैं। मुख्य मंत्री जी ने एयरपोर्ट के दौरे के दौरान उनसे कहा था कि जिस प्रकार निजी भूमि के मालिकों को मुआवजा दिया गया है उसी प्रकार उन्हें भी सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया था कि उन्हें आर0 एण्ड आर0 का लाभ भी दिया जाएगा। मेरा केवल यह

स्पष्टीकरण है कि क्या इन 70 परिवारों को भी निजी भूमि मालिकों की तर्ज पर मुआवजा तथा आर0 एण्ड आर0 के लाभ प्रदान किए जाएंगे? बस यही मेरा प्रश्न है।

अध्यक्ष : माननीय श्री पवन कुमार काजल जी स्पष्टीकरण मांग रहे हैं क्या इसमें माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया कुछ और जोड़ना चाहते हैं?

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, नियम-62 के अंतर्गत माननीय श्री पवन कुमार काजल जी यह प्रस्ताव लेकर आए हैं। ...(व्यवधान)

Speaker: Anybody can seek clarification on the issue under Rule 62. ...(व्यवधान) हम इस राइट को एग्जॉस्ट नहीं करते। I have been doing that.

श्री केवल सिंह पठानिया : जहां तक 3400 करोड़ रुपये की राशि एयरपोर्ट विस्तार के लिए उपलब्ध करवाने का प्रश्न है उसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा। मेरे क्षेत्र सहित जिला कांगड़ा के लिए यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण परियोजना है। प्रदेश का यह पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जिसका इस स्तर पर विस्तार किया जा रहा है। जहां तक मुआवजे का प्रश्न है, माननीय श्री पवन कुमार काजल जी के क्षेत्र में भी लोगों को मुआवजा मिला है तथा मेरे चुनाव क्षेत्र की पंचायतों को भी इसका मुआवजा मिला है। लोगों को अच्छा मुआवजा प्रदान किया गया है। अब जो स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, वह उन 70 परिवारों के संबंध में है। जहां तक आर0 एण्ड आर0 का प्रश्न है यह हमारी पहली सरकार है, जिसने मेरे विधान सभा क्षेत्र की तीन पंचायतों के प्रभावित परिवारों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (आर0 एण्ड आर0) के अंतर्गत 9.5 लाख रुपये का बसाव भत्ता प्रदान किया है। इस योजना के विस्तार व मुआवजे इत्यादि के लिए

25.08.2026/1420/RKS/DC-3

3403 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। आज नहीं बल्कि चौदहवीं विधान सभा के कार्यकाल से आगे भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी इसका लाभ क्षेत्र के लोगों को मिलता रहेगा।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

25.08.2026/1425/बी.एस./.एच के-1

श्री केवल सिंह पठानिया जारी...

आदरणीय काजल जी आपने अपनी बात रख ली है, अब मुझे बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : आदरणीय काजल जी, यह आपने डिसाइड नहीं करना है, I have given him a time. ...(Interruption) I have given him a time. This will be decided by me. I have given him a time. ...(Interruption) I have given him a time. अगर आपने प्रश्न पूछना है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। Shri Pawan Kumar Kajalji, if you want to ask any clarification, I will allow you.

श्री केवल सिंह पठानिया : यह तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने डिसाइड करना है कि हाउस कैसे चलाना है। मेरा मानना है कि यह लोगों के हित की बात है। मैं चाहता हूं कि जो इन्होंने परिवारों की बात कही है कि 26 जनवरी 1950 को जो इंतकाल में गग्गल के अंदर बसे थे उन परिवारों के नाम जो जमीन थी उसमें एक तो उनको कंपनसेशन मिली। यह पंचायत मेरे साथ वाले क्षेत्र की है। इन्होंने जो 60-70 परिवारों की बात की है। यह बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिवली 45-46 परिवार हैं, हो सकता है कि अभी इसमें और ऐड हों। ...(व्यवधान)

Speaker : Don't pay any attention towards them.

श्री केवल सिंह पठानिया : ये जो परिवार हैं, ये 60-70 सालों से वहां काम-काज कर रहे हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि जहां 3403 करोड़ रुपये हैं यह बहुत बड़ी राशि है यह कोई छोटा-मोटा फैसला नहीं है जिला कांगड़ा के लिए यह बहुत-बहुत बड़ा फैसला है।

Speaker : Dr. Hans Rajji please, please. You happened to be a Deputy Speaker. आप बीच में बत बोलिए। मैंने अभी आपको बोलने के लिए अनुमति ही नहीं दी। Let him complete. ...(Interruption) Let him complete. ...(Interruption) आपका कोई समय नहीं जा रहा है। हाउस का सामय है, I will extend it. ...(Interruption) I will

25.08.2026/1425/बी.एस./.-2

extend the House. ...(Interruption) I will extend it upto 8 o'clock. Where is the problem? We will be extending it. Please be seated.

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि ये जो परिवार उजड़ रहे हैं जिनका यह मामला है, जनवरी, 1970 में जो सैटलमैंट हुआ था ये वो परिवार हैं और उनकी एंट्री नहीं है। आदरणीय विधायक जी ठीक कह रहे हैं कि एक-एक के चार-चार परिवार बन गए हैं। और दूसरा मैं उप-मुख्य मंत्री महोदय से यह चाहता हूं कि क्या हमने 4,000 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने खर्च कर दिए हैं?

इस बार जो बजट आया है माननीय प्रधान मंत्री ने अनाउंस किया उसमें देश भर में जहां गांवों के एयरपोर्ट एक्सपैंशन होंगे और कहा है कि हम कनैक्टिविटी देंगे। मैं चाहता हूं ...(व्यवधान) क्या ऐसा प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश की सरकार केन्द्र सरकार को भेजेगी? अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका धन्यवाद।

Speaker : The clarifications which he has sought ...(Interruption) Please, please ...(Interruption) I will allow you. आप एक-एक करके उत्तर दे दीजिए I have no issue. जो क्लेरिफिकेशन इन्होंने चाही है ...(Interruption) The clarification which he has seeking i.e. within the ambit of issue. उसी के ऊपर आप जवाब दीजिए।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, गग्गल का एयरपोर्ट का निर्माण मौजूदा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूरे देश में एयरपोर्ट्स जो हैं केंद्र सरकार ने बनाए हैं। अब हाल ही में बिहार में चार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स जो हैं केंद्र सरकार बना रही है। लेकिन समहाऊ हिमाचल प्रदेश में केंद्र से हमें एयरपोर्ट्स के विस्तारीकरण की या बड़े एयरपोर्ट बनाने के लिए सहयोग नहीं मिल पाया।

इसलिए जो सरकारें रही हैं निरंतर सरकारें प्रयास कर रही हैं कि कोई-न-कोई एक एयरपोर्ट तो हम ऐसा बना लें पूरा जहां पे हम टूरिस्ट को इनवाइट कर सकें। इंडस्ट्रियलिस्ट को इनवाइट कर सकें और प्रदेश के लोगों को जिससे लाभान्वित कर

सकें। इसलिए हमारे पास तीन ही एयरपोर्ट हैं। एक धर्मशाला का है और एक शिमला का है और एक भुंतर का है।

25.08.2026/1425/बी.एस./.-3

हमारी सरकार ने धर्मशाला को टूरिज्म की दृष्टि से प्रोत्साहन देने के लिए फैसला लिया और अब इस पर लगभग 3500 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। यह पहली दफा है कि जमीन एक्विजिशन का काम तो हो ही रहा है साथ-ही-साथ जो लोग यहां उजड़े हैं उनके पुनर्वास का काम भी किया जा रहा है। जब भी प्रोजेक्ट बनते हैं तो लोग उजड़ते हैं और हमारे लोग बहुत परेशान हुए हैं। आपने देखा है कि उनको राजस्थान में जाकर कहां पट्टे दे दिए गए।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

25.08.2026/1430/DT/HK-1
उप-मुख्य मंत्री जारी..

लेकिन उन्हें वहां पर किसी ने बसाया नहीं। लेकिन प्रदेश सरकार उन लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार सबसे ज्यादा गंभीर है। अब तो 113 इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स को भी 17 करोड़ रुपये दे दिए गए हैं। आप कह रहे हैं कि 70 लोग हैं और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 45 लोग हैं। मैं इस हाउस को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब हम इतना बड़ा कदम उठा ही चुके हैं तो किसी को भी हाइड्राय नहीं रखा जाएगा ताकि कोई ऐसा व्यक्ति बाद में छूट न जाए। सब लोगों के हितों का ख्याल रखते हुए हम फाइनलिटी पर पहुंचेंगे और सबके हितों की पूर्ति करेंगे। अब बहुत थोड़ा-सा भाग बचा है जो आप ध्यान में ला रहे हैं। उसको भी मंत्रिमण्डल से अप्रूव करवाकर कोई फैसला लेकर हम लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे।

Speaker : Thank you Hon'ble Deputy Chief Minister. You have exhaustively replied. Thank you very much.

आपने क्लैरिफिकेशन पूछा था और जानकारी मांगी थी? ऐसा है कि clarification is allowed but no further information. अब नियम-130 के अंतर्गत जो विषय लगा है उसे ले लेते हैं।

अब नियम-130 के अंतर्गत विषय उठेंगे। पिछले कल माननीय श्री विपिन सिंह परमार जी का विषय चर्चा में ऑलरेडी है जो इस प्रकार से है कि "प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों के निर्माणाधीन भवनों, आधुनिक उपकरणों, दवाइयों की अभावता, रिक्तियों तथा स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्ता प्रदान करने बारे सदन विचार करे"। इस पर आगे चर्चा होगी। अब मेरे पास जो लिस्ट आई है उसमें पिछले कल माननीय सदस्य जो इस विषय पर बोल चुके हैं उनमें माननीय श्री विपिन सिंह परमार जी ने 36 मिनट लिए, माननीय श्री नीरज नैय्यर ने 21 मिनट 21 सेकेंड, डॉ0 जनक राज ने 29 मिनट 23 सेकेंड, श्री पवन कुमार काजल ने 19 मिनट 24 सेकेंड और श्री राम कुमार जी ने 15 मिनट 35 सेकेंड लिए हैं। एक तो यह टाइमिंग में बहुत डिस्पैरिटी है। मेरे पास अभी रिवाइज्ड लिस्ट आ गई है। दोनों पार्टियों से लिस्ट आई है। कांग्रेस की तरफ से माननीय श्री हर्षवर्धन चौहान जी जो हमारे Parliamentary Affairs Minister हैं उन्होंने रिवाइज्ड लिस्ट में आठ आदमियों के नाम दिए हैं और बीजेपी की तरफ से चार नाम

25.08.2026/1430/DT/HK-2

हैं। साथ में बीजेपी ने भी मुझसे से आग्रह किया है कि हम चार बोलेंगे, मैं तो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता लेकिन you can request to them that they should also confine to the four members. This is the request which I have received from Shri Vinod Kumar. But this was the duty of Shri Vinod Kumar to talk to you before talking to me. But since he has not talked about all this. In any case, if you want to curtail the list ...(Interruption), please take your seat. Let me complete first. If you want to curtail the list, you are welcome to do that. This is what he wants. ...(Interruption) यह इनकी इच्छा है, माननीय श्री हर्षवर्धन चौहान जी। ...(Interruption) एक मिनट। I will give you a chance. I will give you a chance. Let the Hon'ble Minister speaks ...(Interruption) चलिए। What do you want to say? बोलिए, माननीय श्री विनोद कुमार जी। मैंने आपकी बात बोली थी की चार सदस्य हैं लेकिन किससे शुरू करना है वह मैंने डिसाइड नहीं किया।

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, लेकिन आपने नाम तो ले लिया।

अध्यक्ष : अभी मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया। अभी आठ सदस्य सत्ता पक्ष से और चार सदस्य विपक्ष से बोलने वाले हैं। कौन-कौन बोलेंगे, यह अभी मैंने नहीं बोला।

श्री विनोद कुमार : सर, आपने श्री रणधीर शर्मा जी का नाम कल ले लिया था। और हमने रिवाइज्ड लिस्ट आपको चार लोगों की दी है। अगर वहां से आठ लोगों के नाम हैं तो हमारी तरफ से भी होंगे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी कल श्री राम कुमार जी सत्ता पक्ष की ओर से लास्ट स्पीकर के रूप में बोले थे उसके बाद आज श्री रणधीर शर्मा जी ही बोलेंगे। यहीं से स्टार्ट होगा। I am not starting from this side. यह चर्चा नियम-130 के अंतर्गत हो रही है, कोई बजट पर डिबेट नहीं हो रही है। I know the procedure, rules and directions.

श्री विनोद कुमार : ठीक है सर, अगर सत्ता पक्ष से आठ सदस्य होंगे तो हमारे भी आठ सदस्य ही होंगे।

25.08.2026/1430/DT/HK-3

अध्यक्ष : आप लिस्ट दे देना फिर। अब माननीय उद्योग मंत्री जी अब आप चर्चा में भाग लेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण चर्चा है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के हर चुनाव क्षेत्र को इफैक्ट करता है। हर माननीय सदस्य यह चाहता है कि वह स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित उसके विधान सभा क्षेत्र के इश्यू इस माननीय सदन में रखे और इस सदन के माध्यम से उसके चुनाव क्षेत्र के लोग सुने कि हमारे प्रतिनिधि ने हमारे क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों या डाक्टर्ज के जो रिक्त पद हैं उस पर चर्चा की या नहीं। जो माननीय सदस्य ने नियम-130 के अंतर्गत जो विषय इस सदन में उठाया है इसमें विपक्ष के पांच सदस्य पहले लिस्टिड थे, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। मैं तो चाहता कि हमारे सत्ता पक्ष के सदस्यों के नामों की लिस्ट कम हो ताकि अगली वाली चर्चा भी हो सके। मगर हमारे विधायक

श्री एन0जी0 द्वारा जारी.....

25.08.2026/1435/वाई.के.-एन.जी./1

संसदीय कार्य मंत्री.......... जारी

लेकिन हमारे माननीय विधायक इस बात को नहीं मानें। हमारे आठ माननीय विधायकों के नाम शामिल हैं और मेरा विपक्ष से आग्रह है कि वे भी अपने आठ माननीय सदस्यों को चर्चा में शामिल करवाएं। नियम-130 के तहत रोजगार के विषय पर जो चर्चा करनी है, उसे कल आरम्भ कर देंगे। आज स्वास्थ्य के विषय पर दोनों ओर के माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात रख लेते हैं और उसके बाद माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री उस चर्चा का उत्तर दे देंगे।...(व्यवधान) सदन की कार्यवाही को बढ़ाया भी जा सकता है लेकिन वह तो अध्यक्ष महोदय के अधिकार क्षेत्र में है और उस संदर्भ में अध्यक्ष महोदय जैसा उचित समझेंगे, वे कर सकते हैं।

अध्यक्ष : ऐसा है, मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि आप (विपक्ष के माननीय सदस्यों को कहा) सुनते तो हैं नहीं और ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। मेरे पास नियम-130 का एक इश्यू है जोकि पिछले कल से चल रहा है। इसके अलावा दो और इश्यू लिस्ट में शामिल हैं। पिछले कल हमने डिसाइड किया था कि जो नियम-67 वाला इश्यू है, वह नियम-130 में डिस्कस होगा। हमने आज उसको प्रायोरिटी भी दे दी है। श्री केवल सिंह पठानिया जी का भी एक इश्यू लगा है। इस प्रकार से मेरे पास नियम-130 के तहत कुल 3 इश्यू हैं और उनमें से एक चल रहा है। इस विषय पर यदि आठ माननीय सदस्य सत्तापक्ष से बोलेंगे और आठ माननीय सदस्य विपक्ष से बोलेंगे, यानी कुल 16 माननीय सदस्य बोलेंगे। 16 माननीय सदस्यों के बोलने का मतलब यह है कि यदि एक माननीय सदस्य पांच से सात मिनट भी बोलेगा, तो $16 \times 5 = 80$ मिनट हो जाएंगे।

25.08.2026/1435/वाई.के.-एन.जी./2

हमारे पास पांच बजे तक टाइम निर्धारित है और उसके बाद समय को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन आप सबकी राय के मुताबिक ही किया जाएगा। मेरा आग्रह यह है कि विषय के ऊपर ही आप अपने आपको सीमित करें। आप उसी विषय के ऊपर बोलें, क्योंकि yesterday, what I had noticed is that while speaking on the issue, the member had travelled beyond the issue also and that is a part of the proceedings also. Yet, I am going through that proceedings. That will not be a part of the proceedings. In any case, one who has travelled beyond the issue also? This is what I wanted to clarify. क्योंकि इसके बाद माननीय सदस्य श्री संजय रत्न जी ऐज ए सभापति टेक ओवर करेंगे। I will request you to be very particular into this. Time allotted is not more than 5 to 10 minutes. Now, I will request the Hon'ble Member from the BJP side, Shri Randhir Sharma, to further take part in the deliberations.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री विपिन सिंह परमार जी ने नियम-130 के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के संबंध में चर्चा लाई है और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग जनता से सीधे रूप से जुड़ा हुआ विभाग है। हर व्यक्ति को इस विभाग में कभी-न-कभी, किसी-न-किसी मौके पर जाना पड़ता है। इसलिए इस विभाग की कमियां उजागर करना और स्वास्थ्य विभाग में क्या सुधार हो सके, ऐसे सुझाव देना, यह विपक्ष का दायित्व है और जिसे हम यहां पर निभा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण चर्चा है और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि विषय के अंतर्गत ही सबको बोलना चाहिए। कोई सदस्य अगर विषय से भटक जाए तो आसन से अपेक्षा की जाती है कि उसे विषय पर लाया जाए या सदन के नेता से उम्मीद की जाती है कि वे चर्चा को विषय पर लाएं।

अध्यक्ष महोदय, दुःख का विषय यह है कि पिछले कल जब सभी माननीय सदस्य स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा कर रहे थे और स्वास्थ्य विभाग पर ही सारे मुद्दे केंद्रित थे तो

25.08.2026/1435/वाई.के.-एन.जी./3

माननीय मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया। मुख्य मंत्री जी हस्तक्षेप करते हुए स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर अन्य मुद्दों पर चले गए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चलो छोड़ो, कल उसका जवाब हो गया।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, उस समय सभापति के नाते आसन पर बैठे आदरणीय श्री संजय रत्न जी मुस्कुराते रहे। इसलिए आप मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं उनकी एक-दो बातों का जवाब जरूर देना चाहूंगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब तो दे दिया था। आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने जवाब दे दिया था और उसके बाद मुझे कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा था।

श्री रणधीर शर्मा : नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा करते-करते राज्यसभा के सदस्य श्री हर्ष महाजन, विधायक श्री सुधीर शर्मा जी आदि के बारे में विजिलेंस जांच की चर्चा की और मुझे लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री आजकल इनके फोबिया से ग्रस्त हैं। मुख्य मंत्री जी को दिन में तो सपने आते ही हैं लेकिन रात को भी इनके ही सपने आते हैं। मुख्य मंत्री जी ने विजिलेंस जांच करते-करते कहा कि मेरे पास तो वर्ष 2017 की चार्जशीट आई और उस चार्चशीट में बीजेपी वालों ने श्री सुधीर शर्मा जी और श्री राजेन्द्र राणा जी पर आरोप लगाए तथा मैंने उसकी जांच करवा दी। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं

अध्यक्ष--------श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

25.08.2026/1440/YK/PB/1

श्री रणधीर शर्मा ...जारी

Speaker : I think this cannot be a part of the debate. ...(Interruption) This cannot be a part of the debate. In any case, if anything has come on record as such, because I was not on the Chair at that time, so I will peruse the record and I will remove it from the record. So it's better you should confine yourself and your discussion to the issue. Then, I will peruse the record.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे पास उस चार्जशीट की प्रति है। उसमें 32 कांग्रेस नेताओं के नाम हैं। उन नेताओं में से जो आज दुनिया में नहीं है और जो आज सदन में नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा परंतु इस चार्जशीट में मुख्य मंत्री जी आपका भी नाम है। उप-मुख्य मंत्री जी, आपका भी नाम है। आप उस समय उद्योग मंत्री थे और आपकी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री विनय कुमार जी का भी नाम है। यदि आप चार्जशीट की जांच करवाना चाहते है तो बाकी को छोड़िए आप इन तीनों की जांच करवा लीजिए। मैं तब मानूंगा कि आप इस मामले की जांच करवा रहे है। फिर आप कहते है कि हम बदले की भावना से काम नहीं करते। 32 नेताओं के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं और आप पिक एंड चूज करके केवल दो की ही जांच करवाते है। यह प्रतिशोध की राजनीति है जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम कोई बदला नहीं लेंगे लेकिन बदला लेने वाला बैठा है। प्रकृति का नियम है कि पेड़ बोए बबूल के आम कहां से होए। मुख्य मंत्री जी, आप ये बबूल के पेड़ बो रहे हैं इसलिए आपको आम नहीं मिलेंगे, आपको कांटे ही मिलेंगे। यह मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं।

Speaker : Come to the issue now.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अब मैं मुद्दे पर आता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे साथियों ने स्वास्थ्य विभाग की चर्चा की कि आज पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 और सिविल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं हैं। आप डॉक्टर उपलब्ध करवाइए। पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 और सिविल हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं हैं। इन संस्थानों में पैरासिटामोल तक नहीं मिलती और इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। हम सदन में इन सब चीजों को लेकर चर्चा कर

25.08.2026/1440/YK/PB/2

रहे थे लेकिन मुख्य मंत्री जी कहने लगे कि हमने रोबोटिक सर्जरी दे दी। स्वास्थ्य विभाग के दो विभाग हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा। हम स्वास्थ्य विभाग की चर्चा कर रहे है और मुख्य मंत्री जी रोबोटिक सर्जरी की बात करते है। हमें आवश्यकता है कि सी0एच0सी0, सिविल हॉस्पिटल और रीजनल हॉस्पिटल में एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और एम0आर0आई0 की सुविधा हो परंतु अस्पतालों में ये मशीनें नहीं हैं। यदि मशीनें हैं तो रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है। अभी मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 28 करोड़ रुपये की एम0आर0आई0 मशीन आए हुए दो महीने बीत गए है। इस पर अखबार में लिखा है कि "28 करोड़ रुपये की एम0आर0आई0 मशीन बनी शोपीस।" यह मुख्य मंत्री जी का जिला है और यहां भी बातें हवा में हो रही है। हम रोबोटिक सर्जरी के विरोधी नहीं हैं लेकिन आप आवश्यकता के अनुसार चलिए। स्वास्थ्य संस्थानों में खांसी-जुकाम की दवाई नहीं है और आप रोबोटिक सर्जरी के सपने दिखा रहे है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले कल हमने कोई आरोप नहीं लगाया कि रोबोटिक सर्जरी में कोई भ्रष्टाचार हुआ है। हमने ऐसा आरोप कहीं नहीं लगाया लेकिन मुख्य मंत्री जी अपने आप सफाइयां दे रहे है कि कोई साबित कर दे कि किसी ने एक रुपया भी खाया हो, हमने मशीनें उस कंपनी से ली है। अरे, हम इस बात को कब कह रहे है? इसका मतलब यह है कि आपके मन में बेईमानी है। (***)

Speaker : (***)is unparliamentary word.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष **जी**, आप इस पंक्ति को ही कार्यवाही से हटा दीजिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी अपने आप स्पष्टीकरण

देकर यह साबित करने का प्रयास कर रहे है कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। आदरणीय नीरज भारती जी ने जिन पांच (***) की बात की थी, मुझे विश्वास है कि उनमें से एक (***) रोबोटिक सर्जरी की मशीनें देने वाली कंपनियों की थी। मुझे मुख्य मंत्री जी के बयानों से ऐसा ही लगता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर आगे चर्चा करना चाहता हूं।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा जी, please take your seats. संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

25.08.2026/1445/ए0जी0/ए0पी0-01

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने आदेश दिया था कि स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा करें तो स्वास्थ्य के विषय पर ही चर्चा होनी चाहिए। आप ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, जिनका कोई तथ्य नहीं है। आप सरकार और मुख्य मंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं। आपके पास इसका क्या प्रमाण है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर इन्होंने सदन का माहौल खराब करना चाहते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। आपने निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य के विषय पर ही चर्चा करें और अपने आपको स्वास्थ्य तक सीमित रखें। अध्यक्ष महोदय, यह जो आरोप लगा रहे है इसे कार्रवाई से बाहर निकाला जाए।

Speaker: This will be removed from the record.

श्री रणधीर शर्मा : मैंने बोला की मुख्य मंत्री जी के बयानों से ऐसा लग रहा है क्योंकि वे सफाई दे रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। वे सफाई दे रहे हैं।

Speaker: This is not a discussion on corruption. This is a discussion on the health facilities - how to improve the health facilities. If any part of your speech will be regarding the corruption, I will not allow that.

श्री रणधीर शर्मा : सर, भ्रष्टाचार सर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भ्रष्टाचार तो हो रहा है।

Speaker: You bring another discussion under rule.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। यह पत्र लिखकर दिया गया कि कंपनी एम0आर0पी0 के रेट से दस-दस गुना ज्यादा पैसा लोगों से वसूल रही है। सरकार ने क्या कार्रवाई की? अगर यह भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है?

अध्यक्ष : इस दस्तावेज को सदन में ले करें।

25.08.2026/1445/ए0जी0/ए0पी0-02

श्री रणधीर शर्मा : जी सर, रख देंगे। माननीय सदस्य श्री पवन काजल जी ने टांडा मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के कितने मुद्दे उठाए हैं। क्या उनकी कोई जांच हुई? मुख्य मंत्री जी के बारे में सोशल मीडिया पर बातें आती रहती हैं। सोशल मीडिया की भी जवाबदेही है। अगर उसमें गलत खबर आती है तो उस पर भी कार्रवाई होती है। अगर सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखती है तो चाहे बात सोशल मीडिया में आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए, प्रिंट मीडिया में आए या कोई व्यक्ति कहे, सरकार को उसकी जांच करनी चाहिए। इसे ही जीरो टॉलरेंस कहते हैं। आप घोटाले पर घोटाले करें और यहां हिमाचल प्रदेश का नाम बदनाम हो गया है। कभी हिमाचल प्रदेश फार्मास्यूटिकल

हब के रूप में जाना जाता था। आज हमें हर महीने खबर पढ़ने को मिलती है कि दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं। किस फर्म पर कार्रवाई हुई? कौन इन फर्मों को बचाता है? उन फर्मों में घटिया दवाइयाँ क्यों बन रही हैं? क्या किसी एक फर्म को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है? आप भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? आप हिमकेयर में घोटाले की बात करते हैं। अगर घोटाला हुआ है तो उसकी जांच करवाइए, आप हिमकेयर को बंद कर रहे हैं। आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हिमकेयर की सुविधा को बंद कर दिया है, अब आप ही बताए कि लोग कहां जाएं? मैंने अभी इसी अखबार में पढ़ा कि हमीरपुर में जब एम0आर0आई0 की सुविधा नहीं मिली तो लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर तीस-तीस हजार रुपये खर्च करने पड़े। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हिमकेयर की सुविधा होती तो गरीब लोगों को फायदा होता। आज अभी खबर पढ़ रहा था कि हिमकेयर की सुविधा न मिलने से एक मरीज की मृत्यु हो गई। अभी-अभी मुझे यहां से यह जानकारी मिली है। ऐसी हालत है और आपकी हालत क्या है? हिमकेयर में करीब चार सौ करोड़ रुपये की देनदारी है। आज आई0जी0एम0सी0, जिसकी चर्चा मुख्य मंत्री जी कर रहे हैं कि यह सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है। उसमें हिमकेयर की कितनी देनदारी है? अगर स्वास्थ्य मंत्री जी बताते तो ज्यादा अच्छा होता, परंतु ये बताएंगे नहीं। मैं इन्हें जरूर बताना चाहता हूं कि अभी आपने आई0जी0एम0सी0 का 80 करोड़ रुपये हिमकेयर का देना है। टांडा का 72 करोड़ रुपये देना है। एम्स का 60 करोड़ रुपये देना है और पी0जी0आई0 का 20 करोड़ रुपये देना है। आप यह पैसा नहीं

25.08.2026/1445/ए0जी0/ए0पी0-03

दे रहे हैं, उसका परिणाम क्या हो रहा है? अगर मरीज एडमिट है और जो वेंडर है, उसकी पेमेंट नहीं हुई है तो वह आगे जो भी उसकी जरूरत है, चाहे दवाई की हो या किसी उपकरण की, वह उपलब्ध नहीं कराता। क्योंकि उसकी पेमेंट नहीं हो रही है। आज हिमकेयर के साथ-साथ आपने आयुष्मान का करीब दो सौ करोड़ रुपये स्टेट शेयर देना बाकी है। आपने सहारा योजना को भी बंद कर दिया है। आप उस परिवार से पूछिए,

जिसका एक सदस्य शय्याग्रस्त हो जाता है, उसका पूरा परिवार बंध जाता है। एक सदस्य चौबीस घंटे उसकी सेवा में लग जाता है। माननीय श्री जय राम जी ने उपकार किया था, तीन हजार रुपये की पेंशन लाई थी।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

25.08.2026/1450/AT/AG/01

श्री रणधीर शर्मा जारी....

एक सदस्य चौबीस घंटे उसकी सेवा में लगता है। श्री जय राम जी ने उपकार किया था, तीन हजार की पेंशन लाई थी, आपने वह भी बंद कर दी। यही सरकार की संवेदनशीलता है? यही सरकार का गरीबों के लिए किया जाने वाला काम है? नई योजना तो क्या चलानी, आपने पुरानी चली हुई योजनाओं को बंद कर दिया और इस तरह से, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आपने वादा किया था कि मुद्दा कल आएगा, हम अब भर्तियाँ रेगुलर करेंगे। परंतु स्वास्थ्य विभाग में हालात क्या हैं? स्टाफ नर्सें और फार्मेसिस्ट आउटसोर्स पर भर्ती हो रहे हैं। स्वीपर होते हैं, सिक्योरिटी मैन होते हैं, बात समझ आती है स्टाफ नर्सें और फार्मेसिस्ट भी आउटसोर्स पर भर्ती हो रहे हैं। आउटसोर्स पर जो भर्ती होती है, उसमें न मेरिट है, न रिजर्वेशन। आप मेरिट की अनदेखी करके स्टाफ नर्सों की भर्ती कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की हालत क्या होगी? और आउटसोर्स में भी करप्शन हो रही है। मुख्य मंत्री जी के मित्रों की आउटसोर्स एजेंसियाँ लाखों रुपये रिश्वत लेकर नर्सों को आउटसोर्स पर भर्ती कर रही हैं। कितनी बार इस सदन में यह मुद्दा उठाया? क्या कभी कोई जांच हुई? क्या कभी कोई कार्यवाही हुई? रेगुलर भर्ती नहीं हो रही। यहां तो कहा जा रहा है कि हमने 65 प्रतिशत रिक्तियां भरीं, परंतु उसमें 90 प्रतिशत आउटसोर्स है, जिसको आप कह रहे हैं कि हम रेगुलर नहीं करेंगे। स्वास्थ्य विभाग किस ओर जा रहा है, देखिए आप उसको।

राम कुमार जी यहां बैठे है इन्होंने यहां पर बड़ी-बड़ी चर्चा की गई।, संस्थान बंद कर दिए। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने कोई संस्थान बंद नहीं किया, परंतु इस सरकार ने दो हजार से ऊपर संस्थान बंद किए हैं। उसमें से 257 संस्थान

स्वास्थ्य विभाग के हैं, जिनमें पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 भी हैं। 257 संस्थान बंद करके आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरु हुआ है ...(व्यवधान)

अध्यक्षः तेरह मिनट हो चुके हैं।

श्री रणधीर शर्मा : आप कल बीस-बीस मिनट बोले हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यहां जो बात बोली जाए, तथ्यों पर बोली जाए। हां, नीरज मेहयर जी कल

25.08.2026/1450/AT/AG/02

बोले, तथ्यों पर बोले। पर उन्होंने भी क्या कहा? केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही। हमें गर्व है कि नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर हैं, परंतु वह हिमाचल का ध्यान नहीं रख रहे।

मैं अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह जो एम्स है, यह किसकी देन है? यह एम्स किसकी देन है?...(व्यवधान) आय, हाय, हाय, हाय, हाय, हाय। मारे जावां। सर, कहीं तो सच्चाई बोलो। मैं इतिहास की हर बात जानता हूं। वर्ष 2014 में देश के ग्यारह प्रदेशों को एम्स मिले। हमारे सांसदों ने पत्र लिखा, तो ग्यारह प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश का नाम आया। हमने बात की। अपनी जमीन, जो वहां एनिमल हसबेंडरी के नाम थी, उसे स्वास्थ्य विभाग के नाम कराने के बाद सरकार को दिया। वह स्वास्थ्य विभाग के नाम हुई। केंद्र में नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री बने, तो बिलासपुर के कोठीपुरा में एम्स हॉस्पिटल खुला। आपकी हालत क्या है?...(व्यवधान) भवानी जी, सुनिए। आपने तो उस एम्स के लिए हमारी सरकार द्वारा खोली गई पुलिस चौकी को भी बंद कर दिया था। आप उस एम्स के लिए 32 के0वी0 का सब-स्टेशन नहीं बना पाए, चौथा साल खत्म हो रहा है। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के बच्चों के लिए सेंटर ने सेंट्रल स्कूल दिया है, चार साल में आप उसके लिए जमीन नहीं दे पाए। आप एम्स का क्रेडिट ले रहे हो। आपके मेडिकल कॉलेज किसकी देन हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा और बताना चाहता हूं कि किस तरह से यह सरकार केंद्र के पैसे को खर्च नहीं कर रही है। कोई अधिकार नहीं है आपको केंद्र से पैसा

मांगने का। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कह रहा हूं...(व्यवधान) क्योंकि आप खर्च नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं है, क्योंकि आप खर्च नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं है कि आप खर्च नहीं कर रहे हैं। अरे भैया...(व्यवधान)

अध्यक्षः रणधीर जी, प्लीज़।

श्री रणधीर शर्मा : सर, मैं जब बोलूंगा, आप मान जाओगे कि नहीं?...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पंद्रहवें वित्त आयोग में स्वास्थ्य विभाग को 521 करोड़ रुपये मिले। स्वास्थ्य मंत्री जी, कितने खर्च हुए? अभी आधी धनराशि भी खर्च नहीं हुई है।

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी ......

25.08.2026/1455/AV/AS/1

श्री रणधीर शर्मा जारी

आपको और पैसा मांगने का क्या अधिकार है? आपको स्वास्थ्य विभाग से पी0एम0 ए0बी0एच0आई0एम0 योजना के अंतर्गत 73 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां दी गईं परंतु आप अभी तक एक को भी नहीं चला सके। आपकी इस प्रकार की हालत है। आपको 12 इंटीग्रेटिड हैल्थ लैब्ज दी गईं उसमें से केवल एक चली है। स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आपको केंद्र से 15 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स मिले उसमें से भी एक ही चला। उसमें से एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक तो हमारे नैना देवीजी के घवांडल सिविल होस्पिटल के लिए भी आया है तथा 31 करोड़ रुपये की राशि भी आई। उसको आए अढ़ाई वर्ष का समय हो गया। मगर न तो क्रिटिकल केयर ब्लॉक बना और ऊपर से आप लोग 31 करोड़ रुपये भी (***) गए। फिर आप बोलते हैं कि हमें पैसा दीजिए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पैसा (***)नहीं गए और (***) शब्द असंसदीय है। आप इसका पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे सदन के माहौल में गर्मी पैदा हो ऐसा शब्द क्यों इस्तेमाल करना?

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार उस 31 करोड़ रुपये की राशि को खर्च ही नहीं कर पाई।

अध्यक्ष : हां, आप ऐसा बोलिए।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो सरकार केंद्र से स्वीकृत संस्थान न खोल सके, उससे निकम्मी कोई और सरकार नहीं हो सकती। अब हालात ऐसे हैं, ...(व्यवधान)

Speaker : As and when Hon'ble Member Shri Bhawani Pathania will come here then he will notify the word Nikamma as unparliamentary word, I am not that. Though he belongs to my clan but yet.

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

25.08.2026/1455/AV/AS/2

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हालात ऐसे हैं कि आज नियुक्तियां करने की बजाय पद समाप्त किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नये संस्थान और पोस्ट्स की जरूरत है परंतु इस सरकार द्वारा उसके विपरीत 257 संस्थान बंद करने के साथ-साथ हजारों पोस्ट्स को भी समाप्त किया जा रहा है। आप पोस्ट्स का विषय भी छोड़िए, इन्होंने तो मेल हैल्थ वर्कर्ज और फिमेल हैल्थ वर्कर्ज का कैडर ही समाप्त कर दिया। हम तो सुनते थे इलाज से परहेज अच्छा है और उसके लिए ही हैल्थ सब-सेंटर्ज खोले गए थे तथा उसी उद्देश्य हेतु उनमें मेल एण्ड फिमेल हैल्थ वर्कर्ज नियुक्त किए गए थे। परंतु आपने उस कैडर को ही समाप्त कर दिया। आप स्वास्थ्य विभाग में सुधार की बात करते हैं।

Speaker : It was decided much before.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अब मैं नशा मुक्ति केंद्र की बात करना चाहूंगा जोकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। नशे के कारण प्रदेश का युवा वर्ग भटक रहा है और उनका भविष्य अधर में लटक रहा है। वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते ही अपने पहले बजट में कहा कि यह सरकार स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कण्डाघाट में नशा मुक्ति केंद्र खोलेगी। इस सरकार को सत्ता में आए हुए चार वर्ष हो चुके हैं परंतु वह केंद्र अभी तक नहीं बना। इस सरकार ने दो वर्ष पहले फिर से कहा कि वह केंद्र अब सिरमौर में बनाया जाएगा। मगर वह भी नहीं बना। फिर आप स्कूल्ज के बच्चों को दौड़ाकर बोलते हैं कि हम प्रदेश में नशा मुक्ति कर देंगे। आपसे एक नशा मुक्ति केंद्र नहीं खोला जा रहा। आपने कहा कि प्रत्येक जिला में एक-एक खोलेंगे। मगर आपने कहीं पर नहीं खोले। हमने कहा कुछ मत कीजिए। आप रीजनल होस्पिटल में चार-चार कमरे इस उद्देश्य हेतु रख दीजिए और उनमें एक-एक मनोरोग विशेषज्ञ की पोस्ट क्रिएट कर दीजिए परंतु आपसे वह भी नहीं हो पाया। इससे तो यह प्रतीत होता है कि नशा मुक्ति आपके लिए केवल एक नारा है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाए और न ही कुछ करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के बारे में भी चर्चा की जाती है।

Speaker : Wind-up now.

25.08.2026/1455/AV/AS/3

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रिस्ट्रिक्ट किया इसलिए मैं केवल अपने विधान सभा क्षेत्र की ही बात करूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में घवांडल सिविल होस्पिटल को आपने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया। परंतु चौथा वर्ष खत्म होने को आ गया है, जो भवन पिछली सरकार के कार्यकाल में बन रहा था वह भवन अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमारी सरकार ने भवन बनाने के लिए बजट दिया था, इनके पास पैसा नहीं था। उसके लिए टेम्पल ट्रस्ट से पैसा मांगा गया। हमने उसका विरोध नहीं किया और टेम्पल ट्रस्ट ने 5-5 करके पूरे 10 करोड़ रुपये दिए परंतु वह भवन तब भी पूरा नहीं हुआ। मैंने पिछले सत्र के दौरान भी कहा था कि उसमें 4-5 करोड़ रुपये और लगने हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी, आप लगा

दीजिए या फिर मंदिर ट्रस्ट से ले लीजिए। परंतु उस पर उप-मुख्य मंत्री जी ने हाथ खड़े कर दिए कि हाई कोर्ट का निर्णय है कि मंदिर ट्रस्ट से पैसे नहीं दे सकते। अब मंत्री जी कहते हैं कि पैसे आ गए हैं परंतु अभी तक भी उस भवन का आगे का काम शुरू नहीं हुआ। उसमें 10 डॉक्टर्ज के पद सैंक्शन्ड हैं परंतु वर्तमान में 10 में से 7 पद खाली हैं।

एन0 एस0 द्वारा जारी-

25-8-2026/1500/NS-AS/1

श्री रणधीर शर्मा -----जारी

आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की क्या हालत है? श्री नैना देवीजी में लाखों श्रद्धालु आते हैं। वहां हर शनिवार व रविवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और नवरात्रों में तो इनकी संख्या लाखों में होती है तथा वहां आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में 10 में से 7 डॉक्टरों के पद खाली हैं। पैरा मेडिकल स्टाफ के कुल 61 पद हैं जिनमें से 33 पद खाली हैं। यह स्वास्थ्य संस्थान की हालत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की चर्चा करूंगा। आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने अपनी सरकार के समय हमारी पी0एच0सी0, भाखड़ा बॉर्डर में हैं और उसको अपग्रेड कर सी0एच0सी0 बनाया। पी0एच0सी0 मलोखर, अवस्थी जी के विधान सभा क्षेत्र के साथ लगती है, उसे भी सी0एच0सी0 बनाया गया और इनकी कांस्टिच्यूएंसी के लोग भी वहां आते हैं। परन्तु सरकार बनने के बाद दोनों संस्थानों को डीनोटिफाई कर सी0एच0सी0 से पी0एच0सी0 कर दिया गया। मैं तो इसके लिए बहुत बोला परन्तु अवस्थी जी चुप रहे क्योंकि इनकी मजबूरी रही है। अब हालत यह है कि मलोखर में अभी एक भी डॉक्टर नहीं है। ...(व्यवधान) आप झूठ मत बोलिए। आज तक मलोखर में कोई डॉक्टर नहीं है। स्वारघाट हमारा तहसील हैडक्वार्टर है और एस0डी0एम0 वहां बैठते हैं। वहां सी0एच0सी0 है परन्तु वहां कोई भी डॉक्टर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में डॉक्टरों के 13 पद खाली हैं। सिविल हॉस्पिटल, मारकंडेय में चार पद, सिविल हॉस्पिटल, घवांडल में सात पद, सी0एच0सी0, स्वारघाट में एक पद तथा पी0एच0सी0, मलोखर में एक पद खाली है। इस प्रकार कुल 13 डॉक्टरों के पद रिक्त हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बड़ी पेशेंस से सुनते हैं परन्तु केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए कुछ काम भी करना होगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिविल हॉस्पिटल, घवांडल के भवन निर्माण कार्य को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए, यह मेरी पहली मांग है।...(व्यवधान) एक तो भवन निर्माण का कार्य पूरा किया जाए। दूसरा, डॉक्टरों के 13 रिक्त पद हैं जिनमें सिविल हॉस्पिटल, घवांडल में सात पद, सिविल हॉस्पिटल, मारकंडेय में चार, सी0एच0सी0, स्वारघाट में एक तथा पी0एच0सी0, मलोखर में एक पद शामिल है। इन पदों को तुरंत प्रभाव से भरा जाए।

25-8-2026/1500/NS-AS/2

मेरी कांस्टिच्यूएंसी में अन्य 294 पद हैं जिनमें से 161 पद खाली हैं और उन पदों को भी भरा जाए। हमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक की सौगात केंद्र से मिली है उसे तुरंत प्रभाव से शुरू कर संचालित किया जाए। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

25-8-2026/1500/NS-AS/3

अध्यक्ष : अब माननीय राजस्व मंत्री जी चर्चा में भाग लेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी द्वारा इस विषय पर जो चर्चा लाई गई है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो प्रस्ताव यहां पर लाए हैं, वे स्वयं पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं और इन्हें बहुत बेहतर तरीके से पता है कि उस समय

क्या हालत थी तथा आज की तारीख में उसमें कितना सुधार हुआ है। वैसे तो यह चर्चा सत्ता पक्ष की तरफ से आनी चाहिए थी क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में इतना अच्छा काम हुआ है जिसका हमें स्वयं व्याख्यान करना चाहिए था। परंतु आपने इस विषय को यहां लाया और मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने हमें भी स्वास्थ्य विभाग तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश के अंदर पिछले साढ़े तीन वर्षों में हुए कार्यों को बताने का मौका दिया है। अभी यहां पर मेरे से पूर्व माननीय रणधीर शर्मा जी ने कई विषय रखे हैं। मैं सबसे पहले एम्स से शुरू करता हूं। अब ये एम्स का बार-बार ऐसा गुणगान करते हैं जैसे कि इनके समय में ये इनके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से लेकर आए थे। एम्स का सारे-का-सारा काम डॉ0 मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके रहते हुए हुआ है। यह वर्ष 2012 में सैंक्शन हुआ है। ...(व्यवधान)

Speaker : No interruption please. ...(interruption) ठीक है , आपने बोल दिया। ...(व्यवधान)

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

25.08.2026/1505/RKS/DC-1

राजस्व मंत्री... जारी

...(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दें।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने इन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। हमारी विधान सभा के नियम भी कहते हैं कि जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो दूसरे सदस्य को बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। यह नियमों का उल्लंघन है और इससे इनके व्यक्तित्व पर भी लांछन लगता है। आप इस

माननीय सदन को फिश मार्किट कैसे बना सकते हैं? आप अपनी बात कहकर हमारी बात कहने से कैसे रोक सकते हैं? मुझे भी उतना ही बोलने का अधिकार है जितना आपको है। अतः यह गलत तरीका है और ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हिमाचल प्रदेश विधान सभा के पूरे इतिहास को देखें तो जिस प्रकार से अबकी बार बीच-बीच में इंटरप्ट किया जा रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। यह गलत परंपरा है। फिर संविधान कैसे चलेगा और विधान सभा कैसे चलेगी?

अध्यक्ष : मैंने इस संबंध में समय-समय पर सभी माननीय सदस्यों से निवेदन किया है कि जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो उसे बीच में इंटरप्ट न किया जाए। यदि किसी सदस्य का कोई इश्यू है तो उसके लिए मैं बाद में समय दूंगा।

राजस्व मंत्री : सर, हम कहीं इंटरप्ट नहीं करते हैं। मेरा भी संवैधानिक अधिकार है, उसे आप कैसे रोक सकते हैं? इसलिए मैं यह शुरू में ही कह देना चाहता हूं ताकि बाद में यह बात रह न जाए।

झूठ बोलकर लोग शर्मिंदा नहीं होते हैं आजकल,

झूठ बोलकर बेगुनाहों को गुनाहगार बना देते हैं।

यह बात इन पर लागू होती है। ये इसी प्रकार की बातें करते हैं। ...(व्यवधान) कुछ चीजों का शुरू में ही मज़ा आता है और कुछ का स्वाद चखने तथा समझने के बाद आता है। जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, मुझे भी इस माननीय सदन में काफी अरसा हो गया है। कई साथी 6-7 बार के सदस्य रह चुके हैं।

25.08.2026/1505/RKS/DC-2

अध्यक्ष : यहां पर 6 बार के ही सदस्य हैं और आप भी 6 बार के ही सदस्य हैं।

राजस्व मंत्री : सर, मैं पांच बार का सदस्य हूं।

अध्यक्ष : अगली बार आप 6 बार के सदस्य हो जाएंगे और इसके लिए हमने आपको आज ही आशीर्वाद दे दिया है।

राजस्व मंत्री : सर, आपका धन्यवाद। स्वास्थ्य के विषय पर सदन में हमेशा चर्चा होती रही है। पहले यह कहा जाता था कि डॉक्टर नहीं हैं, नर्सिज नहीं हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में अनेक कमियां हैं। किंतु यह पहला अवसर है और आज आपने प्रश्न काल में भी देखा होगा कि यदि ऐसी कोई गंभीर समस्या होती तो माननीय सदस्य नियम-62 के अंतर्गत विषय लाते। कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं आया, कोई प्रश्न नहीं आया और न ही कोई अन्य मामला आया। इसका अर्थ यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ शत-प्रतिशत ठीक हो गया है किंतु मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने एक नई सोच पैदा की है। पहली बार किसी मुख्य मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को इतने गहरे स्तर पर देखा है कि आज इस क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन आ रहा है। अभी रोबोटिक सर्जरी की बात हो रही है लेकिन उसका भी मज़ाक बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि जब देश के प्रधान मंत्री स्वर्गीय भारत रत्न श्री राजीव गांधी थे तब उन्होंने कंप्यूटर युग की शुरुआत की थी। उस समय यही लोग कहते थे कि कंप्यूटर आने से नौकरियां समाप्त हो जाएंगी और देश बर्बाद हो जाएगा। आज इनके प्रधान मंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं जबकि डिजिटल इंडिया बना ही नहीं है। यह जो आज रोबोटिक सर्जरी आई है वह एक दूरदर्शी सोच का परिणाम है। यह कार्य श्री जय राम ठाकुर जी भी कर सकते थे। ये डबल इंजन सरकार में थे। इन्हें रोबोटिक सर्जरी शुरू करने से किसने रोका था किंतु इनकी सोच उस दिशा में नहीं थी। ये केवल अपने तक सीमित रहे। ये सिर्फ अपने क्षेत्र में हैलीपैड और सड़कें बनाते रहे। ठीक है, सड़कें बननी चाहिए। ...(व्यवधान) श्री विनोद कुमार जी ये होर्टिकल्चर कॉलेज को भी अपने विधान सभा क्षेत्र में ले गए थे। यदि ये चाहते तो वह कॉलेज आपके क्षेत्र में भी बन सकता था और वहां बेहतर स्थान उपलब्ध था। हमने उसे वहां स्थापित कर दिया है इसके लिए आप हमारा धन्यवाद कीजिए। आज आपके क्षेत्र के बच्चे बहुत खुश हैं और कहते हैं कि वहां सभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। इनकी सोच केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित रही। इनकी सोच तंबुओं तक ही सीमित रही। इन्होंने इन्वेस्टर मीट के

25.08.2026/1505/RKS/DC-3

नाम पर 20-20 करोड़ रुपये के तम्बू गाड़ दिए लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं आया। इनका चाल-चलन, चरित्र डबल स्टेंडर्ड का है। ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। यदि हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो क्या किसने कभी सोचा था कि आई0जी0एम0सी0 की इमरजेंसी में आज इतनी बेहतर व्यवस्था उपलब्ध होगी। वहां यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी डॉक्टर आठ घंटे से अधिक ड्यूटी नहीं देगा।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

25.08.2026/1510/बी.एस./डी.सी.-1

राजस्व मंत्री जारी...

इतनी बढ़िया व्यवस्था की गई है। एक डॉक्टर आठ घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं देगा और उसके बाद अगला डॉक्टर आएगा। पहले इमरजेंसी में यहां से पेशेंट को आई0जी0एम0सी0 भेजते थे और पेशेंट बाहर पड़ा रहता था। आज इतनी बढ़िया इमरजेंसी का सिस्टम बनाया गया है जहां आपको लगातार डॉक्टर्स मिलेंगे। आपको बेड्स खाली मिलेंगे और सारे वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं।

क्या यह किसी की सोच थी? क्या कभी इन्होंने इस बात के बारे में सोचा था? किसी ने नहीं सोचा कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विस और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को अलग करना चाहिए। यह व्यवस्था हमारे मुख्य मंत्री की सोच के कारण हुई है। इसी सोच के कारण आज मेडिकल कॉलेजों में बेहतर शिक्षा दी जा रही है।

पहले मेडिकल कॉलेजों में क्या होता था? अब जैसे चम्बा मेडिकल कॉलेज को इंडियन मेडिकल काउंसिल से अधिकारी चेक करने के लिए आएंगे तो शिमला से कुछ प्रोफेसर्स को जबरदस्ती उस दिन के लिए वहां भेजा जाता था। जब चम्बा का काम खत्म हो गया और नाहन की बारी आई तो उन्हीं प्रोफेसर्स को उठाकर वहां दिखा दिया जाता था। यही काम डबल इंजन की सरकार करती रही।

आज की तारीख में जो एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं उनको डिजिग्नेट करके 100 से ज्यादा प्रोफेसर्स मेडिकल कॉलेजों को दिए गए हैं। क्या इन्होंने कभी ऐसा सोचा था? ये तो केवल पी0पी0ई0 किट घोटाले में पड़े रहे। कोरोना जैसे संकट के समय भी इनको शर्म नहीं आई। उसमें भी पैसा खा गए। 10 रुपये का सैनिटाइजर 250 रुपये में बेच गए। क्या कारण था कि उस समय के इनके प्रदेश अध्यक्ष को रिजाइन करना पड़ा? अगर वह डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे तो शक की सुई उन्हीं पर क्यों थी? उनका दामाद और उनकी बेटी इसमें स्कैंडल में शामिल थे। ये ऐसे लोग हैं जो मुसीबत के समय अवसर ढूंढते हैं।

इन्होंने कारगिल को भी नहीं छोड़ा। कारगिल में हमारे जवान शहीद हुए और इन्होंने उनके ताबूत के पैसे खाए। उनके जूतों के पैसे खाए। क्या यह झूठ है? क्या यह गलत है? यह गलत है क्या?

25.08.2026/1510/बी.एस./डी.सी.-2

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कृपया स्वास्थ्य के विषय पर ही चर्चा करें। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से भी अग्रह करूंगा कि आप भी विषय से बाहर न बोलें।

राजस्व मंत्री : आदरणीय रणधीर शर्मा जी जब वहां से बोल रहे थे तो इन्होंने भी बहुत कुछ कहा है। कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही सब्जेक्ट में बोलेंगे कुछ-न-कुछ बीच में नमक-मिर्च तो डालना पड़ेगा तभी जाकर इनको भी कुछ मिर्ची लगती है नहीं तो कैसे काम चलेगा?

सर, मैं कह रहा था कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मैं डबल इंजन की सरकार के समय की बात करता हूं। मैं अपने जनजातीय क्षेत्रों की बात करता हूं। हमारा पांगी, किलाड़ और लाहौल-स्पीति तथा भरमौर का क्षेत्र था। वहां के मरीजों का हाल यह था कि किसी को छोटी-सी पट्टी लगाने के लिए भी डॉक्टर नहीं था।

आज हमारे जनजातीय इलाकों में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। आज सारे मेजर ऑपरेशंस खासकर मेरे जिला किन्नौर के अंदर परफॉर्म किए जा रहे हैं और हमारे

लोगों को बार-बार ढाई सौ किलोमीटर दूर शिमला आने की नौबत नहीं पड़ रही है। यह सारा कार्य पिछले साढ़े तीन वर्ष में हुआ है। हम नई सोच के साथ आगे बढ़े हैं।

सर, पैट स्कैन के लिए इसी माननीय सदन में हमने कई बार प्रश्न किए कि भाई पैट स्कैन तो लगाओ। डबल इंजन की सरकार एक पैट स्कैन तक नहीं लगा सकी। हमारी सरकार जैसे ही आई है हमने पैट स्कैन लगाया है। पहले 45,000 रुपये देकर चंडीगढ़ जाकर पैट स्कैन करवाना पड़ता था और आने-जाने का खर्च अलग था। अब यह पैट स्कैन आपके पास हो रहा है। आप उसकी बात नहीं करते।

आपके समय में अल्ट्रासाउंड की मशीनें थीं। आपकी सारी अल्ट्रासाउंड की मशीनें सड़ गईं। आपकी एम0आर0आई0 की मशीनें सड़ गईं। आज नई सोच के साथ 3,000 करोड़ रुपये का बजट रखकर स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो रही है।

आपका क्रष्णा जो आपके लोगों की ही लैब है और जो एक कंपनी है। क्रष्णा लैब में कौन पार्टनर है यह आप बढ़िया से जानते हैं। उनके रिजल्ट को डॉक्टर मानते नहीं
25.08.2026/1510/बी.एस./डी.सी.-3

हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इसमें डिफेक्ट है और इसका रिजल्ट एरर वाला है। इसलिए दोबारा वह टैस्ट किसी दूसरी जगह भेज देते हैं।

ये अपने समय की बात भूल गए हैं कि इन्होंने क्या करना था और क्या नहीं करना था। आज स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो नई सोच पैदा की गई है उसमें नया काम हुआ है। डॉक्टर्स लगातार भर्ती किए जा रहे हैं। आज कुछ पी0एच0सी0 में यह हो सकता है कि जहां डॉक्टर्स नहीं पहुंचे हों। लेकिन अब ज्यादातर पी0एच0सीज0 में डॉक्टर आ गए हैं और आपके सी0एच0सी0 में भी डॉक्टर आ गए हैं।

आप हेल्थ वर्कर्स की बात कर रहे हैं वहां अब हेल्थ वर्कर के स्थान पर बी0एस0सी0 नर्सिंग की व्यवस्था की जा रही है जो हेल्थ सब-स्टेशन सेंटर में रहेगी। वे वहां इंजेक्शन लगाने के लिए भी काबिल है। हेल्थ वर्कर तो इंजेक्शन ही नहीं लगा सकती थी। वह

पैरासिटामोल और दो-चार दवाइयों के अलावा सिरदर्द की दवा देने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता था।

जो रिवोल्यूशन हुआ है उसकी प्रशंसा की बजाय ये लोग केवल उसकी आलोचना कर रहे हैं। जिन माननीय सदस्य ने यह चर्चा लाई है वे जवाब सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं और सदन से वापस चले गए हैं। क्योंकि उनको पता है कि जो कुछ बोला जा रहा है वह सच बोला जा रहा है और जो उन्होंने बोला था वह सब कुछ गुमराह करने वाली बात थी। इसलिए आज स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरा प्रदेश खुश है।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

25.08.2026/1515/DT/HK-1
राजस्व मंत्री जारी.

क्योंकि आज जो रोबोटिक सर्जरी तथा डायलिसिस हो रहे हैं। आज नशा मुक्ति की बात हुई। नशा मुक्ति के लिए इन्होंने पांच वर्ष में कब और क्या किया? पांच वर्ष में इन्होंने नशा मुक्ति का नाम तक नहीं लिया। आज नशा मुक्ति के लिए जगह-जगह बड़े-बड़े मैराथॉन हो रहे हैं और लोगों को जागृत किया जा रहा है। स्पेशल टास्क फोर्स लगाकर आज चिट्टा पकड़ा जा रहा है। जिसने भी चिट्टे के कारोबार में संलिप्त लोगों को पकड़ा गया है उनकी संपत्ति भी जब्त की जा रही है। अभी हाल ही में मेरे जिला किन्नौर में भाजपा के पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष को साढ़े सात ग्राम चिट्टे के साथ होटल में पकड़ा गया और उसके पास डेढ़ लाख रुपये भी थे। उसकी बात ये लोग नहीं करते हैं। चिट्टे का धंधा कौन कर रहा है? चिट्टा माफिया तो इनके अंदर बैठा हुआ है। जब मैंने यह बात प्रेस में उजागर की तो इनका एक छुटभैया नेता कहता है कि मंत्री को कुछ पता नहीं लगता क्योंकि वह छुटभैया नेता उसी होटल में जाकर उस व्यक्ति के साथ खाता-पीता है और कई बात वहीं रहता है। ये सारी बातें हैं। बोलना बड़ा आसान है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के समय वक्त के हिसाब से बहुत सारे रिफॉर्म्स मेडिकल फिल्ड में हुए हैं और उनको अभी थोड़ा समय और लगेगा। जब ये रिफॉर्म्स आएंगे तो डेढ़-दो वर्ष के अंदर हिमाचल की जनता याद

करेगी कि ऐसी कांग्रेस की सरकार थी और ऐसा मुख्यमंत्री था जिसने बड़ी गहराई से सोच कर स्वास्थ्य क्षेत्र में इतना बढ़ा सुधार किया।

अध्यक्ष महोदय, जो हिमकेयर की बात हुई है- हिमकेयर योजना में क्या था? हिमकेयर योजना में विपक्ष ने अपने शासनकाल में प्राइवेट में जितने भी इनके अपने लोग थे उनको एम्पैनल किया हुआ था और सारे-के-सारे फर्जीवाड़े वहां होते थे। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये पब्लिक के चले गए और किसी का केयर ही नहीं हुआ। सिर्फ अपना केयर हुआ और इनके लोगों का केयर हुआ। ये आयुष्मान भारत की बड़ी बात करते हैं। इसमें मात्र 80 करोड़ रुपये हमें केंद्र से मिलते हैं और तीन सौ-चार सौ करोड़ रुपये प्रदेश सरकार खर्च करती है। क्यों, क्योंकि हमें यह योजना चलानी थी। हमारी एक सब-कमेटी की मीटिंग थी जिसके अध्यक्ष उप-मुख्य मंत्री महोदय थे और उसमें इस विषय पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई और हमने देखा कि इस योजना के भेष में पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा यह योजना बनी हुई थी। अब फैसला लिया गया है कि इस

25.08.2026/1515/DT/HK-2

हिमकेयर और आयुष्मान योजनाओं को छोड़ो और इसको गोली मारो। अब हम सीधा किसी और नई स्कीम में आते हैं। इंश्योरेंस स्कीम की बात हो रही है। उसमें दस लाख रुपये का इंश्योरेंस होगा। उसमें सरकार कुछ पैसा देगी और कुछ पैसा प्रीमियम के ष्व में देना होगा। आपका हिमकेयर तो आपका अपना केयर था। इस योजना की आड़ में आपने अपने लोगों का केयर करके उनको मालामाल कर दिया। मुझे ये सारी बातें कहनी हैं। बेसहारा की बात हो रही है। मैंने अभी डिटेल मंगाई है। बेसहारा में एक ही कांस्टिच्यूएंसी में सारे बेसहारे हुए और बाकी जगह पर तो बेसहारे हैं ही नहीं। ये कैसी बेसहारा योजना थी कि सिर्फ अपनों को सहारा देना और दूसरों को बेसहारा कर देना? ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं उनमें कोई भी सच्चाई का अंश नहीं है बल्कि इन्होंने केवल आलोचना के लिए यहां पर यह प्रस्ताव लाया है। मैं इस प्रस्ताव का बिल्कुल समर्थन नहीं करता क्योंकि जो तथ्य हैं इनके कथन के विपरीत है।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।

25.08.2026/1515/DT/HK-3

अध्यक्ष : अब चर्चा में आगे भाग लेंगे माननीय सदस्य डॉ0 हंस राज।

डॉ0 हंस राज : धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष जी। एक महत्वपूर्ण विषय जो माननीय सदस्य जी ने स्वास्थ्य के संबंध में लाया है उस पर आपने मुझे भी बोलने का समय दिया। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

चूंकि प्रदेश और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में अलग-अलग सदस्यों ने कह दिया है इसलिए मैं सीधे चम्बा-तीसा और अपने विधान सभा क्षेत्र की ही बात करूंगा। माननीय नेगी जी कई बार भटक जाते हैं तो मुझे लगता है कि इन पर भी भंडारी जी का असर दिख रहा है, निगम भंडारी जी ऐसे बंदे हैं इस तरह का उनका प्रेशर इन पर रहता है। जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे कह रहे थे कि चम्बा गए मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि क्या पता इस बार टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता नहीं था कि वह भी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो समय बदलता है और समय अपना रंग दिखाता है। कब किसका कैसा समय आएगा वह तो वक्त ही बताएगा लेकिन इतना जरूर है कि मैं पूर्ण तरह से मुतमईन हूं कि जिस चुराह के लिए हमने रात-दिन बात की है और जिस चुराह को कई बार लोग यह कहते थे कि बहुत रिमोट और एस्पिरेशनल टाइप का इलाका है तथा बहुत दूरस्थ इलाका है, वह आज अपने पैरों पर खड़ा है और हम लगभग सारे डिवीजन वहां खोल चुके हैं। एक डिवीजन की बिल्डिंग का उद्घाटन करने का सुअवसर माननीय डिप्टी सीएम साहब को भी मिला जो हमारे टाइम में बनी थी। ऐसे ही कई योजनाएं हमने बनाई थीं जिनका इन्होंने अभी उद्घाटन किया है। हम लोग अपनी पूरी रफ्तार में चले हुए हैं। पिछले चार वर्षों में, मैं कोई कुंठावश या यूं कहें कि इसलिए आलोचना नहीं करूंगा कि मैं इस तरफ से खड़ा हूं और इसलिए इनका विरोध करूंगा। लेकिन जो एक्चुअल व्यवस्था है और जो सच में गड़बड़ाई हुई है

श्री0 एन0जी0 द्वारा जारी...

25.08.2026/1520/एच.के.-एन.जी./1

डॉ0 हंस राज.......... जारी

इसलिए आलोचना नहीं करूंगा कि मैं इस तरफ से खड़ा हूं और मुझे इनका विरोध ही करना है। लेकिन जो वास्तविक व्यवस्था है और वह सच में गड़बड़ाई हुई है, उस पर बात करना जरूरी है। जिस दिन मुख्य मंत्री जी ने या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने कहा कि हम लोग आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की व्यवस्था करेंगे, उस दिन मुझे भी लगा था कि स्वास्थ्य संस्थानों का सुधार होगा। मेरे क्षेत्र में तीसा का हॉस्पिटल 25 बेडिड हुआ करता था और उसको अपग्रेड करते-करते हमने पहले उसे 50 बेडिड और फिर 100 बेडिड का बना दिया। वह अस्पताल 53 ग्राम पंचायतों को फीड करता है। मुझे लगा था कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के बहाने ही सही, शायद हमें एक अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा और जो चीजें हमसे नहीं हो पाई, शायद वर्तमान सरकार उसमें एन्हांसमेंट करेगी और उसे थोड़ा और आगे बढ़ाएगी। लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा क्योंकि हमारे राजनगर में बहुत पुरानी सी0एच0सी0 है और वहां पर तीन-तीन डॉक्टर हुआ करते थे। पुखरी हमारा मेन जंक्शन है और वहां पर भी 4-4 डॉक्टर रहे। वर्तमान सरकार ने हमारी दो पी0एच0सी0 को तो डिनोटिफाई ही कर दिया जिसमें से एक बैरागढ़ में खोली थी और दूसरी हमने कूहाल में खोली थी। मैंने परसों एक एक प्रश्न लगाया था, प्रश्न संख्या - 1695, जिसमें मैंने पूछा था कि चुराह विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कितनी पोस्टें रिक्त हैं? वैसे तो मुझे इस बात का इल्म था और पूरा विश्वास था कि बहुत सारी पोस्टें खाली हैं, क्योंकि जब मैं तीसा को ही देखता था और जब मैं पिछली बार सरकार में था तो हमने वहां पर 17 डॉक्टर रखे थे। इस सरकार में वे तीन पर आ गए और वहां पर कोई नर्सें भी नहीं रहीं। मैं सोच रहा था कि जिसकी ओ0पी0डी0 प्रतिदिन 150 से 300 की है, वहां पर डॉक्टर्स कम कैसे हो सकते हैं? हमारे क्षेत्र के लोगों को क्षेत्र के मुख्य मेडिकल कॉलेज, चम्बा पहुंचने के लिए 60-70 किलोमीटर चलना पड़ता है। मैंने सोचा कि इसी आंकड़े को देखते हुए एक प्रश्न ही पूछ लेता हूं।

25.08.2026/1520/एच.के.-एन.जी./2

मैंने प्रश्न पूछा और उत्तर में जो निकल कर आया उससे महसूस होता है कि यह कितनी भयावह स्थिति है। माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी और सत्ता पक्ष के लोग अगर सुन रहे हों तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कुल 239 पोस्टों में से 130 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। उसमें बी0एम0ओ0 कितने हैं या नहीं हैं ये तो अलग बात है लेकिन तीसा में, जोकि क्षेत्र का मुख्य हॉस्पिटल है और 53 पंचायतों को फीड करता है, कम-से-कम वहां तो बी0एम0ओ0 होना चाहिए। लेकिन पिछले चार साल से वहां पर कोई बी0एम0ओ0 नहीं है। जो वहां से गया, वह वापस ही नहीं आया। यहां पर मैं देख रहा था कि सत्तापक्ष के लोग पैट स्कैन की बात कर रहे थे। हमने पैट स्कैन लगाने के लिए आई0जी0एम0सी0 में जगह देखी थी और उसको सैंक्शन भी करवाया था। अभी वह चला या नहीं चला, उसकी हमें कोई डिटेल नहीं मिली। लेकिन पैट स्कैन चलना चाहिए क्योंकि यह बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश इतना बड़ा है और यहां पर पैट स्कैन होता नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, अपने हिसाब से अच्छा कर रहे होंगे। लेकिन कल आप लोगों ने भी विपक्ष में जाना है। मेरा आग्रह है कि आप लोग ऐसा सिस्टम मत छोड़ कर जाना कि प्रदेश के लोगों को समस्या हो। माननीय मंत्री जी, आप सीनियर व्यक्ति हैं और पता नहीं विभाग आप चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं। मैं सच में आपसे बड़ी सहानुभूति रखता हूं, क्योंकि आपके विभाग में जिस तरह से आउटसोर्स में भर्तियां हो रही हैं और उनमें कोई रोस्टर लागू नहीं है। मंत्री जी, आप भी शेड्यूल्ड हैं। श्री जगत सिंह नेगी जी बड़ा चिल्ला रहे थे लेकिन उन भर्तियों में न शेड्यूल्ड कास्ट, न शेड्यूल्ड ट्राइब, न ओ0बी0सी0 और न कोई अन्य रोस्टर लागू हुआ है तथा वे भर्तियां वैसे ही हो रही हैं। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने तो कहा था कि हम पक्की नौकरी देंगे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में पक्की नौकरी नहीं है। इसके अलावा नर्सें कब भर्ती हो रही हैं, पता ही नहीं चल रहा है?

25.08.2026/1520/एच.के.-एन.जी./3

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे प्रदेश के नेता हैं, सदन के सबकुछ हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि जो चर्चा लाई गई है, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप अन्यथा न लें और इस चर्चा को लेकर आप लोग कटाक्ष न करें। देखो, चुराह विधान सभा क्षेत्र में व्यवस्थाएं हमने लगभग-लगभग ठीक कर दी थीं। हमारी एक पी0एच0सी0 झज्झा है, वहां पर हमने एक्स-रे तक शुरू करवा दिया था। जैसे भी व्यवस्थाएं की थीं, कर दी थीं। तीसा हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल चलता था। कलेहल हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलता था। हमारी हिमगिरि की पी0एच0सी0 बहुत शानदार चलती थी। हमारा जो पुखरी का इलाका है, उसमें पी0एच0सी0 बहुत शानदार चल रही थी। लेकिन आप लोगों ने सच में सारी पी0एच0सीज़0 को खराब कर दिया। कहीं से डॉक्टर उठा लिए और कहीं से फार्मासिस्ट। दूसरी सबसे भयावह स्थिति तीसा हॉस्पिटल की बताता हूं, जहां पर 300 की ओ0पी0डी0 प्रतिदिन होती है। अभी माननीय डिप्टी सीएम साहब गए थे और इनसे वहां पर कुछ लोग मिले भी थे। उन्होंने आपसे कहा और आग्रह भी किया कि आप हमारे साथ सिविल हॉस्पिटल तीसा चलें। वहां पर एक वक्ता भाषण दे रहे थे और उनकी खुद की ही जुबान फिसल गई। उनको यह बोलना नहीं चाहिए था कि पिछले चार साल पहले तो यहां पर 17 डॉक्टर तैनात थे। मैं वहां पर मौजूद था। अब वह बोल गया

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

25.08.2026/1525/YK/PB/1

डॉ0 हंस राज जारी...

क्योंकि सच्चाई बोलनी ही पड़ती है। हमारी पूर्व की भाजपा सरकार ने आर0के0एस0 के तहत सफाई कर्मचारियों की भी उपयुक्त व्यवस्था कर दी थी। उसके बाद वर्तमान सरकार द्वारा कहा गया कि फंड नहीं आ रहा है। दूसरा, हॉस्पिटल को अलग से पानी का कनैक्शन दिया था। हम जिस सैनिटेशन, वॉशरूम्स या टॉयलेट्स की बात करते हैं उसके लिए मैं

चाहता हूं कि आप आउटसोर्स पर कर्मचारी रखवा दीजिए। वहां पर सच में बड़ी भयावह स्थिति है। माननीय मुख्य मंत्री जी आज तक चुराह नहीं आए है। मैं उनको यहां से निमंत्रण भी देता हूं कि आप चुराह आइए और एक बार जरूर संज्ञान लीजिए तथा वहां पर इस आदर्श स्वास्थ्य संस्थान को बनाएं। मैं भाभी जी (माननीय सदस्या श्रीमती कमलेश ठाकुर की ओर इशारा करते हुए) से भी आग्रह कर रहा हूं कि आप भी मुख्य मंत्री जी के साथ आइए। हमारा सतरुंडी का इलाका बहुत अच्छा है। देवी कोठी माता और चांजू वाली माता का बड़ा आशीर्वाद है। वहां खुंडी माता की यात्रा निकलती है। आप इसी बहाने घूम-फिर भी लेंगी और हो सकता है कि उसी बहाने सड़क भी दुरुस्त हो जाए जो बड़ी मुश्किल से दुरुस्त होती है। शायद हम आपको उस हॉस्पिटल में ले जाने में कामयाब हों और शायद वह ठीक हो जाए। लेकिन अब मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि चार साल में आपसे जो व्यवस्थाएं खड़ी नहीं हुई, वे आगे भी नहीं होंगी। मैं आपसे सिर्फ इतनी गुज़ारिश कर रहा हूं कि जो सरकार के बचे हुए एक वर्ष में कम-से-कम आप यह कार्य कर दीजिए। कुर्सी किसी की परमानेंट नहीं होती है। हमें भी सदन में अब पंद्रह साल होने को हो गए हैं । हमने कई बार देखा है कि जो गरजते थे और बहुत सारी बातें भी करते थे उनकी जब परफॉर्मेन्स की बारी आई तो वहे नहीं कर पाए। बाद में पछतावा ही होता है और झुंझलाहट होती है। जब सत्ता में नहीं होते या मान लो उस आसन पर नहीं रहते या उस जगह पर नहीं रहते उसके बाद जब रिज-मॉल में मिलते हैं तो अपने आपको कोसते होंगे कि शायद मैं यह कर सकता था और अजर-अमर हो सकता था। ऐसे नहीं है। कुछ बिरले लोग ही अजर-अमर हुए हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको अच्छी रियलाइजेशन हो रही है। I am very happy to note this.

25.08.2026/1525/YK/PB/2

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, कुछ चीजें समय सिखा देता है, कुछ सीखनी पड़ती है और कुछ लोग सिखा देते हैं। अपने लोग ज्यादा सिखाते हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको अपने और दूसरे लोगों से काफी तजुर्बे है।

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, मेरे सभी अपने ही हैं। मेरा सरकार से यह आग्रह है कि मैं आपको जो चुराह विधान सभा क्षेत्र के बारे में गिनवा रहा हूं, इस क्षेत्र ने बहुत भुगता है और हमने बहुत मुश्किल से सारा ट्रैक ठीक किया था। इसमें सरकार को बराबर अटेंशन देनी चाहिए। मैं तीसा अस्पताल के बारे में बार-बार कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, चंबा मेडिकल कॉलेज की बात करना भी बहुत जरूरी है। मिंजर के उपलक्ष में मुख्य मंत्री जी आए। उन्होंने मिंजर के बहाने ही सही तीन वर्षों के उस क्षेत्र का टूर किया। हम उनको बधाई देते है। जिस दिन मुख्य मंत्री जी आए उस समय सारी व्यवस्थाएं नए परिसर में लेकर गए। उस दिन उन्होंने फिर टीका-टिप्पणी की कि ये लोग मिंजर में नहीं आए। मुझे पता था कि वे ऐसा कहेंगे। हम वहां कैसे आते? मैं आपको इसकी सच्चाई फिर कभी फुर्सत में बताऊंगा। लेकिन हमें लगा कि आज ये बिल्डिंगें काम आ ही गई अन्यथा वे खंडहर बन जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, आप इसका संज्ञान लीजिए नहीं तो वे बिल्डिंगें खंडहर बन जाएंगी। प्रशासन द्वारा फर्नीचर भी वहां लिया गया और जैसे ही मुख्य मंत्री जी वहां से गए, सारी व्यवस्थाएं फिर से शिफ्ट कर दी गई। वहां के प्रिंसिपल महोदय की सदन में प्रशंसा बनती है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस मेडिकल कॉलेज को केवल रेफरल मेडिकल कॉलेज बनाकर न रखा जाए क्योंकि टांडा पर बहुत बड़ा प्रेशर है।

सरकार को चम्बा जैसे रिमोट जिले में उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधाएं देनी चाहिए क्योंकि चम्बा से जो मरीज शिफ्ट होता उसे टांडा पहुंचने में चार-पांच घंटे लग जाते है। अध्यक्ष महोदय, पिछले कल सदन में फैक्टर-9, फैक्टर-4, फैक्टर-3 और हीमोफीलिया की बात हो रही थी, मैंने उस संबंध में कई बार स्वस्थ्य मंत्री जी और सेक्रेटरी हेल्थ से भी बात की है। ऐसे मरीज जिनके लिए टांडा जाना बहुत मुश्किल है, जैसे कैंसर के मरीज हैं जिनकी कीमो लगनी होती है या जिनके डायलिसिस होने हैं और बाहर नहीं जा सकते। चम्बा में कम से कम कैंसर और डायलिसिस के लिए तथा हीमोफीलिया और इस तरह के

25.08.2026/1525/YK/PB/3

मरीजों के लिए मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं दी जाएं। हम यह नहीं कहेंगे कि आप वहां क्या करें और क्या न करें। लेकिन अगर आप भर्तियां भी कर रहे हैं तो वह ठीक ढंग से की जानी चाहिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, यह आपको यह औदा न बार-बार मिलेगा और न ही यह दौर बार-बार आएगा। मैं आपसे सच्चाई कह रहा हूं। मैं आपसे यह इल्तिजा कर रहा हूं कि चम्बा कि इस जिले के हालात को ठीक करने के लिए सही तरीके से स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो उपयुक्त व्यवस्था हो सकती है, वह करनी चाहिए।

मुख्य मंत्री जी, आप बाकी जगह काम कर रहे है या नहीं कर रहे है, वह हम चुनावों में बताएंगे लेकिन जिला चम्बा ने मेडिकल कॉलेज के लिहाज़ से एक बहुत बड़ा एरिया आपको दिया है। इससे लगभग पांच विधान सभा क्षेत्र फीड हो सकते हैं। सियूंता वाले तो टांडा

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

25.08.2026/1530/वाई0के0/ए0पी0-01

नियम- 130 के अंतर्गत चर्चा जारी .....

डॉ हंस राज जारी .....

लेकिन बाकी पूरा चंबा वहीं फीड होता है। उस पर फोकस करिए। चुराह विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों की जो मैंने बात की है, वहां पर विशेषकर सी0एच0सी0 सिविल हॉस्पिटल तीसा है, उसमें आप आउटसोर्स कर दें। स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के हिसाब से, सफाई के हिसाब से। दूसरा, वहां नर्सेस और बी0एम0ओ0 नहीं हैं और 17 डॉक्टरों के एवज में केवल 6 डॉक्टर हैं, आप उसे भी स्ट्रेंथन कर दीजिए। दूसरा, हमारा पुखरी का मेन हॉस्पिटल जोकि 22-से-25 पंचायतों को फीड करता है। मसरूंड और राजनगर वाला इलाका, कलेहल वाली बेल्ट और बगई वाला पोर्शन, ये अलग-अलग जंक्शन हैं। चुराह विधान सभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बहुत फैला हुआ है। अगर आप वहां पर एजुकेट व्यवस्थाएं देंगे तो मैं समझता हूं कि एक तरह से आप लोगों की वाहवाही होगी। इससे

ज्यादा तो क्या ही होना है और बाकी तो आने वाले दौर में पता चल ही जाएगा। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद।

25.08.2026/1530/वाई0के0/ए0पी0-02

अध्यक्ष : अब चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी। I would request the Hon'ble Member Shri Sanjay Rattan to come to Chair the further proceedings.

सभापति महोदय पदासीन हुए।

श्री मोहन **लाल ब्राक्टा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विषय नियम-30 के तहत चर्चा में रखा गया है, वह प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों के निर्माण, उन्नयन, बुनियादीकरण, उपकरण, दवाइयों की उपलब्धता और स्वास्थ्य से संबंधित विषय है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, चाहे सत्तापक्ष हो या विपक्ष, बहुत सारी बातें की हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। इतना जरूर है कि विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कोई दोराहे नहीं है। लेकिन जब यह विषय यहां प्रस्तुत किया गया और जब ऑपोजीशन मेंबरों ने इस पर बोला तो समझा आता है कि उनकी मंशा कुछ और ही है। मंशा विषय की नहीं, बल्कि विषय से हटकर है। इनका काम सिर्फ यह है कि सरकार को कोसना और घेरना है। मेरे से पूर्व माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने भी अपनी बात कही जिसमें उन्होंनं कहा कि ऑपोजीशन का काम रूलिंग पार्टी और सरकार को सुझाव देना है। मैंने सोचा कि माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी शायद इसी विषय पर अच्छी बात करेंगे, लेकिन फिर वे विषय से हट गए और कहीं और चले गए। मैं एक की बात नहीं कर रहा बल्कि सभी लोगों विषय से हट कर बोलने लगे। मतलब कि जो विषय है, सब्जेक्ट मैटर है, उस पर बात करने के बजाय सरकार को कोसने की बात कही कि सरकार ने यह नहीं किया, वह नहीं किया और भ्रष्टाचार किया। अगर भ्रष्टाचार की बात करूं तो स्वास्थ्य सेवाओं में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो वह आपकी सरकार के समय हुआ है। अगर आपको याद होगा, आपके हेल्थ मिनिस्टर को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। चाहे कोविड की बात हो या कोई दूसरी बात हो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं इस

पर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में जो सुधार और इंप्रूवमेंट लाया है, वह सराहनीय है। चाहे रोबोटिक सर्जरी की बात हो, चाहे दूसरी मशीनरी की बात हो, चाहे डॉक्टरों की भर्ती हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो या दूसरा स्टाफ हो, हमारी सरकार के समय में बहुत सारी भर्तियां हुई हैं। लेकिन

25.08.2026/1530/वाई0के0/ए0पी0-03

यहां ऑपोजीशन की तरफ से सिर्फ यही सुनने को आ रहा है कि सरकार ने यह नहीं किया, वह नहीं किया, वह भी नहीं किया। मेरे माननीय साथियों ने यहां जो बातें कही हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो स्वास्थ्य के बगैर कुछ भी नहीं है। विषय बहुत अच्छा था और विषय अच्छा होने ही सब नहीं है आपकी मंशा भी अच्छी होनी चाहिए। माननीय श्री विपिन सिंह परमार जी ने तो 34-35 मिनट बात की, लेकिन उसमें भी बस सरकार को कोसने की बात कही।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

25.08.2026/1535/AT/AG/01

श्री मोहन लाल ब्राक्टा जारी....

परमार साहब ने तो मेरे ख्याल से 34-35 मिनेट बस कोसने की बात कही। उन्होंने कोई ऐसी सजेशन नहीं दी। जितने भी आप लोगों ने बातें कही आप उस में कोई पॉजिटिव सजेशन देते, ठीक बात है। ऑपोजिशन का काम, हर चीज को ऑपोज करना नहीं है। पोज भी करना चाहिए,हर चीज को गलत बताएं, ऐसा नहीं है। आज सरकार को चार साल का समय होने जा रहा है, क्या चार साल में कुछ नहीं हुआ? क्या ऐसे ही सरकार चली है? ये भी सोचने की बात है। थोड़ा सा सोच-समझकर तो बोला करो। बाकी यहां पर, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रदेश की और भी कई बातें, चाहे कॉलेज की बात है, चाहे भर्ती की बात है, चाहे दूसरे विषयों की बात है, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कही

हैं। मैं अब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक कन्फाइन करूंगा और कुछ बातें माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में भी लाना चाहूंगा।

सीबील हॉस्पिटल रोहड़ू में डेली की ओ0पी0डी0 आठ सौ से एक हजार के करीब होती है। यह केवल रोहड़ू कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही फीड नहीं करता, बल्कि साथ लगती जुव्वल तहसील का पूरा क्षेत्र, आधी जुव्वल कोटखई कॉन्स्टिट्यूएंसी रोहड़ू में आती है। यहां तक कि उत्तराखंड का इलाका भी रोहड़ू से जुड़ा हुआ है। आज वहां पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं।

जहां तक डॉक्टरों की बात आती है, आज मेरे पास पूरे डॉक्टर हैं। 31 डॉक्टर का अस्पताल चला रहे हैं, 31 के 31 डॉक्टर वहां पर हैं, हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां पर है। सर, उसमें आजकल स्टाफ नर्सों की कमी आ रही है। उसका भी रीजन यह है कि कई लीव पर हैं, कई मैटरनिटी लीव पर हैं और कई ने नौकरी छोड़ दी है। इसलिए उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज रोहड़ू सिविल हॉस्पिटल में डिलीवरी केसेस हो रहे हैं, सर्जरी हो रही है, आंखों की सर्जरी हो रही है और यहां तक कि ईको टेस्ट के लिए, जिसके लिए हमें IGMC, शिमला आना पड़ता था, उसके टेस्ट भी हो रहे हैं। हमारे किडनी पेशेंट के डायलिसिस भी हो रहे हैं और यहां तक

25.08.2026/1535/AT/AG/02

कि कैंसर पेशेंट की कीमोथेरेपी भी रोहड़ू में हो रही है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है। जो भी यहां पर स्टाफ नर्सों की कमियां हैं, उनको शीघ्र से शीघ्र भरा जाए, यह मेरा आपसे आग्रह है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उनके आशीर्वाद से रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनने जा रहा है, जो 25 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उसका काम चला हुआ है।...(व्यवधान) इसके अलावा सर, यहां पर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, शायद

रणवीर शर्मा जी ने भी बात कही कि भाई, हमारी सरकार ने तो संस्थान बंद किए। हेल्थ की बात हो रही है, तो मैं हेल्थ में ही आ रहा हूं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार बनी थी और पिछली बार जय राम ठाकुर जी माननीय मुख्य मंत्री थे, उन्होंने मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दो-दो पी0एच0सी0 बंद की थीं। अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो दो पी0एच0सी0 बंद की। इसके अलावा एक PWD का रेस्ट हाउस है, जिसकी टेंडर हो चुका था। वह मेरे गांव कुटाड़ा में था, उसको वापीस ले गए और उस के लिए जो पैसे आए थे उसे भी वापीस ले गए और दूसरी जगह खर्च कर दिए। इसके अलावा डोटरा क्वार का दूरदराज का इलाका, जहां पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने ।T। खोली थी, जय राम ठाकुर जी की सरकार ने उसे भी वहां से हटा दिया। मैं यह सब बताना नहीं चाहता था। मैं हेल्थ सेक्टर से हट कर है, चाहे ।T। है, चाहे PWD रेस्ट हाउस है। पर आप लोग सब्जेक्ट मैटर पर तो कन्फाइन होते नहीं हैं, आप फिर दूसरी बातें और राजनीतिक बातें करते हैं।

दूसरी मैं बात करूं तो इसके अलावा सर, हिमकेयर की बात आती है। इस में कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी स्कीम थी। पर जो भ्रष्टाचार इसमें हुआ, जो धांधलियाँ हुईं, वो आपके सामने हैं। यहां पर ऐसे-ऐसे ऑपरेशन हुए, जिनकी बीमारी होती ही नहीं है। लेडीज़ की बीमारी मर्दों में दिखाई गई है, ऐसे-ऐसे ऑपरेशन हुए, ऐसे-ऐसे ट्रीटमेंट हुए। इसलिए यह भी एक चिंता का विषय है।

मैं इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं। वर्ष 2021 में, जहां शिक्षा के क्षेत्र में आपकी सरकार थी, आप हिंदुस्तान में 21वें स्थान पर थे। आज तीसरे और चौथे स्थान पर आ गए हैं।...(व्यवधान)

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी ......

25.08.2026/1540/AV/AG/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा क्रमागत

सभापति महोदय, जहां तक इस सरकार की बात है तो स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत चाहे मशीनरीज की बात की जाए या फिर स्पेशलिस्ट्स की बात जाए, यहां पर बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की गई हैं। यहां पर जो मुख्य मंत्री जी द्वारा दूध के रेट बढ़ाए गए उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मेरे रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र में पहले 5000 लीटर्ज दूध आता था। परंतु जब से दूध के रेट बढ़े हैं, ...(व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य, अभी स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही है।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा, ...(व्यवधान) मैं भी भटकना नहीं चाहता था। मैं भी स्वास्थ्य पर ही बोलना चाहता था परंतु क्या करे, विपक्ष के साथियों ने अब आदत डाल दी है कि बात हो रही हैल्थ की और ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में चले जाते हैं।

सभापति महोदय, जहां तक नियम-130 के अंतर्गत यह प्रस्ताव लाया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु इनकी मन्शा ठीक नहीं है और जिन-जिन वक्ताओं ने अभी तक इस पर चर्चा की है उससे यही महसूस होता है कि इनकी मन्शा सब्जैक्ट मैटर से संबंधित नहीं है। इसलिए यह जो विषय लाया गया है, मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

25.08.2026/1540/AV/AG/2

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल हिस्सा लेंगे।

श्री राकेश जम्वाल : सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय श्री विपिन सिंह परमार व अन्य साथियों ने जो विषय नियम-130 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित लाया है, मैं भी उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय विपिन सिंह परमार स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और इन्होंने यहां पर बहुत सारे विषयों पर सुझाव भी दिए तथा स्वास्थ्य विभाग में चल रही कमियों पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त डॉ0 जनक राज विधायक होने के साथ-साथ एक नामी डॉक्टर भी हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए और वर्तमान में स्वास्थ्य क्षेत्र में चल रही कमियों की तरफ सरकार का

ध्यान आकर्षित किया। आदरणीय रणधीर शर्मा ने सारे विषय पर बहुत अच्छे तरीके से प्रदेश की स्वास्थ्य परिस्थितियों के संदर्भ में अपनी बात रखी और मैं भी उसमें कुछ बातें जोड़ना चाहता हूं। यह एक ऐसा सेक्टर है जिससे हर व्यक्ति जुड़ा है। वह चाहे अमीर-गरीब, शहरी-ग्रामीण या छोटा-बड़ा; जो भी है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। प्रदेश की सरकार और मुख्य मंत्री जी की ओर से कहा गया कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। विशेष तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए। यहां पर कहा गया कि हम पूरे प्रदेश में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलेंगे। इस प्रकार की घोषणाएं भी हो गईं। हमने पूरे प्रदेश का तो पता नहीं किया परंतु अपने निर्वाचन क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सुन्दरनगर होस्पिटल को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान डिक्लेयर किया गया। सभापति महोदय, योजनाओं की घोषणाओं से काम नहीं चलता, धरातल पर चीजें उतरनी चाहिए। सत्ता पक्ष की ओर से जवाब आता है कि अभी तो हमारी सरकार का एक वर्ष और है। जिस सरकार के द्वारा चार वर्षों तक कुछ नहीं किया गया वह अंतिम वर्ष में क्या करेगी? पूर्व की सरकार की आलोचना करना और उसके द्वारा चलाई गई योजनाओं को बंद करना किसी भी सरकार या मुख्य मंत्री का लक्ष्य नहीं होना चाहिए।

एन0एस द्वारा जारी

25-8-2026/1545/NS-AS/1

श्री राकेश जम्वाल-----जारी

सरकारें कंटिन्यूटी में चलती है। कभी इस दल की सरकार होती है तो कभी उस दल की होती है और आने वाले समय में फिर हमारी सरकार आने वाली है। लेकिन अच्छा काम किसी भी सरकार में हुआ हो उसको बंद नहीं करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन योजनाओं की ओर विशेष ध्यान दें। मैं पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी आदरणीय जय राम ठाकुर जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर हिमकेयर

योजना और सहारा योजना चलाई। वर्तमान सरकार का चार वर्षों का कार्यकाल निकल गया है और कहा जा रहा है कि हिमकेयर में गड़बड़ियां हुई हैं तथा जांच चल रही है। पांच वर्ष का समय निकल जाएगा और कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि जिस नीयत और नीति के साथ जनता की सेवा के लिए श्री जय राम ठाकुर जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वह योजना चलाई थी उसमें किसी की जाति, किसी की पार्टी अथवा किसी का धर्म नहीं पूछा गया। हर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति का इलाज हो, इस सोच के साथ हमारी सरकार यह योजना लेकर आई थी। आज पूरा प्रदेश देख रहा है कि उस योजना का क्या हाल है? हिमकेयर योजना को बंद किया जा रहा है और सहारा योजना लगभग बंद कर दी गई है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी बार-बार रोबोटिक सर्जरी का जिक्र कर रहे हैं कि अस्पतालों में दवाई मिले न मिले, पैरासिटामोल मिले न मिले, इंजैक्शन मिले न मिले लेकिन रोबोटिक सर्जरी जरूर होगी। हिमाचल प्रदेश के सभी छह मेडिकल कॉलेजों में रोबोट से सर्जरी होगी। हमारे मंडी जिला का मेडिकल कॉलेज, नेरचौक आज रैफरल मेडिकल कॉलेज बनकर रह गया है। मैं आदरणीय मोदी जी और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके आशीर्वाद से एम्स जैसा संस्थान हिमाचल को मिला। अगर आज एम्स नहीं होता तो हिमाचल की स्वास्थ्य सुविधाओं में आज हमारी क्या स्थिति होती, ये आप सब जानते हैं? आज हमें लगभग 1470 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से एम्स मिला है जिसमें 750 बैड, 18 स्पेशियलिटी तथा 17 सुपर स्पेशियलिटी विभाग हैं। वहां 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 64 आई0सी0यू0 बैड हैं तथा 24X7 डायलिसिस और इमरजेंसी की

25-8-2026/1545/NS-AS/2

सुविधा उपलब्ध है। वहां एम0आर0आई0, सीटी स्कैन तथा पैट स्कैन जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ एम0बी0बी0एस0 की सीटों पर मात्र 25,000 से 30,000 रुपये फीस में हिमाचल के विद्यार्थियों को वहां एम0बी0बी0एस0 करने की सुविधा मिल रही है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

सभापति महोदय, अब मैं रोबोटिक सर्जरी का जिक्र कर रहा हूं। मुझे नेरचौक से एक बहन का फोन आया कि मेरी बहन का ऑपरेशन हो रहा है। उसे ऑपरेशन थिएटर के लिए तैयार कर दिया गया है लेकिन गॉल ब्लैडर के स्टोन के ऑपरेशन के लिए हमसे 30,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। हम गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। मुझे भी हैरानी हुई कि गॉल ब्लैडर के स्टोन के ऑपरेशन के लिए 30,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। जब मैंने वहां मेडिकल कॉलेज में पता किया तो पता चला कि उनकी सर्जरी रोबोट से हो रही है। मैंने वहां फोन कर एम0एस0 और प्रिंसिपल महोदय से बात की कि क्या आपने मरीज से कंसैंट ली है कि वह रोबोटिक सर्जरी करवाना चाहते हैं? लेकिन आपने रोबोट खरीद लिया इसलिए यह जरूरी है कि रोबोटिक सर्जरी होनी चाहिए। गरीब व्यक्ति के पास पैसे हों या न हों लेकिन रोबोट से सर्जरी होनी चाहिए। जब परिवार की ओर से कहा गया कि हमने रोबोट से सर्जरी करवाने के लिए नहीं कहा था। उसके बाद रोबोट से सर्जरी नहीं हुई। उनके ऑपरेशन का दवाइयों सहित मात्र 5,000 रुपये खर्च आया और उनके गॉल ब्लैडर के स्टोन का ऑपरेशन हो गया। अगर रोबोट से सर्जरी होती तो शायद वहां उनके 40,000 रुपये से 50,000 रुपये खर्च होते। हम यह नहीं कहते और न ही सर्जरी का विरोध कर रहे हैं-------

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

25.08.2026/1550/RKS/एएस-1

श्री राकेश जम्वाल... जारी

हम उस सर्जरी का विरोध नहीं कर रहे हैं और न ही यह कह रहे हैं कि रोबोट से सर्जरी न हो। हमारा कहना केवल इतना है कि पहले लोगों को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध हों, इलाज की व्यवस्था हो, डॉक्टर हों तथा पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध हो। हमें इस बात की चिंता नहीं है कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक में रेडियोलॉजिस्ट हैं या नहीं लेकिन वहां रोबोट जरूर होने चाहिए। इस तरह जब लगातार खरीद-फरोख्त की जा रही है, करोड़ों रुपये खर्च करके रोबोट खरीदे जा रहे हैं तो इस

पर चिंता करना वाजिब है। इस विषय पर मेरे वरिष्ठ साथियों ने विस्तार से चर्चा की है इसलिए मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। वर्तमान में नेरचौक मेडिकल कॉलेज के रेडियोलॉजी विभाग में केवल एक ही डॉक्टर कार्यरत है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह डॉक्टर स्वयं भी गंभीर रूप से बीमार रहा और उसकी बड़ी सर्जरी हुई है। यह स्थिति हमारे नेरचौक मेडिकल कॉलेज की है। हम बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं लेकिन यह मेडिकल कॉलेज लाहौल-स्पीति, कुल्लू और पूरी मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए एकमात्र कॉलेज है जिसकी स्थिति विचारनीय है। कोविड महामारी के समय किसी ने भी ऐसी परिस्थिति की कल्पना नहीं की थी। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि लगभग 100 वर्ष पूर्व ऐसी कोई महामारी आई थी। कोविड के दौरान जब कई स्थानों पर भाई, भाई के साथ और पति अपनी पत्नी के साथ खड़ा नहीं हो रहा था तो उस समय वार्ड अटेंडैंट्स, सफाई कर्मचारियों, स्टाफ नर्सिज और ड्राइवरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन लोगों की सेवा की थी लेकिन आपने उन सभी आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से निकालकर घर बिठा दिया। उनका क्या कुसूर था? उनका कुसूर केवल इतना था कि उनकी नियुक्तियां भारतीय जनता पार्टी की श्री जय राम ठाकुर की सरकार के समय में हुई थीं। उन्हें हटाकर अब अपने चहेतों को नौकरियां दी गई हैं। जो युवा साढ़े तीन वर्ष तक लगातार सेवाएं देते रहे, उनका क्या दोष था? मैं इस बारे में मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी-बड़ी बातें करती है। मैं कुल्लू का एक उदाहरण देना चाहता हूं। सराज विधान सभा क्षेत्र की बाली चौकी की हमारी बहन मंजू की 20 जून को डिलीवरी हुई और 21 जून को उसकी मृत्यु हो गई। उस घटना के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और आंदोलन किया। परिवार के सदस्यों का आरोप था कि स्टाफ की कमी तथा डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनकी बेटी की

25.08.2026/1550/RKS/एएस-2

मृत्यु हुई। लोग सड़कों पर आए, भूख हड़ताल हुई और धरने-प्रदर्शन किए गए। आज यह स्थिति पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की है। आज पूरा प्रदेश स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चिंतित है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र भी जरूर करना चाहूंगा। आज लोगों को अपना मंगलसूत्र बेचने की नौबत आ गई है लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सरकार लगातार करोड़ों रुपये की खरीद-फरोख्त में लगी हुई है। जैसा मैंने

कहा कि रोबोट तो उपलब्ध हैं लेकिन अस्पतालों में पैरासिटामोल जैसी दवाई भी उपलब्ध नहीं है। आज इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। जहां पूर्व सरकार के समय भवन निर्माण कार्य शुरू किए गए थे उनमें से अनेक कार्य आज भी अधूरे पड़े हैं। यदि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो डॉक्टरों और पैरा-मेडिकल स्टाफ के लिए बनाए जा रहे आवासों का निर्माण कार्य आज भी अधूरा पड़ा है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज में लगभग जो डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया था वह आज बंद पड़ा है और उसकी जगह ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? निश्चित रूप से कहीं-न-कहीं गड़बड़ी जरूर है। उस ऑक्सीजन प्लांट को संचालित करने वाले दो नौजवानों को हमने आउटसोर्स आधार पर रखा था लेकिन उन्हें भी घर भेज दिया गया है। जो तीन-चार वर्षों से सेवाएं दे रहे थे उन्हें केवल इसलिए घर भेज दिया गया क्योंकि उनकी नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुई थी। मैंने मंत्री महोदय से आग्रह किया था कि उन दोनों युवाओं को पुनः नौकरी में रख दिया जाए ताकि हमारा ऑक्सीजन प्लांट चल सके और लोगों को सुविधा मिले सके। लेकिन वह ऑक्सीजन प्लांट नहीं चलाया जा रहा है और वहां ऑक्सीजन सिलेंडरों की खरीद की जा रही है। हमारा राही केयर के माध्यम से पी0पी0पी0 मोड पर एक डायलिसिस सेंटर संचालित होता था। वहां हिमकेयर के अंतर्गत गरीब लोग डायलिसिस करवाते थे लेकिन अब राही केयर ने भी यह कहकर सेवा देने से मना कर दिया है कि उन्हें भुगतान नहीं मिल रहा है इसलिए वे डायलिसिस की सुविधा प्रदान नहीं कर सकते हैं।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

25.08.2026/1555/बी.एस./.डी.सी.-1

श्री राकेश जम्वाल जारी...

इसलिए हम इलाज नहीं कर सकते और हम डायलिसिस नहीं कर सकते। हमारे मण्डी के गुटकर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। आजकल वहां जो भी हार्ट के मरीज आ रहे हैं वहां पर

स्टेंटिंग हो रही है और लाखों रुपये लोगों से लिए जा रहे हैं। वह हॉस्पिटल एम्पेनल्ड है लेकिन न वहां आयुष्मान कार्ड चल रहा है और न ही हिमकेयर का कार्ड चल रहा है।

मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मण्डी जिला के गुटकर के उस हॉस्पिटल में जहां लगातार दिन में 10-10 और 15-20 लोगों को स्टेंट डाले जा रहे हैं वहां जांच की जाए कि आयुष्मान का कार्ड क्यों नहीं चल रहा है और हिमकेयर का कार्ड क्यों नहीं चल रहा है? हमारे लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है इसलिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं ताकि लोगों की जान बच सके लेकिन वहां पर न आयुष्मान कार्ड चल रहा है और न ही हिमकेयर कार्ड चल रहा है।

सभापति महोदय, हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं। पूर्व की जय राम जी की सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्रों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बदली में खोला था और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पौड़ा कोठी में खोला था। सरकार के आते ही दोनों प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद कर दिए गए। मैंने सदन के अंदर भी कहा कि आप इसकी जांच करवा लो और इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगवा लो। वहां 50-55 किलोमीटर के बीच में कोई स्वास्थ्य संस्थान नहीं है। कोई दुर्घटना हो जाए तो किसी को फर्स्ट एड भी वहां नहीं मिलती। हमारा बंदली का प्राइमरी हेल्थ सेंटर था लेकिन आपने राजनीतिक द्वेष के चलते उन स्वास्थ्य संस्थानों को बंद कर दिया जिसके कारण हमारे क्षेत्र में बहुत दिक्कत आ रही है।

सभापति महोदय, हमारे नीहरी में मेरे विधान सभा क्षेत्र का बड़ा केंद्र और तहसील हेडक्वार्टर है। यह सुंदरनगर का दूसरा बड़ा केंद्र है। वहां पर अगर आप देखेंगे तो हमने भवन निर्माण का कार्य शुरू किया था। आज उस भवन निर्माण का कार्य रोक दिया गया है और कहा गया है कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं।

अगर वह भवन बन जाता तो उस क्षेत्र के लोगों को वहीं पर स्वास्थ्य सुविधा मिलती क्योंकि वह क्षेत्र ऐसा है जो सुंदरनगर,कसोग,तत्तापानी और सुन्नी की तरफ

25.08.2026/1555/बी.एस./.-3

से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हम चाहते थे कि उस क्षेत्र के लोगों को वहीं पर स्वास्थ्य सुविधा मिले लेकिन भवन का निर्माण कार्य बंद करके ठेकेदार को कह दिया गया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं।

मैं बार-बार सदन के अंदर कह रहा हूं आप कर हरे हैं कि सरकार को सुझाव दिया जाएं। मैं यही सुझाव दे रहा हूं कि उस क्षेत्र की जनता का क्या कसूर है? मेरे विधान सभा क्षेत्र की और साथ लगते नाचन विधान सभा क्षेत्र की जनता का क्या कसूर है? इसलिए उस भवन निर्माण कार्य को जल्द-से-जल्द शुरू करवाया जाए। ऐसा मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री राकेश जम्वाल : सभापति महोदय, एक-दो बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के नीहरी की मैंने बात कही। आज मात्र दो डॉक्टर वहां पर हैं। दुर्गम क्षेत्र में हमारी सी0एच0सी0 है लेकिन डॉक्टर वहां पर नहीं हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर दूसरे क्षेत्र से किसी डॉक्टर को डिप्यूट करेंगे तो उस दूसरे क्षेत्र में कमी आएगी।

इसके साथ मेरे रोहांडा में भी डॉक्टरों की कमी है और बहकी धार मेरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और जुड़ोल में आज वहां पर डॉक्टर नहीं हैं। उस क्षेत्र के लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।

इसके साथ सुंदरनगर विधान सभा क्षेत्र का डहर का सिविल हॉस्पिटल है। पूर्व की आदरणीय जय राम जी की सरकार ने उसको सी0एच0सी0 से सिविल हॉस्पिटल बनाया था। भवन को तैयार करके जनता को समर्पित कर दिया गया था और 108 एम्बुलैंस की सुविधा वहां पर दे दी गई थी। इसके बावजूद वहां पर डॉक्टरों की कमी है। आप कल्पना करो कि मात्र दो डॉक्टर उस इलाके डहर में हैं जो सुंदरनगर और मण्डी के साथ-साथ बिलासपुर के क्षेत्र को भी कैटर करने वाला एरिया है।

25.08.2026/1555/बी.एस./.-4

सभापति महोदय, यहां पर सत्ता पक्ष की ओर से बार-बार पूर्व की सरकार को और केंद्र की सरकार को दोषी ठहराया जा रहा है। लेकिन मैं पूर्व की जय राम जी की सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रयास किया।

मैं केंद्र की मोदी जी की सरकार और जगत प्रकाश नड्डा जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे हिमाचल के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स जैसा संस्थान दिया है।

लेकिन सरकार से और मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ सुझाव मैंने प्रदेश स्तर पर भी रखे हैं और कुछ अपने विधान सभा क्षेत्र के भी सुझाव रखे हैं। निश्चित तौर पर सभापति महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार का अब अंतिम वर्ष है इसलिए इसमें तो कुछ सुधार कर दीजिए और ऑक्सीजन प्लांट चला दीजिए।

जो भवनों के निर्माण कार्य रुके हुए हैं उन्हें शुरू करवा दीजिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए वे उन्हें मिलें। नियम-130 के अंतर्गत श्री विपिन सिंह परमार जी और अन्य साथियों द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। मैं यह उम्मीद करता हूं कि सरकार इन सभी सुझावों पर विचार करके उन पर अमल करेगी।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

25.08.2026/1600/DT/DC-1

श्री संजय अवस्थी : धन्यवाद सभापति महोदय। नियम-130 के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो प्रस्ताव मेरे सहयोगी साथियों ने लाया है उस पर चर्चा हो रही है और मैं भी इस चर्चा में भाग लेने के लिए अपने आपको शामिल कर रहा हूं।

किसी भी सरकार का मुख्य ध्येय और सर्वोच्च प्राथमिकता बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य के संदर्भ में बेहतर शिक्षा प्रदान करना तथा हर गांव और हर क्षेत्र को सड़कों से जोड़ना एवं बेहतर सड़क व्यवस्था उपलब्ध करवाना रहती है।

पूर्व में पांच वर्ष जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जब उसके बाद उस सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ तो चुनाव हुए। पांच वर्ष की नाकामी का आईना जब प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करके दिखाया तो वर्ष 2022 में कांग्रेस को जनादेश मिला। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू प्रदेश के मुख्य मंत्री बने। जो परिस्थितियां थीं चाहे वह कर्मचारी वर्ग हो या किसी भी विभाग की बात करें तो अव्यवस्था का आलम था। मुख्य मंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का संकल्प लिया। जो अव्यवस्था हमारे विपक्ष के साथी विरासत में फैला कर गए थे उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का जो मूलभूत ढांचा था वह अव्यवस्थित था और इनके द्वारा उसको व्यवस्थित करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई थी। मुख्य मंत्री श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया और उस व्यवस्था परिवर्तन के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम करना शुरू किया। आज तीन वर्ष आठ महीने वर्तमान सरकार के बीत जाने के बाद उस व्यवस्था परिवर्तन का परिणाम स्वास्थ्य सुविधाओं में देखने को आया है। मैं बड़ा हैरान होता हूं। मुझसे पूर्व जो हमारे विपक्ष के साथी इस चर्चा में भाग ले चुके हैं, वह चाहे नेता प्रतिपक्ष हों चाहे पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री हों और चाहे इस चर्चा में प्रस्ताव लाने वाले सदस्य हो, मैं तो यह समझता हूं कि श्री विपिन सिंह परमार जी को आज भी इस बात का दुख है कि क्यों उनको स्वास्थ्य मंत्री से हटाकर अन्य जिम्मेदारी दी गई। उसका कारण मैं नहीं जानना चाहूंगा। वह बेहतर जानते हैं और उनके साथी भी बेहतर जानते हैं। लेकिन जब किसी भी विभाग में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो और पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से बदलाव आज स्वास्थ्य सुविधाओं में आया है और बेहतर स्वास्थ्य

25.08.2026/1600/DT/DC-2

सुविधाएं आज प्रदेशवासियों को मिल रही हैं तो विपक्ष के साथियों का भी यह नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है कि उसको एप्रिशिएट करें। लेकिन क्योंकि इनकी एक ही मंशा है और इनका एक ही संकल्प है कि विपक्ष में रहकर केवल विरोध करना है इसलिए ये अपना धर्म निभा रहे हैं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो हमारा जो सिविल हॉस्पिटल अर्की था वह एकमात्र रेफरल हॉस्पिटल था। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दारला घाट घोषित तो हो गया था और बिल्डिंग बनकर भी तैयार हो गई थी लेकिन पद सृजित न होने की वजह से वह खाली बिल्डिंग बनकर रह गई थी और फंक्शनल नहीं हो पाई थी। सिविल हॉस्पिटल कुनिहार में डॉक्टर्स का अभाव था। इसी तरह से प्राइमरी हेल्थ सेंटर चाहे वह चंडी हो, चाहे वह बागा हो और चाहे वह गनागू घाट हो, वहां पर भी डॉक्टर्स का अभाव था और डॉक्टर्स नहीं थे। सरकार माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में बनी और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

25.08.2026/1605/एच.के.-एन.जी./1

श्री संजय अवस्थी.......... जारी

सरकार माननीय मुख्य मंत्री, श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में बनी और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के प्रयास किए गए। आज उसका परिणाम यह है कि सिविल हॉस्पिटल अर्की में 17 डॉक्टर कार्यरत हैं और आज वह रेफरल हॉस्पिटल नहीं रहा, बल्कि

दूर-दराज के क्षेत्रों से भी लोग वहां पर अपना इलाज करवाने आते हैं। यह व्यवस्था परिवर्तन का ही परिणाम है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसी तरह से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, दाड़लाघाट में पद सृजित नहीं थे—न डॉक्टर्स के और न पैरामेडिकल स्टाफ के—तो मैंने माननीय मुख्य मंत्री से आग्रह किया और माननीय मुख्य मंत्री ने तुरंत प्रभाव से इस पर संज्ञान लिया तथा पद क्रिएट किए गए। आज वहां पर डॉक्टर्स, नर्सेज और फार्मासिस्ट हमारे क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। यह व्यवस्था परिवर्तन है, जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं।...(व्यवधान) माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा जी, आपने बिल्कुल गलत कहा और आपने तो अपना आंकड़ा भी गलत दिया। आपने मलोखर हॉस्पिटल की बात करी तो वहां पर आज भी एक डॉक्टर कार्यरत है और वह किसी ट्रेनिंग पर गई हुई हैं। ट्रेनिंग में जाने के बाद वहां पर दूसरे डॉक्टर डेपुटेशन के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वह मेरे क्षेत्र के साथ लगता क्षेत्र है। आप इस बात पर जरूर ध्यान दें और माननीय सदन को गुमराह न करें।...(व्यवधान)

Chairman: Please don't disturb. ...(Interruption) Please don't disturb. Let him complete.

श्री संजय अवस्थी : सभापति महोदय, पूर्व सरकार के समय में जब कोई गंभीर बीमारियां हो जाती थीं, तो उसके उपचार के लिए हमारे पेशेंट्स को बाहरी राज्यों में जाना पड़ता था। मुझे याद है कि जो निवर्तमान मुख्य मंत्री थे और आज प्रतिपक्ष के नेता हैं, वह भी अपना इलाज करवाने के लिए दिल्ली गए थे। ये आपके समय की स्वास्थ्य सुविधाएं थीं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं।

25.08.2026/1605/एच.के.-एन.जी./2

सभापति महोदय, मैं आपके संज्ञान में कुछ बातें रखना चाहता हूं कि आज इन तीन वर्ष और आठ महीने के कार्यकाल में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और मरीजों को विशेष

स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने व आधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। सबसे पहले हम यदि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सुधार रोबोटिक सर्जरी का हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हुई है। चाहे वह आई0जी0एम0सी0 हो, चाहे टांडा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय हो, इसके साथ-साथ चमियाना हॉस्पिटल में भी यह सुविधा आरंभ की गई है जिसका लाभ हमारे प्रदेशवासियों को मिल रहा है। इस सुविधा की प्राप्ति के लिए हमारे लोग बाहरी राज्यों में जाते थे। अब प्रदेश में आम आदमी भी इस आधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकता है। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो रोबोटिक सर्जरी का खर्च लगभग पांच लाख रुपये आता है, लेकिन आज यह सुविधा प्रदेश में ही उपलब्ध होने के कारण 30,000/- रुपये से 80,000/- रुपये में हमारे लोगों को उपलब्ध हो रही है। यह व्यवस्था परिवर्तन है, जो आपको भी पता है, लेकिन आप चुप बैठे हैं।

सभापति महोदय, आई0जी0एम0सी0 शिमला में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा प्रदान करने के लिए 8 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा 256-स्लाइस सीटी स्कैन मशीन, जोकि सबसे हाई-एंड मशीन है, सबसे अत्याधुनिक मशीन है, उस मशीन की खरीद के लिए 12 करोड़ रुपये माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नेस्वीकृत किए हैं। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आज आई0जी0एम0सी0 में पैट स्कैन की सुविधा शुरू हुई है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच के लिए मरीजों को बाहरी राज्यों में नहीं जाना पड़ता। यह क्या कम बदलाव आपको देखने में मिल रहा है? टांडा और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालयों में पैट स्कैन मशीन की खरीद के लिए टेण्डर किए जा चुके हैं और आने वाले समय में वहां के लोगों को भी इसकी सुविधा मिलेगी।

25.08.2026/1605/एच.के.-एन.जी./3

सभापति महोदय, शिमला के चमियाना हॉस्पिटल और आई0जी0एम0सी0 शिमला में अत्याधुनिक 3 ट्रेस्ला एम0आर0आई0 की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जिसका लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है। माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा जी, आप मंद-मंद मुस्कुरा रहे हैं और आपको भी इस बात की जानकारी है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चमियाना हॉस्पिटल, आई0जी0एम0सी0 शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक ऑटोमेटिक लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। यह वह सुविधा है, जिसमें एक बार लिए गए ब्लड सैंपल से कई तरह की जांच करवाई जा सकती है।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

25.08.2026/1610/HK/PB/1

श्री संजय अवस्थी जारी...

जिसकी रिपोर्ट में शत-प्रतिशत एक्यूरेसी होगी। आज यहां ऐसी मशीन लगने जा रही है। क्या आपको (विपक्ष) यह दिखाई नहीं देता? आप अपना राजनीतिक चश्मा बदलें तो आपको सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मैं आपको यह सुझाव भी देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस बार मुख्य मंत्री जी ने 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर चीफ गेस्ट के तौर पर एक घोषणा की है। उसमें आउटसोर्स पर कार्यरत स्टाफ नर्सों, फार्मसिस्ट, ऑपरेशन थिएटर सहायकों और लैबोरेटरी टेक्नीशियन्स के लिए 25,000 रुपये प्रति माह वेतन तथा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18,000 रुपये प्रति माह संशोधित पारिश्रमिक की घोषणा की गई है। क्या यह कम है? पूर्व की भाजपा के समय में नौकरियां तो छोड़िए, जो लोग कार्यरत थे उन्हें प्रॉपर सैलरी भी नहीं दी जाती थी। सरकार ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स का स्टाइपेंड 40,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रति माह किया है और सीनियर रेजिडेंट सुपर स्पेशलिस्ट का स्टाइपेंड एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक लाख तीस हजार रुपये प्रति माह किया है। क्या यह बदलाव भी आपको नजर नहीं आता?

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी अभी सदन में नहीं है। उन्होंने एम्स की बात की थी और कहा था कि यह एम्स किसने बनाया? मैंने जवाब दिया था कि एम्स कांग्रेस पार्टी ने बनाया। इसकी शुरुआत करने का विजन नेहरू जी का था। वर्ष 1956 में जब नेहरू जी देश के प्रधान मंत्री थे उस समय पहला एम्स शुरू किया गया था। यह उनका विजन और दूरदर्शिता थी। आज पूरे देश में एम्स स्थापित किए गए हैं और बिलासपुर में भी एम्स स्थापित हुआ है। उसका क्रेडिट विपक्ष लेना चाह रहा है लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस मूलभूत ढांचे की शुरूआत कहां से हुई थी।

सभापति महोदय, इसके अलावा माननीय सदस्य ने हिमकेयर की बहुत चर्चा की है। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि हिमकेयर की सुविधा अधिकतर पात्र लोगों को नहीं मिली है। यह योजना केवल चुनिंदा और मुट्ठीभर लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी जिसमें प्रदेश सरकार मुख्य मंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह,

25.08.2026/1610/HK/PB/2

सुक्खू जी के नेतृत्व में अमेंडमैंट कर रही है। इस योजना में जो आर्थिक अनियमितताएं हुई हैं तथा जिन लोगों ने इसका दुरुपयोग करके लाभ उठाया है उन पर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में प्रदेश की जनता के सामने उनके चेहरे सामने आएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हिमकेयर की योजना में अमेंडमैंट होने के बाद इसे इन्श्योरेंस से जोड़ा जाएगा और इसका लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा। माननीय सदस्य श्री रणधीर जी ने एक बात जरूर कही है कि जो फीमेल हेल्थ वर्कर और हेल्थ वर्कर्स की पोस्ट खत्म की गई है। उसके संबंध में सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जिन्होंने ए0एन0एम0 का डिप्लोमा किया है और जो आज बेरोजगार है हमें उनके लिए नीति बनाने की जरूरत है। ए0एन0एम0 का डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी हेल्थ वर्कर की पोस्ट के लिए पात्र होते हैं। इसलिए इनके बारे में विचार करने की जरूरत है। पूरे प्रदेश स्तर पर काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ए0एन0एम0 का डिप्लोमा किया है।

इसके अतिरिक्त, जाइका प्रोजेक्ट के सहयोग से 1,710 करोड़ रुपये की डी0पी0आर0 बनाकर दी गई है। इसके तहत स्वास्थ्य उपकरणों और स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने के लिए 1,710 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आने वाले समय में इसका लाभ हमारे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। जाइका चरण दो के तहत 1,617 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृति के लिए भेजी गई है जिसकी स्वीकृति जल्दी ही मिल जाएगी। इसके तहत बहुत से आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे जिसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिलेगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में सर्वांगीण विकास हुआ है और प्रदेश सरकार द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई हैं।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

25.08.2026/1615/वाई0के0/ए0पी0-01

श्री संजय अवस्थी जारी .....

जिसमें प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक-एक तथा लाहौल-स्पीति एवं भरमौर विधान सभा क्षेत्र में दो-दो स्वास्थ्य संस्थानों का स्तर उन्नत करके प्रदेश में कुल 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले गए हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हर केंद्र में मशीनरी एवं उपकरणों की व्यवस्था के लिए एक करोड़ रुपये प्रति केंद्र दिए गए हैं। इनमें छह-छह विशेषज्ञ चिकित्सक, 134 प्रकार की प्रयोगशाला सुविधाएं, आधुनिक एम0आर0आई0 और सी0टी-स्कैन मशीन, आठ स्टाफ नर्स, दो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और पर्याप्त संख्या में पैरामेडिकल स्टाफ सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि इस बात को भी सुनिश्चित करें। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पी0जी0 मेडिकल सीटों की संख्या जो पहले आपके समय में 270 हुआ करती थी, उन्हें आज 597 करने का प्रस्ताव रखा है। एक ही चरण में पी0जी0

सीटों में इतनी बड़ी बढ़ोतरी पहली बार प्रस्तावित की गई है। इसका उद्देश्य हमारे प्रदेश में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना और हर पी0एच0सी0 में डॉक्टरों की सुविधा सुनिश्चित करना है। इस दृष्टिकोण से यह फैसला लिया गया है। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट के मासिक वेतन में 78 प्रतिशत की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस निर्णय के तहत जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर का मासिक वेतन जो पहले 33,660 रुपये हुआ करता था। अब सीधे 60,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, उनसे न केवल प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं बल्कि हिमाचल प्रदेश देशभर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल राज्य के रूप में स्थापित हुआ है, यह हमारा व्यवस्था परिवर्तन है। विपक्ष के साथियों ने जो प्रस्ताव नियम-130 के तहत लाया है, मैं इसका विरोध करता हूं और आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को

25.08.2026/1615/वाई0के0/ए0पी0-02

वापस लें। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो बेहतर कार्य किए हैं, उन्हें स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार का साथ दें। पिछले तीन साल आठ महीनों में जो आपकी गलतियां रही हैं और जब-जब विधान सभा का सत्र हुआ है, उसमें आपने लगातार विघ्न पहुंचाने की कोशिश की है तथा मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए वॉकआउट करने की जो परंपरा आपने शुरू की है, उस पर प्रदेश की जनता के सामने आपको जवाब देना है। अभी लगभग सवा साल का कार्यकाल बचा है इसमें अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं और प्रदेश सरकार की जनहित की योजनाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग दें, धन्यवाद।

25.08.2026/1615/वाई0के0/ए0पी0-03

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्रीमती रीना कश्यप भाग लेंगी।

श्रीमती रीना कश्यप : सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत जो विषय इस सदन में चर्चा के लिए आया है, उस विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। हमारे प्रदेश की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को लेकर मैं कहना चाहूंगी कि अभी भी पूरे प्रदेश में बहुत से ऐसे स्वास्थ्य संस्थानों के भवन हैं जो निर्माणाधीन हैं और अधूरे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि उन निर्माणधीन भवनों का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के जो रिक्त पद हैं, उन पदों को भी जल्दी-से-जल्दी भरा जाए। माननीय मंत्री जी, मैं सीधे अपने विधान सभा क्षेत्र में आना चाहूंगी। अगर मैं अपने पच्छाद विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो मैं कहना चाहूंगी कि कहीं-न-कहीं पच्छाद विधान सभा क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं। अगर मैं सराहां अस्पताल की बात करूं तो सराहां अस्पताल 30-से-40 पंचायतों का केंद्र है, लेकिन वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं शून्य के बराबर हैं। वहां डॉक्टरों के 11 पदों में से केवल चार-या-पांच पद ही भरे हुए हैं। अगर पच्छाद ब्लॉक की बात करूं तो वहां से पी0एच0सी0 में जो डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं, उन्हें भी डेपुटेशन पर सराहां भेज दिया जाता है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। अभी जब मैं दो-

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

25.08.2026/1620/AT/YK/01

श्रीमती रीना कश्यप जारी....

तीन दिन पहले मैं पी0एच0सी0 जैहर गई थी। वहां मैंने लोगों से पूछा कि क्या हमारी पी0एच0सी0 जैहर में डॉक्टर नहीं है? उन्होंने बताया कि डॉक्टर तो है, मगर मैडम सात दिन में केवल दो दिन ही वहां बैठते हैं, बाकी दिनों में उन्हें डेपुटेशन पर सरांह भेज दिया

जाता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जैहर के लोग भी परेशान हैं और सरांह के लोग भी परेशान हैं। सरांह के लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि जो मरीज चेकअप करवाने आते हैं, जब उन्हें तीन या पांच दिन बाद दोबारा बुलाया जाता है, तो उन्हें डॉक्टर मिलते ही नहीं हैं। इस कारण उन्हें अच्छी तरह से जो इलाज और सुविधा मिलनी चाहिए, वह वहां नहीं मिल पा रही है।

जब मैं उस पी0एच0सी0 में निरीक्षण के लिए गई तो मैंने देखा कि वहां के भवन की स्थिति भी ठीक नहीं थी। भवन के दरवाजे और खिड़कियां तक टूटे हुए थे, माननीय मंत्री जी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि पी0एच0सी0 जैहर और पी0एच0सी0 डोंग्याद के भवनों के निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करवाएं।

मैं सराह हॉस्पिटल की बात करूं तो, जब हमारी सरकार थी और आदरणीय मुख्य मंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने, उस समय इस हॉस्पिटल को 100 बेड का करने की बहुत लंबे समय से मांग थी। हमारी सरकार ने इस हॉस्पिटल को 100 बेडेड कर दिया था, परंतु व्यवस्था परिवर्तन के कारण हमारे सरांह हॉस्पिटल को 100 बेडेड से डिनोटिफाई कर दिया गया। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इसे पुनः 100 बेडेड किया जाए। साथ ही, वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन की भी व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें या तो सोलन जाना पड़ता है या फिर शिमला जाना पड़ता है। अगर इस हॉस्पिटल को 100 बेडेड से डिनोटिफाई नहीं किया गया होता, तो आज सरांह में हमें बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही होतीं। इसलिए इस विषय पर आप जरूर, माननीय मंत्री जी, स्पष्ट करें।

सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार आपने कहा था कि हर विधान सभा में आदर्श संस्थान खोले जा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी कि हमारे पच्छाद में यह संस्थान कब खुल रहा है? कभी आपने यहां सदन में खड़े होकर स्पष्ट रूप से मुझे कहा था कि नारग में आदर्श संस्थान खोला जाएगा।

25.08.2026/1620/AT/YK/02

अगर माननीय मंत्री जी अब उड़ती-उड़ती खबर आ रही है कि आप इसे सरांह में खोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सदन में कहते हैं तो उस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि नारग में नहीं खुलेगा और अगर सरांह में खुलेगा, तो मैं कहना चाहूंगी कि कहीं न कहीं नारग की जनता और सरांह की जनता के अधिकारों का हनन न हो जाए। यह बात मैं इस सदन में स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी। इस विषय को लेकर आप जरूर विचार करें कि आदर्श संस्थान नारग में खुले और जो 100 बेडेड हॉस्पिटल है, वह सरांह में पुनः किया जाए। इस विषय पर आप आज ही इस सदन में स्पष्ट उत्तर दें। माननीय मंत्री जी, मैं राजगढ़ अस्पताल की बात करूं तो यह भी हमारी 30 से 40 पंचायतों का केंद्र है और रेणुका विधान सभा के लोग भी यहीं पर आते हैं। मगर यहां की परिस्थितियों की अगर हम बात करें, तो जब हमारी सरकार थी और आदरणीय जय राम ठाकुर जी हमारे मुख्य मंत्री थे, उस समय वहां कम से कम 17-18 डॉक्टर पोस्टेड थे। आज की परिस्थिति ऐसी है कि वहां चार से पांच डॉक्टर भी नहीं हैं। वहां काफी लंबे समय से ब्लड बैंक की मांग थी कि अस्पताल में ब्लड बैंक होना चाहिए। मैं काफी समय से जब भी सदन में बात रखती हूं, तो यही बात रखती हूं कि वहां यह व्यवस्था होनी चाहिए। इस संबंध में विभाग और अस्पताल के माध्यम से आपको कई बार लिखित रूप में भी जानकारी भेजी गई है। वहां एक बहुत बड़ी समस्या अल्ट्रासाउंड मशीन की थी। हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन लगभग आठ से नौ महीनों से खराब थी। कई बार विभाग के माध्यम से इसकी सूचना भी दी गई, मगर उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। मजबूरन मुझे कंपनी में खुद फोन करना पड़ा, क्योंकि वहां यह कहा गया कि जो मशीन सरकार ने दी है, वही ठीक करवाएगी। यह बात सही नहीं लगती। मगर फिर भी मैंने फोन किया और अब अल्ट्रासाउंड मशीन ठीक हो गई है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मशीन तो ठीक हो गई है, मगर उसे ठीक करवाने में जो राशि लगी है, उसका भुगतान किया जाना है। इसलिए आप यहां से सी0एम0ओ0 नाहन को आदेश करें कि जल्दी से जल्दी अल्ट्रासाउंड मशीन को ठीक करवाने में लगी राशि का भुगतान किया जाए। अगर माननीय मंत्री जी यह नहीं कर सकते हैं, तो वह भी आज हमें बता दें, हम स्वयं करेंगे। यह बात मैं इस सदन में कहना चाहती थी। कहीं न कहीं इतने लंबे समय तक अल्ट्रासाउंड मशीन का खराब रहना विभाग की लापरवाही है। इसलिए इन चीजों को माननीय मंत्री जी आपको स्वयं देखना पड़ेगा। साथ ही,

---

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी ......

25.08.2026/1625/AV/AG/1

श्रीमती रीना कश्यप जारी

अगर मैं सब-सेंटर्ज की बात करूं तो भूज्जल, टपरोली, नेई नेटी, भयानाघाट, कोठिया जाजर, जयहर, सिरमौरी मंदिर, मड़ीघाट, कुईना काटली, वासनी, सरसू, देवल टिक्करी, ढंगयार, डिंगर किन्नर, नया गांव, नेरी नावण और शाड़िया; हमारे पास इतने सारे सब-सेंटर्ज हैं परंतु इन सबमें ताले लटके हुए हैं। इनमें किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है। वहां के लोगों की ऐसी कोई डिमाण्ड नहीं है जो आप रोबोट की बात करते हैं। वहां के लोगों की किसी भी प्रकार के रोबोट हेतु मांग नहीं है। वहां के लोग केवल यह चाहते हैं कि इन सब-सेंटर्ज में केवल पी0सी0एम0 इत्यादि छोटी-मोटी दवाई देने की व्यवस्था की जाए यानी उनके ताले खुल जाए तो अच्छा रहेगा। मेरा मंत्री जी से यह निवेदन रहेगा कि आप इस विषय के बारे में जरूर सोचें।

मंत्री जी, मैं आपके ध्यान में एक बात जरूर लाना चाहती हूं। अगर इन विषयों को लेकर आपने कड़ा संज्ञान नहीं लिया तो जनता आपसे जरूर पूछेगी 'क्या किया, भई क्या किया, इन चार वर्षों में क्या किया? फिर ऐसा न हो कि (***)। ऐसी बात नहीं आनी चाहिए और साथ में सहारा योजना और हिमकेयर योजना बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये योजनाएं गरीबों के हित को मद्देनज़र रखकर बनाई गई हैं। मेरा सरकार और मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि आप इन योजनाओं को पुनः चलाएं।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : माननीय सदस्या द्वारा जो (***) कहा गया, इसको एक्सपंज किया जाए।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

25.08.2026/1540/AV/AG/3

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री किशोरी लाल चर्चा में हिस्सा लेंगे।

श्री किशोरी लाल : सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत सदन में श्री विपिन सिंह परमार जी, श्री नीरज नैय्यर जी, डॉ0 जनक राज जी और श्री पवन कुमार काजल जी स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्वास्थ्य से जुड़े हुए अन्य विषयों पर चर्चा लेकर आए हैं। मैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।यह स्वास्थ्य संबंधी प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की जरूरत जीवन में किसी भी इंसान को कभी भी पड़ सकती है। इसलिए स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। मैं यहां पर बैजनाथ विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। वर्ष 1972 से पहले बैजनाथ चुनाव क्षेत्र में एक भी होस्पिटल और पी0एच0सी0 नहीं थी। वहां पर केवल एक आयुर्वैदिक डिस्पेंसरी हुआ करती थी। वहां पर लोगों को झोला छाप डॉक्टर्ज, वैद्य और कविराज से अपना इलाज करवाना पड़ता था तथा डिलीवरी के समय महिलाओं को दाइयों के सहारे रहना पड़ता था। वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत बुरी हालत थी। वर्ष 1972 में वहां से आदरणीय पं0 संत राम जोकि अब हमारे बीच में नहीं है, चुनकर विधान सभा में आए। उन्होंने अपने प्रयत्नों से वहां पर एक एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर तैनात किया। वहां पंचायती राज के भवन में उस डॉक्टर ने अपनी सेवाएं देनी शुरू की थी। लोगों को उस एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर का तब पता चला कि इस प्रकार से एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर भी होते हैं। उससे पहले हमें इंजैक्शन लगवाने के लिए सिविल होस्पिटल पालमपुर या धर्मशाला जाना पड़ता था। समय बीतता गया और प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री बनें तथा प्रदेश सरकार में पं0 संत राम जी मंत्री बनें।

एन0एस0 द्वारा जारी

25-8-2026/1630/NS-AG/1

श्री किशोरी लाल-----जारी

तो बैजनाथ को 50 बिस्तरों का अस्पताल और भवन मिला। स्वास्थ्य सेवाएं गांव-गांव तक फैलीं। पी0एच0सीज0 खुलीं और हर पांच किलोमीटर के अंदर एक पी0एच0सी0 है। वहां पर डॉक्टर और स्टाफ उपलब्ध है। अब बैजनाथ हॉस्पिटल 100 बिस्तरों का हो गया है। वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के बीच मैंने तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी से आग्रह किया था और उन्होंने उस हॉस्पिटल को 100 बिस्तरों का किया। आज वहां पर 17 डॉक्टर उपलब्ध हैं। मैं मुख्य मंत्री श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने बैजनाथ सिविल हॉस्पिटल को आदर्श हॉस्पिटल बनाया। यहां कभी एक एम0डी0 डॉक्टर हुआ करता था और आज वहां छह एम0डी0 डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज वहां ऑपरेशन भी हो रहे हैं और लोगों को उस हॉस्पिटल से अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं।

इसके साथ ही हमारी पी0एच0सी0 में भी डॉक्टर उपलब्ध हैं और उनके भवन भी बने हुए हैं। बैजनाथ में स्वास्थ्य सेवाओं की अच्छी सुविधाएं हैं लेकिन फिर भी जहां कमी है उसे पूरा करने का मैं निवेदन करना चाहता हूं। यहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी बैठे हैं। हमारा सिविल हॉस्पिटल तैयार है जो पिछली सरकार के समय सी0एच0सी0 हुआ करता था और अपग्रेड होकर सिविल हॉस्पिटल बना। वहां छह डॉक्टरों के पद हैं जिनमें से तीन डॉक्टर इस वक्त वहां कार्यरत हैं। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने वहां दो डॉक्टरों और नर्सों की तैनाती की है। इससे काफी हद तक वहां लोगों को जो मुश्किल थी उसका हल हुआ है। फिर भी वहां जो कमी है उसे पूरा किया जाए। वहां के लोगों की एक डिमांड है कि एक एम0डी0 डॉक्टर उपलब्ध करवाया जाए। मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि लोगों की मांग के अनुसार वहां एक एम0डी0 डॉक्टर उपलब्ध करवाया जाए। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं जितनी अच्छी होंगी लोगों को उतनी ही कम दिक्कतें होंगी।

यहां हमारे कई साथी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ कांग्रेस की गारंटियों की बात कर रहे थे लेकिन जो गारंटियां भाजपा ने की थीं उनकी बात किसी ने नहीं की। यहां कहा गया कि 1500 रुपये का वायदा किया है, किया है तो सरकार उसे पूरा

25-8-2026/1630/NS-AG/2

करेगी और यह सरकार का फर्ज है। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में चर्चा हो रही थी और उसके बीच ऐसी बातें जोड़ना शोभा नहीं देता। अगर साफ तौर पर कहा जाता कि हमने भी वायदे किए थे कि दो करोड़ बच्चों को नौकरी देंगे, 15 लाख रुपये खाते में डालेंगे और महंगाई कम करेंगे, तब मैं मानता कि यह बैलेंस हो गया लेकिन वह बात किसी ने नहीं कही। मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि यह प्रस्ताव केवल स्वास्थ्य सेवाओं का था और इस पर ही चर्चा होनी चाहिए थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इधर-उधर की ऐसी बातें जोड़ना समय बर्बाद करना है। इससे कुछ नहीं मिलता। सरकार आज जो कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास कर रही है। सरकार ने कई हॉस्पिटल्ज में रोबोटिक सर्जरी शुरू की है जिसका यहां जिक्र आया और यह सराहनीय कदम है। पहले लोगों को रोबोटिक सर्जरी के लिए बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ता था लेकिन आज प्रदेश में ही इलाज हो रहा है।

सभापति महोदय, इन स्वास्थ्य सेवाओं को मेंटेन करना और इनमें जो भी कमियां हैं, उन्हें दूर करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उन्हें दूर कर रही है। वर्तमान सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए हैं उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। उनके प्रयासों से हर विधान सभा क्षेत्र में आदर्श हॉस्पिटल स्थापित किए जा रहे हैं जिससे लोगों को फायदा होगा। मैं अपने बैजनाथ की बात करूं तो पहले वहां एक एम0डी0 डॉक्टर तैनात होता था जबकि आज वहां छह-छह एम0डी0 डॉक्टर हैं। लोगों के एडमिशन्ज हो रहे हैं और उनका इलाज हो रहा है। लोगों को तभी बाहर जाना पड़ता है जब कोई गंभीर बीमारी हो। कांगड़ा के लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज,टांडा कांग्रेस पार्टी की देन है और स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। टांडा में बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। यह बात ठीक है कि वहां बहुत भीड़ होती है जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी होती है

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

25.08.2026/1635/RKS/एएस-1

श्री किशोरी लाल जारी

लेकिन एडमिशन मिल जाए तो वहां अच्छा इलाज भी उपलब्ध है। वहां पर बिना पैस खर्च किए बेहतर उपचार मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां मरीजों की संख्या ज्यादा है लेकिन फिर भी डॉक्टर दिन-रात सेवाएं देकर व्यवस्था को मेंटेन कर रहे हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि वहां जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए सरकार प्रयास करेगी क्योंकि मैं स्वयं भी कई बार टांडा गया हूं। लोगों को पर्ची बनवाने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। इस व्यवस्था में भी सुधार किया जाना चाहिए ताकि लोगों की पर्चियां आसानी से बन सकें और उनकी एडमिशन समय पर होकर उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। यदि पिछली सरकार के समय स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी थीं तो कोविड काल के दौरान जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उन्हें भी याद किया जाना चाहिए। पूरे देश में कोविड महामारी फैली थी और हिमाचल प्रदेश में भी सरकार ने जगह-जगह कोविड सेंटर खोले थे। मैं बैजनाथ की बात करना चाहता हूं। वहां पंचायती राज संस्थाओं के प्रशिक्षण केंद्र में कोविड सेंटर बनाया गया था। वहां दाखिल मरीजों को भोजन एक प्राइवेट संस्था उपलब्ध करवाती रही। इसी प्रकार राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पपरोला में भी कोविड सेंटर बनाया गया था और वहां भी भोजन की व्यवस्था एक प्राइवेट संस्था द्वारा की जाती रही। सरकार ने इन व्यवस्थाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो लोग अपने घरों में रहे वे तो किसी प्रकार सुरक्षित रहे लेकिन जो कोविड सेंटरों में भर्ती हुए उनमें से अनेक लोगों का प्रोपर इलाज नहीं हो पाया और कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। राजेन्द्र नामक एक व्यक्ति की धर्मपत्नी पपरोला में भर्ती थी और वहां उनकी मृत्यु हो गई। जब परिजन उनका शव घर लेकर गए तो उनके गहने गायब पाए गए। मैं कहना चाहता हूं कि कोविड काल में ऐसी घटनाएं भी सामने आई थी। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि यहां यह दुहाई दी जा रही है कि श्री जय राम ठाकुर जी के समय स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी थी लेकिन कोविड के समय भी सरकार ने लोगों को उतना ध्यान नहीं रखा जितना रखा जाना चाहिए था। कोविड के समय कभी शंख, कभी घंटियां और कभी थालियां बजाने का काम किया गया लेकिन उससे कोविड समाप्त नहीं हुआ। लोगों ने बहुत कष्ट झेले और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को मिला और आपको वहां बैठना पड़ा। मैं यह कहना चाहता हूं

25.08.2026/1635/RKS/एएस-2

कि आज हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अच्छी है। लोगों को घर-द्वार पर बेहतर उपचार उपलब्ध हो रहा है और जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। यह जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

25.08.2026/1635/RKS/एएस-3

सभापति : अब माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सभापति महोदय, इस माननीय सदन में हमारे वरिष्ठ सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाया गया है। आपने मुझे इस पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद। इस प्रदेश के अंदर जब भी कोई नई सरकार आती है तो उसके लिए स्वास्थ्य सेवाएं मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक होती है। प्रत्येक सरकार जनता के हित में नई-नई योजनाएं लेकर आती है लेकिन हिमाचल प्रदेश में यह पहली कांग्रेस सरकार है जिसने पिछली सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनाओं को बंद किया है। पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमकेयरी योजना उस समय लाई थी जब गरीब लोगों को अपने इलाज के लिए खेत-खलिहान और अपने जेवरात तक गिरवी रखने पड़ते थे। गरीब महिलाओं ने अपने परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए कई वर्षों तक अपने मंगलसूत्र तक गिरवी रखे। इन्होंने गरीबों के इस दर्द को देखकर हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना लाई थी।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

25.08.2026/1640/बी.एस./ए.एस.-1

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी...

हिमाचल प्रदेश में इस योजना से लाखों परिवार मृत्यु से बचे और उनकी संपत्तियां भी बिकने से बचीं। हिमकेयर योजना में बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे थे जो हॉस्पिटल जाते थे उनको पता था कि 5 लाख रुपये तक का इलाज निःशुल्क होता है और 5 लाख रुपये तक के इलाज से गरीब परिवार बिना किसी भय के अपना इलाज करवाते थे।

सभापति महोदय, दूसरी योजना सहारा योजना आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने लाई थी। सहारा योजना वह योजना थी जिसमें कोई मरीज घर में बिस्तर पर पड़ा हो और हिल-डुल नहीं सकता हो तो उसके लिए 3,000 रुपये की पेंशन का प्रावधान किया गया था। उनके लिए सहारा के रूप में पेंशन का प्रावधान किया गया था। वह योजना भी इन्होंने बंद कर दी है। गरीब परिवार 3,000 रुपये से अपने परिवार का काफी हद तक पालन-पोषण और खाने की व्यवस्था करता था। मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष भी इसे भी आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने शुरू किया था। इसके लिए पहले बजट में ही 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। यह योजना भी बंद कर दी गई है।

मानव जीवन के लिए स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। कोई भी सरकार आए तो सबसे पहले वह स्वास्थ्य के लिए योजनाएं बनाती है। यह पहली सरकार है जिसने स्वास्थ्य की योजनाएं बंद की हैं। आज की तारीख में सभापति महोदय, जहां गरीब परिवार 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में करवाते थे वहां आज उनको पैरासिटामोल की दवाइयां तक नहीं मिल रही हैं। यह प्रदेश के हॉस्पिटल की स्थिति बनी हुई है।

हॉस्पिटल की स्थिति यह है कि हिमकेयर योजना की देनदारी इतनी अधिक हो गई है कि हॉस्पिटल में गरीब परिवारों के इलाज नहीं हो रहे हैं। पिछली देनदारियां भी लंबित हैं। आई0जी0एम0सी0 की करीब 80 करोड़ रुपये की पिछली देनदारी है।

आई0जी0एम0सी0 सहित टांडा हॉस्पिटल और किसी भी मेडिकल कॉलेज में सहारा योजना के तहत कोई इलाज नहीं हो रहा है।

25.08.2026/1640/बी.एस./ए.एस.-2

सभापति महोदय, अभी श्री संजय अवस्थी जी ने सदन में कहा था कि चमियाणा के हॉस्पिटल को हमने बहुत सारी मशीनरी दी है। मैं इस सदन को कहना चाहता हूं कि चमियाणा में जो अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बना है उसके निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 262 करोड़ रुपये दिए हैं।

आई0जी0एम0सी0 का न्यू ओ0पी0डी0 ब्लॉक बना है। उसके लिए भी केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपये से अधिक दिए हैं। शिमला का कैंसर हॉस्पिटल बना है। उसके लिए भी केंद्र सरकार ने 230 करोड़ रुपये दिए हैं।

सभापति महोदय, एक शगूफा जिसे बोलते हैं कांग्रेस सरकार ने पूरे हिमाचल प्रदेश में छोड़ा है कि हम आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोल रहे हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में अभी तक दवाइयों का इंतजाम नहीं हुआ है और किसी टैस्ट का इंतजाम नहीं हुआ है। मैं अपने चोपाल की बात कहना चाहता हूं, मेरे बी0एम0ओ0 नेरवा और बी0एम0ओ0 मत्याना के दो पद हैं। पिछले साढ़े तीन वर्ष से दोनों बी0एम0ओ0 नहीं हैं।

मेरे चुनाव क्षेत्र में 68 डॉक्टरों के पद हैं। पिछली सरकार ने एक बार 62 डॉक्टर चोपाल में भेज दिए थे। आज वही 22 डॉक्टर पूरे चुनाव क्षेत्र में रह गए हैं। बाकी डॉक्टर मेरे चुनाव क्षेत्र से पूरे शिमला जिला के उन क्षेत्रों में भेजे गए हैं जहां कांग्रेस के विधायक हैं। चोपाल के साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से जिस तरह का अन्याय हुआ है वह बहुत गंभीर विषय है। आज चोपाल में प्राइमरी हैल्थ सैंटर और बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर और स्टाफ नर्सें नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह एक बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। अगर मशीनें हैं तो रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और इस कारण हम चौपालवासी बहुत सारी दिक्कतें झेल रहे हैं। चौपाल एक बहुत दूरदराज का क्षेत्र है। पिछली गवर्नमैंट में माननीय श्री जय राम ठाकुर जी ने एक ही कैबिनेट में 90 पोस्टें सैंक्शन की थीं जिसमें 45 चौपाल की और 45 नेरवा की थीं।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

25.08.2026/1645/DT/DC-1

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी...

इसमें एक चुनाव क्षेत्र में एक ही दिन में आठ-आठ डॉक्टरों सहित कुल 16 डॉक्टरों के पद सैंक्शन किए गए थे। ये जो रिक्त पद हैं यह केबिनेट से अप्रूव्ड हैं फिर भी मेरे विधान सभा क्षेत्र डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े हैं। इसी तरह 22-22 स्टाफ नर्सों के पद भी सैंक्शन किए गए थे लेकिन स्टॉफ नर्सिज भी केवल दो-तीन हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। पहले पूरे हॉस्पिटल में डॉक्टर थे और स्टाफ नर्सें भी थीं। अब सारी स्टाफ नर्सें ट्रांसफर कर दी गई हैं। मैं इस सदन के माध्यम सह यही कहना चाहूंगा कि चौपाल के साथ बहुत अधिक भेदभाव किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के समय हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग 200 इंस्टिट्यूशन बंद किए गए हैं और आयुष में भी लगभग 40 इंस्टिट्यूशन बंद किए गए हैं। इनमें मेरे चौपाल विधान सभा क्षेत्र के इंस्टिट्यूशन भी शामिल हैं। कम्युनिटी हैल्थ सेंटर छैला बंद किया गया है। पीवएच0सी0 को भी किरण बंद कर दिया गया है। पी0एच0सी0 उत्तराखंड की सीमा से लगे हुए क्षेत्र में खोली गई थी, यह एक बहुत ही दूरदराज का क्षेत्र है यहां पर नेटवर्क भी काम नहीं करता। अभी उस क्षेत्र के लिए सड़क भी बनी है। पी0एच0सी0 दारचना तथा पी0एच0सी0 कोटी-एनोक भी बंद कर दी गई है। चौपाल में कोई आयुष हॉस्पिटल नहीं था। आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने चौपाल में आयुष हॉस्पिटल बनाया। वह आयुष हॉस्पिटल भी वर्तमान सरकार द्वारा बंद किया गया है। इसलिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितने भी स्वास्थ्य संस्थान बंद किए गए हैं,

मैं माननीय मंत्री महोदय तथा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इन सभी इंस्टिट्यूशन को दोबारा खोल दिया जाए।

सभापति महोदय, जिस तरह से यहां पर रोबोटिक सर्जरी की बात कही जा रही है वह ठीक है। दुनिया, देश एवं प्रदेश एडवांस डवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। परंतु मेरी सरकार से विनती है कि पहले जो दूरदराज के क्षेत्रों के हॉस्पिटल हैं वहां दवाइयों का इंतजाम किया जाए। पैरासिटामोल जैसी दवाइयों का भी इंतजाम किया जाए क्योंकि आज हॉस्पिटल में कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं हो रही है। आज स्थिति

25.08.2026/1645/DT/DC-2

यह है कि मरीजों को अपनी जेब से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। जो गरीब लोग गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होते थे और जिन्हें यह विश्वास था कि हमारा इलाज इस हिमकेयर या आयुष्मान योजना के माध्यम से होगा, वे सारे गरीब लोग आज अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करें कि हॉस्पिटल में पूरी दवाइयां भेजी जाएं। जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, जितने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं और जितने हमारे सिविल हॉस्पिटल हैं, उन सभी जगहों पर, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में स्टाफ और दवाइयां जरूर भेजी जाएं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह का भेदभाव चौपाल के साथ हुआ है ऐसा हमारे बहुत सारे विपक्ष के विधायकों के विधान सभा क्षेत्रों के साथ भी हुआ है। न वहां डॉक्टर हैं न स्टाफ नर्सें हैं और न ही वहां दवाइयां मिल रही हैं।

सभापति महोदय, हमारे हॉस्पिटल की जो बिल्डिंगें बन रही थीं उनमें कुपवी क्षेत्र के हॉस्पिटल की बिल्डिंग पिछले छह वर्ष से बन रही है। पिछले साढ़े तीन वर्ष से उसका कार्य स्टैंड स्टिल पड़ा है। कुपवी क्षेत्र एक बैकवर्ड ब्लॉक है । यह बहुत ही दूरदराज का क्षेत्र है। इसलिए लोगों की सुवधिा के लिए उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग बननी चाहिए। माननीय श्री जय राम ठाकुर जी ने एकमुश्त तीन करोड़ रुपये उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने के लिए दिए थे। अभी भी पिछले साढ़े तीन वर्ष में जो कार्य मेरे पूर्व के विधायकशीप में हुआ था

उसके बाद कंस्ट्रक्शन का कार्य वहीं का वहीं रुका हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की जो बिल्डिंग्ज बन रही हैं उनमें भी जितना कार्य पिछली गवर्नमेंट के समय हुआ था, उतना ही कार्य हुआ, उसके बाद से कार्य स्टैंड स्टिल है।

सभापति महोदय, यहां न माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और न ही माननीय मुख्य मंत्री हैं। अब आग्रह भी किससे करें। परंतु हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय यहां पर हैं इसलिए इनके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि चौपाल एक बहुत दूरदराज का क्षेत्र है। एक छोर से दूसरे छोर तक लगभग 288 किलोमीटर का क्षेत्र है। कुपवी क्षेत्र ही इतना बड़ा है कि वहां 18 पंचायतें हैं और वहां पर एक ही डॉक्टर पोस्टिड है। कुपवी में केवल एक डॉक्टर लोग का इलाज कर रहा है। मेरी आपसे विनती है कि दूरदराज के क्षेत्र को आप जरूर देखें।

25.08.2026/1645/DT/DC-3

सभापति महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने कहा था कि तीन महीने के अंदर यहां पर अल्ट्रासाउंड की मशीन आ जायेगी। अभी तक नेरवा में अल्ट्रासाउंड मशीन चालू नहीं हुई है। माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं कहा था कि कुपवी का हॉस्पिटल एक वर्ष के अंदर हैंडओवर करेंगे। साढ़े तीन वर्ष हो गए हैं लेकिन अभी तक उसका कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि आप चौपाल में डॉक्टर्स जरूर भेजें। चौपाल में आज की डेट में स्वास्थ्य विभाग में 40 से ऊपर पोस्टें खाली हैं।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

25.08.2026/1650/डी.सी.-एन.जी./1

श्री बलबीर सिंह वर्मा.......... जारी

मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप हमारे लिए डॉक्टर्स जरूर भेजें। आज की डेट में चौपाल विधान सभा क्षेत्र में डॉक्टर्स की 40 से ज्यादा पोस्टें खाली हैं। स्टाफ नर्स की 30 से ज्यादा पोस्टें खाली हैं। आप हमारे किसी भी हॉस्पिटल या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में देख लें, वहां पर दवाइयां नहीं हैं। इसी प्रकार किसी भी पी0एच0सी0 में देख लें, वहां पर भी दवाइयां नहीं हैं। मेरा आग्रह है कि आप सभी स्वास्थ्य संस्थानों में दवाइयां जरूर भेजें। मेरा विधान सभा क्षेत्र दूर-दराज का क्षेत्र है और कई बार हमारी सड़कें भी बंद हो जाती हैं तो शिमला तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारे हॉस्पिटलों में आप दवाइयों का इंतजाम जरूर करें। यही मैं कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूं। यह प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और मैं समझता हूं कि इससे महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई और नहीं हो सकता। आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

25.08.2026/1650/डी.सी.-एन.जी./2

सभापति : माननीय सदस्य आपके पास तो हर सरकार में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री आर0एस0 बाली भाग लेंगे।

श्री आर0एस0 बाली : धन्यवाद, सभापति महोदय। आज नियम-130 के तहत जो प्रस्ताव हमारे वरिष्ठ सदस्य, जिन्होंने कई वर्ष इस सदन को देखा भी है, स्पीकर की भूमिका भी निभाई और हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं, वे लेकर आए हैं और यह अति आवश्यक प्रस्ताव है। इसके बारे में जो चीजें इतने दिन से बोली गईं और उन बातों के बारे में सुनकर व उनको महसूस करके, मुझे लगता है कि आज उन बातों को थोड़ा-सा खोलना और वरिष्ठ

सदस्यों के सामने, जहां पर हमारे विपक्ष के नेता भी हैं, जिन्होंने प्रदेश को पिछले पांच साल चलाया और जहां पर सत्तापक्ष के हमारे सभी सीनियर नेता जो आज सरकार में अपनी-अपनी भूमिका निभा रहे हैं।

सभापति महोदय, विपक्ष और पक्ष के सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपनी-अपनी बात रखी। इस दौरान काफी गर्मागर्मी भी हुई और काफी बातें विषय से हटकर भी हुईं। उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। आज क्योंकि स्वास्थ्य के ऊपर और एक ऐसे गंभीर विषय के ऊपर चर्चा हो रही है, जिस विषय के ऊपर पूरा प्रदेश निर्भर करता है। हर घर में और हर इंसान को जिंदगी में, जब वह अपनी जिंदगी जी रहा होता है, तो उसको बीमारी का सामना भी करना पड़ता है और हर परिवार में स्वास्थ्य की दिक्कतें भी आती हैं। इसलिए स्वास्थ्य तथा एजुकेशन—ये दो चीजें हर परिवार के लिए जिंदगी में अति महत्वपूर्ण रहती हैं। एक ऐसे विषय को हमारे सीनियर सदस्य सदन में लेकर आए हैं, तो उसके ऊपर एक गंभीर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। आज जब हेल्थ की बात हुई, विपक्ष ने बहुत-सी बातें कहीं, कल भी कहीं और अक्सर अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर आकर कहते हैं। अगर इसका डी0एन0ए0 किया जाए और इसकी सच्चाई लोगों के सामने लाई जाए, तभी हिमाचल प्रदेश की जनता जान पाएगी कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में असलियत में क्या हुआ है। हर सरकार ने इसके ऊपर काम किया और काम करना अनिवार्य भी था। पूर्व में हमारे चाचा

25.08.2026/1650/डी.सी.-एन.जी./3

जी (माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार जी) हेल्थ मिनिस्टर रहे, इन्होंने भी काम किया।

पूर्व में श्री जय राम ठाकुर जी की बड़ी दिलचस्पी हेल्थ के अंदर रही, इन्होंने भी काम किया। उससे पूर्व में राजा वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी बहुत काम किया। उससे पूर्व प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी रहे, उन्होंने भी काम किया। इसके अलावा श्री

यशवंत सिंह परमार जी, श्री राम लाल ठाकुर जी व श्री शांता कुमार जी लेकर आज तक कोई भी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं रहे जिन्होंने हेल्थ सैक्टर पर काम न किया हो। लेकिन माननीय श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी जब से मुख्य मंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए, उन्होंने पहले दिन से स्वास्थ्य क्षेत्र को अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाया और यह आंकड़ों के साथ मैं आपके आगे लेकर आया हूं। कल सभी वक्ताओं ने अपनी बात की

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

25.08.2026/1655/HK/PB/1

श्री आर0एस0 बाली जारी...

कल सभी वक्ताओं ने अपनी-अपनी बात रखी और उन्होंने सदन के समक्ष बहुत-से आंकड़े रखे। निस्संदेह जो आंकड़े रखे गए हैं उनसे हर किसी को कोई न कोई बात कहनी है। कई बार विपक्ष, विपक्ष की भूमिका के अंदर इतना खो जाता है कि वह विपक्ष का काम केवल आलोचना करना समझ लेता है। मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष की सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। देश व प्रदेश में चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हों और देश के नेता चाहे विपक्ष के अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, चाहे सुषमा स्वराज जी रही हो। हमने उन्हें कई बार बड़े हाउस अर्थात् पार्लियामेंट में बोलते हुए देखा है। हमारे देश के नेता चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, पी0वी0 नरसिम्हा राव जी और चाहे डॉ0 मनमोहन सिंह जी रहे हो, उन्होंने हमेशा पक्ष और विपक्ष की सकारात्मक भूमिका की बात की है। परंतु इस सदन में कई समय से यह देखने में आया है कि आलोचना करके जनता के आगे एक नैरेटिव सैट किया जाए।

सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों तथा इस सदन में पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों एवं वरिष्ठ सदस्यों के आगे कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। पूरे हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित बहुत काम हुआ है और हमें सदन में कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में बताया भी है। परंतु टांडा मेडिकल कॉलेज लोअर हिमाचल की लाइफलाइन है और यह मेडिकल कॉलेज मेरे विधान सभा क्षेत्र नगरोटा

बगवां में आता है। निचले हिमाचल का जो मेजर एरिया है चाहे चम्बा, हमीरपुर और सभापति महोदय आपके ज्वालाजी का क्षेत्र हो, वहां के लोग टांडा मेडिकल कॉलेज पर निर्भर हैं। इन क्षेत्रों के सभी लोग स्वास्थ्य के लिए टर्शियरी केयर और स्टेट ऑफ द आर्ट केयर के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं। सभी जानते हैं कि टांडा मेडिकल कॉलेज की स्थापना से पहले यहां टी0बी0 सैनिटोरियम हुआ करता था। यह टी0बी0 सैनिटोरियम वर्ष 1958 में चालू हुआ था। इसके आगे की प्रक्रिया चली और दिनांक 23 अक्तूबर, 1996 को डॉ0 आर0पी0जी0एम0सी0 मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई। वर्ष 1999 में एम0बी0बी0एस0 की कक्षाएं शुरू हुई और इसके बाद टांडा मेडिकल कॉलेज का सफर शुरू हुआ। टांडा मेडिकल कॉलेज टर्शियरी केयर और सुपर स्पेशियलिटी केयर में लोअर हिमाचल का पायनियर

25.08.2026/1655/HK/PB/2

इंस्टिट्यूट बना है। पूरे प्रदेश में यह आई0जी0एम0सी0 के साथ प्रदेश के पहले दो अस्पतालों में से एक है।

सभापति महोदय, इस अस्पताल की एक बड़ी दिलचस्प बात है कि यहां एक वर्ष में छह लाख ओ0पी0डी0 होती है। छह लाख ओ0पी0डी0 का मतलब है कि छह लाख मरीज अपना इलाज करवाने के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज आते हैं। हिमाचल प्रदेश की सत्तर लाख की आबादी में से छह लाख लोग केवल एक अस्पताल में अपना इलाज करवाने आते हैं। छह लाख ओ0पी0डी0 में जो आई0पी0डी0 होती है अर्थात् जिन मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल के अंदर रखा जाता है उनकी संख्या पचास हजार है। पचास हजार मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है और इन पचास हजार मरीजों में से चालीस हजार मरीजों के ऑपरेशन होते हैं। टर्शियरी केयर में चालीस हजार मरीजों के ऑपरेशन किए जाते हैं। अब स्वाभाविक है कि जब छह लाख आदमी अपने इलाज के लिए आएगा और हिमाचल प्रदेश की आबादी सत्तर लाख है तो बहुत से लोग खुश होकर जाएंगे और बहुत से लोगों को कमियां भी नजर आएंगी। हमें क्या करना है? जो मरीज खुश होकर जाते हैं उनका सम्मान करना है और उनसे सीखना है तथा जो मरीज कमियां बताते हैं उनसे भी सकारात्मक तरीके से सीखकर उन कमियों को दूर करने का काम करना है। यही टांडा

मेडिकल कॉलेज की पहली प्राथमिकता रही है। टांडा कॉलेज में छह लाख पेशेंट, पचास हजार पेशेंट भर्ती और चालीस हजार मरीजों के ऑपरेश हुए हैं।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी..

25.08.2026/1700/एच0के0/ए0पी0-01

सभापति : अभी दस माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लेना है। यदि माननीय सदन की अनुमति हो तो सदन की कार्यवाही को एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए। अब माननीय सदन की बैठक एक घंटे के लिए, यानी शाम छः बजे तक बढ़ाई जाती है।

(5.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक का समय 6.00 बजे अपराह्न तक **बढ़ाया** गया।)

श्री आर0एस0 बाली : धन्यवाद, सभापति महोदय, देखिए, कंप्लेंट और उसका समाधान किसी अस्पताल की प्रक्रिया का हिस्सा है। जहां पेशेंट आता है, वहां उसकी कंप्लेंट से सीखना और उसका समाधान करवाना, मुझे लगता है कि अस्पताल की ये दो प्राथमिकताएं होनी चाहिए। इस पर टांडा मेडिकल कॉलेज ने गहन काम भी किया है। जो नए इनिशिएटिव्स टांडा मेडिकल कॉलेज द्वारा लिए जा रहे हैं, उनके बारे में बहुत से लोगों, हमारे मित्रों और हमारे सभी बड़े भाइयों ने रोबोटिक सर्जरी की बात कही। सभी ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी नहीं चाहिए, हमें पैरासिटामोल चाहिए। वहां हमें छोटी दवाई चाहिए, आप रोबोटिक सर्जरी चाहे तो बाद में करवा दीजिए। यह बात कहीं-न-कहीं किसी हद तक ठीक भी है कि जहां रोबोटिक सर्जरी की जरूरत है, वहां छोटी दवाइयों की भी जरूरत है। उनकी बात बिल्कुल सही है। जहां छोटी दवाइयां शुरू की गई हैं। छोटी दवाइयां क्या हैं और बड़ी दवाइयां क्या और अस्पताल के ऑपरेशन क्या हैं, उसके ऊपर भी मैं अभी आता हूं। जहां हिमकेयर और सहारा की बात है, वहां काफी हद तक मैं भी

मानता हूं कि हिमकेयर को मजबूत करना बहुत जरूरी है। हिमकेयर के अंदर इस साल चौथे महीने में जो नोटिफिकेशन हुई है। उस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ चीजें ऐसी आई हैं, जिनके कारण मेडिसिन के पैसे और उससे संबंधित सुविधाओं पर असर पड़ा है। मैं वह नोटिफिकेशन भी लेकर आया हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से इसकी इल्तिजा करूंगा कि उसके अंदर काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां लोगों को जो सुविधा मिल रही थी, उस सुविधा को मजबूत करना हमारा काम है।

25.08.2026/1700/एच0के0/ए0पी0-02

उसके अंदर कहीं भी कमी नहीं आनी चाहिए। इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। जहां पर सहारा योजना की बात है, मैं भी मानता हूं कि पैंतीस हजार-चालीस हजार लोग, जितने भी लोग सहारा योजना से जुड़े थे या हैं, जिन्हें पेंशन मिलती है या तीन हजार रुपये महीना मिलते हैं। उनके लिए यह सुविधा जरूरी है। जिन लोगों को अपनी दवाई और दूसरे खर्चों के लिए पैसे मिलते हैं, उनको समय पर पैसा मिलना बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें बिल्कुल तर्कसंगत हैं और इनके ऊपर काम करना हमारे लिए भी जरूरी है। सरकार भी इसके ऊपर काम कर रही है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि हम हिमकेयर के अंदर एक बदलाव करके इसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स के अंदर मजबूत करेंगे। हिमकेयर को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स से खत्म करना सरकार का एक कदम था क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स में कई गलतियां पाई गई थीं। लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स के अंदर हिमकेयर योजना को मजबूती से खड़ा करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और यह प्राथमिकता भी है। इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स में जहां हिमकेयर है, उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। अगर किसी को पंखे में हवा मिल रही है और पंखे के अंदर किसी तरह से थोड़ी-सी कमी आ जाए या पंखे को थोड़ा कम कर दिया जाए तो हम कहते है कि हमें पंखे की हवा पूरी चाहिए, तो पूरी ही चाहिए, उस पर काम करना जरूरी है। जहां अच्छा काम होने की बात हुई है, वहां मेरा निवेदन विपक्ष के

नेता और विपक्ष के हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी रहेगा। जब आप कुछ कहते हैं तो लोग सोचते हैं कि पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। इसलिए जहां सरकार ने अच्छे काम किए हैं, वहां उन फैक्ट्स और सरकार की सरहाना भी करनी चाहिए। जहां टांडा मेडिकल कॉलेज में रीनल ट्रांसप्लांट शुरू हुआ है। पहले किडनी के इलाज के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था। आज वहां रीनल ट्रांसप्लांट हो रहा है और लोगों को ट्रांसप्लांट के लिए लाखों रुपये खर्च करके बाहर नहीं जाना पड़ रहा है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

25.08.2026/1705/AT/YK/01

श्री आर0एस0 बाली जारी.....

यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह इसी सरकार में हुआ है और माननीय मुख्य मंत्री महोदय के प्रयासों से हुआ है। हम लोग रीनल ट्रांसप्लांट वाले दिन अस्पताल में जाकर बैठे थे और हमने वीडियो कॉल के माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से बात की थी। अगर इतनी बड़ी चीज रीनल ट्रांसप्लांट के रूप में टांडा में आई, तो यह बहुत बड़ी बात थी।

रोबोटिक रीनल ट्रांसप्लांट टांडा में शुरू किया गया और 225 रोबोटिक सर्जरी टांडा में हो चुकी हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। अगर 225 रोबोटिक सर्जरी टांडा में हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों का टांडा पर बहुत बड़ा विश्वास है। ओपन हार्ट सर्जरी, जिसके लिए लोग बाहर जाते थे, कार्डियक और दिल के रोग के मरीजों की सर्जरी अब टांडा में हो रही है। रोबोटिक सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, एडवांस ट्रॉमा एंड इमरजेंसी सर्विस, एडवांस आई0सी0यू0 और नई एडवांस एक्स-रे मशीन यहां पर हैं।

मैं बताना चाहूंगा कि कल बात हो रही थी कि सी0टी0 स्कैन खराब है और एक्स-रे मशीन खराब है। मैं इसका पूरा विवरण लेकर आया हूं। आपको जानकर थोड़ा कष्ट भी होगा और हो सकता है कि आप इसकी सराहना भी करें और इस बात को मानें भी। मैं आपका ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहूंगा, खासकर हमारे विपक्ष के वरिष्ठ सदस्यों का, क्योंकि आपसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। माननीय विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर जी बैठे

हैं, माननीय विपिन परमार जी, हमारे चाचा जी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व स्पीकर बैठे हैं और सभी हमारे विपक्ष के नेता तथा पक्ष के हमारे सभी वरिष्ठ नेता यहां बैठे हैं। आपको पता है कि आज एक्स-रे मशीन, सी0टी0 स्कैन और एम0आर0आई0 की बात हो रही थी। एम0आर0आई0 की दो मशीनें हुआ करती थीं। मैं पहले सी0टी0 स्कैन की बात करता हूं। सी0टी0 स्कैन की जो मशीन थी, वह वर्ष 2008 में लगी थी। वर्ष 2018 में यह नॉन-फंक्शनिंग हो गई और नॉन-फंक्शनिंग होने के बाद वर्ष 2022 तक उसको बीच-बीच में ठीक कराया गया। मेरे पास आज इसका पूरा विवरण भी है कि कितने साल वह नॉन-फंक्शनल रही। आप सभी लोग सरकार में रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि मशीन को ऑर्डर करना पड़ता है, फॉरेन कंट्री से मशीन आती है और उसके लिए प्रावधान करना

25.08.2026/1705/AT/YK/02

पड़ता है। लेकिन ढाई साल आपकी सरकार में सी0टी0 स्कैन की मशीन बंद पड़ी रही। टांडा मेडिकल कॉलेज में सी0टी0 स्कैन की एक मशीन थी और सी0टी0 स्कैन कराने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था। यह बहुत बड़ी बात है। सरकार आई और इन्होंने ऑर्डर भी प्लेस किया। वर्ष 2022 में, जब इनकी सरकार थी, तब इन्हें 5 साल लगे तब जाकर वर्ष 2022 में सी0टी0 स्कैन की मशीन रिप्लेस हो पाई। एम0आर0आई0 की मशीन वर्ष 2007-08 में लगी थी। वर्ष 2018 में यह मशीन चेंज होनी थी, लेकिन इसकी रिप्लेसमेंट वर्ष 2023 में आई।

दूसरी एमआरआई ...(व्यवधान) हंस राज जी आप बार-बार में हर किसी को डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा भी अच्छी बात नहीं है। आप ऐसे इनको नहीं बोल सकते, तो आपके बारे में हम बोलेंगे। यह अच्छी बात नहीं है।...(व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य, please continue.

श्री आर0एस0 बाली : हम लोग पहली बार विधायक बनकर आए हैं, आपसे बहुत कुछ सीखते हैं।...(व्यवधान) नहीं, इनको भी मत बोलिए, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट इश्यू है। आपको कोई मेरे लिए गलत बोल रहा है, लेकिन सच्चाई बताना जरूरी है।...(व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य, please continue.

श्री आर0एस0 बाली : एक मशीन लग चुकी है और दूसरी मशीन जो है, वह लगने वाली है। उसका ऑर्डर प्लेस हो गया है, जगह बन गई है, अब मशीन आकर लगनी है। सी0टी0 स्कैन की मशीन लग गई है, एम0आर0आई0 की मशीन लग गई है और एक्स-रे की तो और भी बड़ी और दिलचस्प बात है। वर्ष 2007 में एक्स-रे मशीन लगी थी और वर्ष 2025 तक वही एक्स-रे मशीन चल रही थी। 1-10-2025 को दोनों मशीनें खराब हो गईं, क्योंकि वे पुरानी थीं। इनकी सरकार में भी इन्हें चेंज नहीं कि गई और जब हमारी सरकार आई, तब भी मशीनें चलती रहीं, जबकि इन्हें चेंज हो जाना चाहिए थी।

आज वहां दो नई मशीनें आ गई हैं और वे चल पड़ी हैं। ये लेटेस्ट मशीनें आई हैं। बल्कि फ्लोरोस्कोपी की मशीन भी आज आ गई है। फ्लोरोस्कोपी की मशीन के अंदर आप

25.08.2026/1705/AT/YK/03

वही सब चीजें कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड जो इनकी सरकार में तकरीबन हुआ करता था, उसको भी घटाया गया है। अगर इनको उसका भी डाटा चाहिए होगा, तो मैं उसका डाटा भी प्रोवाइड करूंगा। यह बहुत जरूरी है कि इस चीज को लोगों तक लाया जाए।

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी ......

25.08.2026/1710/AV/YK/1

श्री आर एस बाली---------जारी

लिवर एण्ड रीनल ट्रांसप्लांट हमने करवाया। हमने सर्जिकल के माइलस्टोन्ज अचीव किए। लिवर और पैंक्रियाज का ट्रांसप्लांट सरकार की प्राथमिकता है और हमारी सरकार इस बारे में काम कर रही है। ओपन हार्ट सर्जरी से संबंधित एडवांस कार्डियेक सर्विस के ऊपर सरकार ने विचार किया और आज टांडा मेडिकल कॉलेज में इसके ऊपर काम हो रहा है। टांडा मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी सर्विस और आई0सी0यू0 इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया। बड़ी दिलचस्प बात है, कल यहां पर बोला जा रहा था कि जहां पर मशीन्ज उपलब्ध हैं वहां पर लोगों की भी जरूरत है। बिल्कुल सही कहा गया, टांडा मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज की जरूरत थी और इस सरकार ने नर्सिंग कॉलेज को स्थापित किया। मुख्य मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री कई बार टांडा गए। पिछले वर्ष वहां पर नर्सिंग कॉलेज को विधिवत रूप से चालू कर दिया गया और इस वर्ष टांडा मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग का सैकिण्ड बैच बैठ गया है। यह बहुत बड़ी बात है कि हमारी सरकार ने एस0आर0 डॉक्टर्ज और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्ज की सीट्स बढ़ाने के साथ-साथ उनकी सैलरी भी बढ़ाई। पहले सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्ज की सैलरी 60 हजार रुपये थी जिसको इस सरकार ने एक लाख रुपये किया। इसी तरह से जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर पहले वर्ष जहां 40 हजार रुपये, दूसरे वर्ष 45 हजार रुपये तथा तीसरे वर्ष 50 हजार रुपये लेता था; उस सैलरी को 10-10 हजार रुपये हर वर्ष के हिसाब से बढ़ा दिया गया। डॉक्टर्ज को रिटेन करने के लिए क्योंकि यहां पर भी एम्ज खुल गया है तो केंद्र की तर्ज पर उनकी सैलरी स्ट्रक्चर को बढ़ाया गया और री-इम्पलॉईड डॉक्टर की सैलरी एक लाख रुपये से तीन लाख रुपये कर दी गई। यह व्यवस्था की गई कि सैलरी में उनकी पेंशन भी जुड़ जाए और प्रत्येक डॉक्टर को साढ़े चार लाख के करीब सैलरी मिले; यह बहुत बड़ी बात है। अगर मशीन्ज और मरीजों की बात की जाए तो आंकड़े कुछ और बताते हैं तथा ये आंकड़े सार्वजनिक हैं जिनको अस्पतालों से लिया जा सकता है। अगर मशीन्ज की बात की जाए तो सारी-की-सारी मशीन्ज उसमें चाहे एम0आर0आई0 की हो, सी0टी0 स्कैन की हो या रोबोटिक सर्जरी की हो; सभी मशीन्ज लगाई गईं। अगर डॉक्टर्ज की बात की जाए तो यहां पर एस0 आर0, जे0 आर0, एम0बी0बी0एस डॉक्टर्ज के साथ-साथ नर्सिज की पोस्ट्स को भी बढ़ाया गया।

25.08.2026/1710/AV/YK/2

सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए।

श्री आर0एस0 बाली : सभापति महोदय, एक-दो चीजें बोलने को शेष रहती हैं। आपसे छोटा होने के नाते मैंने आपसे दो मिनट्स और लेने हैं। आप मुझे माफ कीजिए और इतना मेरा प्रिविलेज भी है। आपके साथ-साथ मेरा डॉ0 हंस राज जी के ऊपर भी पूरा हक है। मैं इनका छोटा भाई हूं और मैं इनसे भी हमेशा प्रिविलेज लेता हूं।

इसके अतिरिक्त पी0जी0 की सीट्स का भी विस्तार किया गया। मशीनों को बढ़ाया गया परंतु अगर आंकड़े देखे जाएं तो अभी भी जब एक अस्पताल में 6 लाख मरीज एक वर्ष में आते हैं और उनमें से 50 हजार मरीज दाखिल होते हैं तथा 40000 मरीज एक वर्ष में अपना इलाज करवाते हैं। एक अस्पताल में एक वर्ष में 6 लाख मरीज आते हैं जबकि हिमाचल की आबादी केवल 70 लाख है। आप खुद सोच सकते हैं कि हमें उसको कहीं-न-कहीं अलग तरीके से देखना पड़ेगा। अब जो अस्पतालों में सफाई कर रहा है वह भी इंसान है और नर्स व डॉक्टर भी इंसान हैं। आप जब सत्ता में होते थे तो आपने उनकी इंसानियत देखी होगी? हमें उनको अभी भी कहीं-न-कहीं समझना पड़ेगा।

कल यहां पर हमारे विपक्ष के नेता ने गोबर की बात की जबकि हैल्थ की बात हो रही थी। इन्होंने महिलाओं को 1500-1500 रुपये देने की बात भी की थी। इस प्रकार से यहां पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। सत्ता पक्ष से भी बोला गया कि केंद्र सरकार ने दो करोड़ नौकरियां देनी थीं। केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो इस प्रकार का वायदा किया गया था। इस प्रकार से 24 करोड़ नौकरियां बन चुकी हैं, हवाई चप्पल वाले ने हवाई यात्रा करनी थी तथा देश में सभी कच्चे घर वर्ष 2022 तक पक्के करवाये जाने थे। इसलिए सत्ता पक्ष की तरफ से भी बहुत कुछ बोला जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला यानी हर कोई हवाई यात्रा करेगा। परंतु आज बात पेपर लीक और चंदा चोरी की हो रही है।

एन एस द्वारा जारी

25-8-2026/1715/NS-AG/1

श्री आर0 एस0 बाली------जारी

और आज बात उन चीजों की हो रही है जो अलग-अलग हैं। नैरेटिव इस साइड से भी अलग होगा और उस तरफ से भी अलग होगा। मुझे लगता है कि अच्छे काम को अच्छा और बुरे काम को बुरा बोलना बहुत जरूरी है। मैं मुख्य मंत्री महोदय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेडिकल फील्ड में एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है। हर सरकार चाहे सत्ता पक्ष की सरकारें रही हों या विपक्ष की सरकारें रही हों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर सरकार संवेदनशील रही है। मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय से दोबारा दरख्वास्त करूंगा कि हिमकेयर के अंतर्गत जिन बातों का सभी ने उल्लेख किया है उनके ऊपर एक बार दोबारा स्टडी की जाए और पूरा डिपार्टमैंट इस पर विचार करे क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसैस, बेड चार्जिज, नर्सिंग एंड बोर्डिंग चार्जिज, सर्जन/ एनेस्थीसिया चार्जिज तथा मेडिसिन एंड ड्रग्स को अलग-अलग कर दिया गया है। इन चीजों को अलग करने की वजह से क्या हुआ है कि जिन लोगों को सुविधा मिल रही थी उनको कहीं-न-कहीं मुझे लगता है कि वह सुविधा पहले की तरह ही प्रॉपरली देना बहुत जरूरी है। सहारा योजना के संबंध में मुझे अभी बताया गया है और मेरे पास एक पर्ची भी आई है कि सारे सहारा बेनिफिशिरीज को ई0डब्ल्यू0एस0 के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया गया है। इन दो अति जरूरतमंद वर्गों को विशेष रूप से इस सुविधा की आवश्यकता है। हमारे हिमाचल प्रदेश में हम भी जरूरतमंद हैं, हर कोई जरूरतमंद है परन्तु हैल्थ की जरूरत विशेष रूप से उनको है जिनके पास पैसे की कमी है। जिन लोगों के पास पैसे हैं, वे प्राइवेट अस्पतालों में भी चले जाते हैं, चंडीगढ़ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं परन्तु जो लाखों लोग गवर्नमैंट अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं उनको इस सुविधा की आवश्यकता होती है। इसी के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी व माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी और इस सरकार ने एक बेहतरीन काम किया है और इसको आगे बढ़ाने का काम भी सभी मिलकर करेंगे।

सभापति महोदय, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। कई बार टांडा मेडिकल कॉलेज में मशीन अवेलेबल नहीं होती तो व्यक्तिगत रूप से एम0एल0ए0 होने के नाते मैं खुद टांडा में किसी पेशेंट के ऑपरेशन के लिए जरूरी मशीन अवेलेबल करवाने के

25-8-2026/1715/NS-AG/2

लिए वहां बैठता हूं और कई बार बाहर से भी मंगवाता हूं। व्यक्तिगत रूप से एक एम0एल0ए0 यही कर सकता है। बहुत-सी मशीनें लाई गई हैं और खरीदी गई हैं जिसकी मैं सराहना करता हूं।

सभापति महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

25-8-2026/1715/NS-AG/3

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय विनोद कुमार जी भाग लेंगे।

श्री विनोद कुमार : सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव वरिष्ठ सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी, श्री नीरज नैय्यर जी, डॉ0 जनक राज जी तथा श्री पवन कुमार काजल जी लेकर आए हैं, मैं भी उसमें खुद को शामिल करता हूं।

सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, काफी सदस्यों ने नियम-130 के अंतर्गत यहां पर काफी विस्तार से चर्चा की है। जिस तरह से इस चर्चा में सभी माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया है निश्चित तौर पर यह बात सही है कि हैल्थ विभाग हर परिवार और हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ ऐसा विभाग है जिसकी आवश्यकता हर जनमानस को रहती है।

(सभापति, श्री आशीष बुटेल पदासीन हुए)

मैं देख रहा था कि माननीय सदस्यों की ओर से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चार साल में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर काफी बड़ी-बड़ी बातें यहां पर की जा रही थीं। साथ ही केंद्र

सरकार, देश के प्रधान मंत्री जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को लेकर भी यहां पर जिक्र हुआ और जब भी इनकी प्रेस कांफ्रैंस होती है तो उसमें इस बात को अक्सर कहा जाता है कि केंद्र सरकार की ओर से कोई भी मदद नहीं की जाती। सभापति महोदय, मैं इस माननीय सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

25.08.2026/1720/RKS/एएस-1

श्री विनोद कुमार... जारी

कि केंद्र सरकार द्वारा पंद्रहवें वित्तायोग के अंतर्गत प्रदेश सरकार को स्वास्थ्य विभाग में 521 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे। एक ओर आप कहते हैं कि हमें केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके तहत मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पंद्रहवें वित्तायोग के अंतर्गत जो 521 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी उसमें से आधी राशि भी अभी तक सरकार की तरफ से व्यय नहीं की गई है। यहां कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया कि बंद पड़े स्वास्थ्य संस्थानों को चलाने के लिए मुख्य मंत्री ने सी0एच0ओ0 की भर्ती करवाई है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में नियुक्त सभी सी0एच0ओ0, एन0एच0एम0 के तहत केंद्र सरकार के माध्यम से नियुक्त किए गए हैं और उनका वेतन भी केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि दवाइयों को लेकर कितनी बार कंप्लेंट्स हुई है? अनेकों बार विभिन्न दवाइयों के सैंपल फेल हुए। यह जानकारी तो सामने आई कि फलां जगह छापे मारे गए और वहां पर दवाइयों के सैंपल फेल पाए गए लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि जिन कम्पनियों की दवाइयों के सैंपल फेल हुए उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई? यदि कार्रवाई नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं? यहां यह भी कहा गया कि हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधान सभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले जाएंगे। अभी मैं श्री आर0 एस0 बाली जी को सुन रहा था। वे डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा के संबंध में अपनी बात कर रहे

थे। यह अच्छी बात है लेकिन सरकार ने घोषणा की थी कि प्रदेश के सभी 68 विधान सभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जाएंगे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ये सभी स्वास्थ्य संस्थान खोल दिए गए हैं? क्या भवन पर पट्टिका लगा देने से आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बन जाता है? सरकार ने तय किया था कि प्रत्येक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध करवाए जाएंगे। हमें इस बात की जानकारी दी जाए कि ऐसे कितने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हैं जिनमें 6 के 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर कार्यरत हैं? सरकार द्वारा यह भी कहा गया था कि इन आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 134 से 350 प्रकार के टैस्ट फ्री किए जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हैं जहां यह सुविधा उपलब्ध है। इसी प्रकार अल्ट्रासाउंड, सी0टी0 स्कैन तथा

25.08.2026/1720/RKS/एएस-2

एम0आर0आई0 जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं? मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि नाचन विधान सभा क्षेत्र के सिविल अस्पताल, गोहर में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की पट्टिका तो लगा दी गई है लेकिन वहां आज तक इनमें से कोई भी सुविधा प्रारम्भ नहीं की गई है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब कोई एक्सिडैंट होता है या कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे एंबुलैंस की सुविधा नहीं मिल पाती और लोग मजबूरी में अपने चुने हुए प्रतिनिधियों, विधायकों तथा प्रधानों को फोन करते हैं। सभापति महोदय आपको भी ऐसे अनेक फोन आते होंगे लेकिन हमें उस समय पता चलता है कि एंबुलैंस का टायर ही नहीं है या एंबुलैंस में तेल तक उपलब्ध नहीं है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

25.08.2026/1725/बी.एस./ ए.एस.-1

श्री विनोद कुमार जारी...

यह है हमारी व्यवस्था परिवर्तन? हम लोगों को और गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा कैसे दे पाएंगे? इस बात को लेकर हमें सोचने की आवश्यकता है।

मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि जितनी भी हमारी पुरानी एम्बुलैंस हैं उनको तुरंत बंद करके उनकी जगह नई एम्बुलैंस लाई जाए ताकि लोगों को बेहतर एम्बुलैंस सुविधा मिल सके। कई जगह टायर और कई जगह तेल को लेकर बात आती है कि एम्बुलैंस में तेल नहीं है। इस चीज को लेकर भी हमें सोचने की आवश्यकता है।

इसके अलावा सभापति महोदय, यहां पर रोबोटिक सर्जरी को लेकर बात की गई। यह अच्छी बात है कि आई0जी0एम0सी0 में यह शुरू हो गई है और नेर चौक में भी शुरू कर दी गई है। यहां पर आदरणीय आर0एस0 बाली जी ने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज में भी यह शुरू कर दी गई है। लेकिन क्या रोबोटिक सर्जरी से सब चीजें ठीक होने वाली हैं?

आज हमें इस बात पर सोचने की आवश्यकता है कि जितने हमारे सिविल हॉस्पिटल हैं जितनी हमारी सी0एच0सी0 हैं जितनी हमारी पी0एच0सी0 हैं और जितने हमारे हेल्थ सब सेंटर हैं क्या उन सभी संस्थानों के अंदर सरकार की ओर से जो दवाईयां फ्री दी जाती थी वे दवाईयां मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं?

मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आपके सिविल हॉस्पिटल और सी0एच0सी0 के अंदर 482 प्रकार की दवाइयां फ्री दी जाती हैं। आप उन हॉस्पिटल के अंदर पता करें। मुझे लगता है कि 10 प्रतिशत दवाइयां भी आज की डेट में आपके हॉस्पिटल में उन गरीब लोगों को नहीं मिल पा रही हैं।

हमारी पी0एच0सी0 के अंदर 167 प्रकार की दवाइयां सरकार की ओर से फ्री दी जाती हैं। लेकिन आप पता करें कि उन पी0एच0सी0 के अंदर आज की डेट में वे दवाइयां लोगों को और गरीब लोगों को उपलब्ध हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इसको लेकर हमें सोचने की आवश्यकता है।

25.08.2026/1725/बी.एस./ ए.एस.-2

हमारे सब सेंटर के अंदर 91 प्रकार की ऐसी दवाइयां हैं जो फ्री दी जाती हैं लेकिन आज वे दवाइयां उन सब सेंटर में उपलब्ध नहीं हैं। इन चीजों को लेकर सरकार को सोचने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, यहां पर हिमकेयर योजना को लेकर बात की गई। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार के समय जब यह हिमकेयर योजना शुरू की गई तो लगभग 4,70,000 लोगों को इस योजना के माध्यम से लाभ दिया गया था। मुझे ध्यान में है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को भी एम्पैनल में लिया गया था। वहां पर भी लोग अपना इलाज करवाते थे क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में बहुत रश होता था। किसी का इमरजेंसी केस होता था तो स्वाभाविक है कि उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाता था।

लेकिन जब से यह व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार बनी है तब से हिमकेयर योजना के तहत गरीब लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो आप कार्रवाई करें। हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इस योजना को बंद नहीं किया जाना चाहिए। इसका लाभ उन गरीब और पात्र लोगों को लगातार मिलता रहना चाहिए। यह मेरा सरकार से निवेदन रहेगा। ...(घंटी)...

श्री विनोद कुमार : इसके साथ-ही-साथ यहां पर सहारा योजना को लेकर भी बात की जा रही थी। सभापति महोदय, हमारी सरकार के समय 22,000 लोगों को इस सहारा योजना के तहत लाभ मिलता था। लेकिन आज क्या स्थिति है? जिंदा व्यक्ति को आपकी सरकार और आपके अधिकारी मृत घोषित कर देते हैं। वह बेचारा लाइव होकर बोलता है कि मैं जीवित हूं भाई मुझे सहारा योजना का लाभ दीजिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितने भी पात्र लोग हैं और जो बैड रिडन हैं तथा जो बार-बार आपके पास एप्लिकेशन दे चुके हैं उन सभी पात्र लोगों को 'सहारा योजना' के तहत लाभ दिया जाना चाहिए। यह मेरा मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा।

सभापतिः माननीय सदस्य, एक मिनट, मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

मुख्य मंत्री : .... श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

25.08.2026/1730/डीटी/एएस-1

मुख्य मंत्री : सभापति महोदय माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ये इतने जोर से क्यों चिल्ला कर बोल रहे हैं? खैर, दो-तीन बातें मैं आपके माध्यम माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं। इस चर्चा का विस्तृत उत्तर तो स्वास्थ्य मंत्री जी ही देंगे उन्हें ही उत्तर देने की शक्तियां हैं। मैं तो बस क्लेरिफिकेशन के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे मंत्री जी के पास पावर है। सभापति महोदय, मैं दो बातें ही इस सदन में कहना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी भी रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं और रोबोटिक सर्जरी की बात श्री रणधीर शर्मा जी ने भी की थी। श्री रणधीर शर्मा जी ने कहा था कि पता नहीं रोबोटिक सर्जरी के मामले में (***) का लेन-देन हुआ होगा। उस समय इनके एक रिश्तेदार ही डी0एम0ई0 थे। कहीं आपको तो (***) नहीं दिया गया? लेकिन मैं कहूंगा कि डी0एम0ई0 ने बड़ी ईमानदारी से काम किया है और इस मशीन को मार्किट भाव से एक करोड़ रुपया सस्ता लिया है। क्योंकि इन्होंने कहा कि (***) उसमें तो नहीं लिया गया है, बस मैं उसका क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। दूसरी बात श्री विनोद जी को मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि हिमकेयर योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है तो हिमकेयर योजना का लाभ भी लोगों को मिल रहा है और सहारा योजना का लाभ भी मिल रहा है लेकिन बस सहारा योजना को शिफ्ट कर दिया गया है। अब इसे हैल्थ डिपार्टमेंट से वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत शिफ्ट किया गया है। 1500 से 3000 लोगों को सहारा योजना का लाभ मिलना शुरू भी हो गया है और लोगों की वेरिफिकेशन भी की जा रही है। आपके समय तो ऐसे लोगों को भी सहारा योजना का लाभ मिला जो पात्र ही नहीं थे और जिनको सहारा योजना की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वे आपकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, इसलिए उनको इस योजना का लाभ दिया गया। अब हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वेरिफिकेशन के काम में लगाया है। मैं सच बोल रहा हूं। मेरी बात तो सुनो। हम आपको केसिज भी बताते हैं। आप इस योजना में क्यों अप्लाई नहीं करवा रहे? इसका ऑनलाइन पोर्टल जारी है। जिसको सहारा योजना का लाभ लेना है

वह पोर्टल पर अप्लाई करे। आप पात्र लोगों से क्यों नहीं अप्लाई करवा रहे? अभी भी पोर्टल खाली है। पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल में क्या किया?

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

25.08.2026/1730/डीटी/एएस-2

सहारा योजना में भी जिन लोगों को सहारा योजना की जरूरत ही नहीं थी उनको आपने इसमें शामिल किया और उन लोगों को आपने सहारा योजना में लाभ दिया जो सहारा योजना में आने ही नहीं चाहिए थे। अब सहारा योजना का लाभ देने के लिए हमारी सरकार ने पोर्टल जारी किया है और हैल्थ से इस योजना को वेलफेयर विभाग में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यह वेलफेयर की स्कीम है। इसमें कोई भी व्यक्ति सहारा योजना की गाइडलाइंस के तहत अप्लाई करेगा तो उसको सहारा योजना का पूरा लाभ मिलेगा। इस लाभ का फायदा वेलफेयर विभाग से अभी 3,000 लोग उठाना चाह रहे हैं। विपक्ष के सदस्यों ने एक स्टैंडिंग स्लोगन लगा दिया है कि सहारा योजना बंद और हिमकेयर बंद। आपने बोला है कि हिमकेयर में कोई घोटाला नहीं हुआ। अब इनक्वायरी से इसकी परतें खुलेंगी और तथ्य आपके सामने भी आ जाएंगे। हम दिखाएंगे कि हिमकेयर में क्या-क्या घोटाला हुआ है। लेकिन हिमकेयर योजना वर्तमान सरकार द्वारा बंद नहीं की गई है। हिमकेयर योजना में पिछली पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। मैंने अभी सेक्रेटरी हैल्थ को कहा है कि हिमकेयर योजना को फ्रेश लागू किया जाएगा। फ्रेश लागू करने का मतलब यह है कि जो आज कार्ड बनेगा उसके इलाज के लिए सामान उसी समय दिया जाएगा। पिछली पेंडेंसी के ही 30 करोड़ रुपये अभी हम लोगों को दे रहे हैं। ये लोग कह रहे थे कि इसमें मेडिसिन भी नहीं मिल रही है। अभी की पेंडेंसी भी हम पूरी कर रहे हैं। आप हिमकेयर योजना में 1,000 करोड़ रुपये की देनदारी हमारे लिए छोड़ कर गये। मैं इसे घोटाला नहीं कह रहा। 1,000 करोड़ रुपये का घोटाला नहीं है-घोटाला तो 100 करोड़ रुपये का है। 1,000 करोड़ रुपये आप हिमकेयर योजना का 1000 रुपये का एरियर हमारे ऊपर छोड़कर

गये हैं। घोटाला 100 करोड़ रुपये का है। ...(व्यवधान) चलो फिर कितने करोड़ रुपये का होगा वह भी सामने आ जाएगा। अभी कुछ लोगों से इनक्वायरी हो गई है। पूछताछ होगी और सारे घोटाले पता लगेंगे कि कहां पैसे गए, किसकी टैची भरी और किसका ब्रीफकेस भरा। ये सब चीजें सामने आने वाली हैं और आपके सामने भी इसके फैक्ट्स रखेंगे। यह मैं कहना चाहता हूं। हिमकेयर योजना को हमने बंद नहीं किया है। हिमकेयर योजना में साल में चार बार कार्ड बनाए जाते हैं और चार बार के अलावा कोई और व्यक्ति भी आ जाए या कोई बीच में अचानक आ जाए तो उसका कार्ड हमारा एम0एस0 बनाता है। एम0एस0 के पास कार्ड बनाने की पावर है और प्रिंसिपल के पास भी कार्ड बनाने की पावर है। ऐसा कहना बंद कर दीजिए कि हिमकेयर योजना बंद कर दी गई है। यह गलत बात है।

25.08.2026/1730/डीटी/एएस-3

सभापति : माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी, प्लीज कंटिन्यू लेकिन जल्दि वाइंड अप भी करिए। आपका बहुत लंबा समय हो गया।

श्री विनोद कुमार : माननीय सभापति महोदय, यह जो (***) वाला शब्द है उसे पहले एक्सपंज करने की व्यवस्था दे दी गई है। मेरा निवेदन रहेगा कि मुख्य मंत्री जी ने जो अब इस शब्द का इस्तेमाल किया है उसको भी आप एक्सपंज करवा दें।

सभापति : हम इस शब्द को एग्जामिन कर लेंगे। मानीय सदस्य कृपया आप जल्दी वाइंड-अप कर लीजिए ।

श्री विनोद कुमार : माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हिमकेयर योजना को बंद नहीं किया गया है लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप कम-से-कम हॉस्पिटल के अंदर अपने किसी आदमी को भेजें।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

B.S. cont………

25.08.2026/1735/डी.सी.-एन.जी./1

श्री विनोद कुमार.......... जारी

आज भी लगभग 90 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनका हिमकेयर योजना के तहत इलाज नहीं हो रहा है। आपके डॉक्टर मना कर रहे हैं कि पिछली जो पेमेंट हमने देनी है, वह हम दे नहीं पा रहे हैं जिसके कारण हम अगला ऑपरेशन या अगला इलाज इस योजना के तहत नहीं करवा सकते। मैं माननीय मुख्य मंत्री एवं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से चाहूंगा कि जब आप रिप्लाई दें, आप निश्चित तौर पर इस बात को लेकर इस हाउस को और इस प्रदेश की जनता को विश्वास दें कि जितने भी लोग हिमकेयर योजना का कार्ड लेकर जाएंगे, उनका उपचार मुफ्त होगा। इस बात को लेकर मुख्य मंत्री जी जरूर अपनी बात यहां पर रखें।

सभापति महोदय, मैं नाचन विधान सभा क्षेत्र की कुछ बातों को लेकर के माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से बात करना चाहता हूं। मेरे नाचन विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो हमारी एक पी0एच0सी0 कनैड है और उसमें डॉक्टर भी है। लेकिन वह डॉक्टर छह दिन में से दो से तीन दिन ही पी0एच0सी0 कनैड में होता है, बल्कि बाकी तीन से चार दिन उसका डेपुटेशन कर दिया जाता है। मेरा निवेदन रहेगा कि आप आज ही सी0एम0ओ0 को ऑर्डर करें कि उसको परमानेंट वहीं पर रहने दिया जाए।

सभापति महोदय, हमारा एक धनोटू ब्लॉक है। विकास खण्ड धनोटू में लगभग 32 पंचायतें हैं और इन 32 पंचायतों में 80 हजार से ऊपर पॉपुलेशन रहती है। हमारी सरकार के समय जो पी0एच0सी0 चौक थी, उसको सी0एच0सी0 किया गया था। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि धनोटू विकास खण्ड, जिसमें 32 पंचायतें और 80 हजार से अधिक पॉपुलेशन रहती है...(घण्टी)...

सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज़ वाइंड अप कीजिए।

25.08.2026/1735/डी.सी.-एन.जी./2

श्री विनोद कुमार : सभापति महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि सरकार ने इसको डिनोटिफाई किया है, इसको पुनः नोटिफाई करने की कृपा करें। इसके अलावा हमारी सरकार के समय सिविल हॉस्पिटल, गौहर को भी 100 बेडिड हॉस्पिटल कर दिया गया था। मंत्री जी ने पूर्व कहा था कि इसके ऊपर कुछ विचार करेंगे, कुछ सोचेंगे। लेकिन अब सरकार जाने वाली है तो मेरा आग्रह रहेगा कि जाते-जाते आप निश्चित तौर पर सोच लें, क्योंकि आने वाले समय में आपको सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, मुझे इस तरह से लगता है।

सभापति महोदय, यहां पर हमारे साथी कोरोना को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। मैं निश्चित तौर पर इस बात को कहना चाहता हूं कि कोरोना का वह भयावह दौर हम सबने देखा है। उस कोरोना के बहुत बुरे वक्त में हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने अपनी ओर से बहुत बेहतर काम करने की कोशिश की है। आप सभी को ध्यान में होगा कि केंद्र सरकार की ओर से सबसे बेहतरीन वैक्सीनेशन करने के लिए हिमाचल प्रदेश की श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार को सम्मानित भी किया गया था। मैं समझता हूं कि उस वक्त कोरोना के जितने भी पेशेंट पाए गए थे, उनका इलाज सरकार की ओर से बिल्कुल मुफ्त करवाया गया था।...(घण्टी)...

सभापति : माननीय सदस्य, अब बहुत हो गया है।

श्री विनोद कुमार : सभापति महोदय, यहां पर बात आई कि उस कोरोना के दौर में किसी के गहने चोरी हो गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर गहने चोरी होने की बात की जा रही है, लेकिन आज इस प्रदेश में जो स्थिति है, उस स्थिति में इलाज करवाने के लिए हमारी बहनों को अपना मंगलसूत्र तक बेचना पड़ रहा है। इस तरह की स्थिति प्रदेश में है।

25.08.2026/1735/डी.सी.-एन.जी./3

मैं ज्यादा लंबी बात न करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद! जय हिमाचल!

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री चंद्र शेखर हिस्सा लेंगे।

श्री चंद्र शेखर : सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं उसके प्रति आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

25.08.2026/1740/DC/PB/1

श्री चंद्र शेखर जारी...

सभापति महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं संबंधित जो प्रस्ताव चर्चा में आया है, वह अति महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत प्रदेश व जिला स्तर पर तथा अपने-अपने विकास खंडों के अंतर्गत प्रदेश सरकार के माध्यम से जनता को जो सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, उनके ऊपर भी व्यापक चर्चा हो रही है। यह अति महत्वपूर्ण विषय है और जिस तरह से माननीय विपक्ष के विधायक इस पर चर्चा कर रहे हैं उससे एक बात स्पष्ट हुई है कि प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर सेवा के केंद्र बिंदु पर लाया है। मुख्य मंत्री जी की इस नई सोच से प्रदेश की जनता और माननीय विधायकों को जो अपेक्षाएं तथा उम्मीदें पैदा हुई हैं वह अपने आप में शुभ संकेत है। मुख्य मंत्री जी ने पहले बजट में जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान को लेकर उल्लेख किया था उसको लेकर सभी चाहते हैं कि उनके विधान सभा क्षेत्रों के अंदर यह मॉडल लागू हो और इसकी

स्पिरिट अक्षरशः लागू हो। जनता इस बात को देख रही है कि पिछले पौने चार वर्षों के अंदर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा परिवर्तन आया है।

मुख्य मंत्री जी ने स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम किया। डी0एच0एस0 और डी0एम0ई0 के बीच जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था उसको समय रहते दूर किया गया और उनकी खामियों को दूर किया गया। डी0एम0ई0 को मेडिकल कॉलेजों तथा डी0एच0एस0 को सिविल अस्पताल, सी0एच0सी0 और पी0एस0सी0 के निपटारे का कार्य दिया गया। इस कार्य को प्रदेश के अधिकारियों, डॉक्टरों तथा सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ईमानदारी के साथ व सरकार की स्पिरिट के साथ मिलकर पूरा किया है। आज प्रदेश पौने चार वर्षों के बाद उस मुकाम पर पहुंचा है जहां प्रदेश में डॉक्टरों की कमी खलती थी, उस कमी को काफी हद तक प्रदेश सरकार ने पाटा है।

अभी 600-700 नए डॉक्टर्ज की रिक्तियां हैं। इस प्रदेश में लगभग तीन हजार डॉक्टर्ज सेवाएं दे रहे हैं। इसमें वे मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं जिनकी हालत पहले बदतर थी। ऐसे सिविल अस्पताल जो विधान सभा क्षेत्रों के बीच में स्थापित थे, वे

25.08.2026/1740/DC/PB/2

नाममात्र के थे और रेफरल अस्पताल के तौर पर काम करते थे। पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल था कि इलाज अगर होगा तो पी0जी0आई0 और आई0जी0एम0सी0 में होगा। प्रदेश में एक विश्वास का वातावरण नहीं था। उस विश्वास के वातावरण को कायम करने में मौजूदा प्रदेश सरकार मुख्य मंत्री जी की राहनुमाई में बहुत हद तक कामयाब हुई है। इसकी रिफ्लेक्शन यह है कि विपक्ष के विधायक उम्मीद कर रहे हैं कि उनके विधान सभा क्षेत्रों में भी उस मानक को अचीव किया जाए और उस माइलस्टोन को अचीव किया जाए जिसकी उम्मीद आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों से की जाती है। मैंने पैंतीस वर्षों में एक बड़ा बदलाव अपने क्षेत्र में देखा है और मेरी महान जनता ने जो बदलाव लाया है, मैं उस बदलाव का प्रतीक हूं। निश्चित तौर पर पिछली सरकार और मौजूदा सरकार के बीच कंपैरिजन किया जाएगा कि आज की परिस्थिति और साढ़े तीन साल पहले की परिस्थिति

में क्या अंतर आया है। हम आज की बात में उसी का उल्लेख और उसी को अंडरलाइन करेंगे।

मेरे क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण सिविल अस्पताल चार, सी0एच0सी0 चार तथा पी0एस0सी0 पांच हैं। इस प्रकार तेरह बड़े स्वास्थ्य संस्थानों से क्षेत्र के अंदर सुविधाएं दी जा रही हैं।माननीय जय राम ठाकुर जी की सरकार में कहा गया था कि

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

25.08.2026/1745/ ए0पी0-01

श्री चंद्र शेखर जारी .....

धर्मपुर क्षेत्र के अंदर इतना ज्यादा विकास हुआ है, जिसका न कोई भूत है और न ही कोई भविष्य। लेकिन मैं सदन में कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय धर्मपुर, संधोल, मढ़ी, टीरा और मंडप क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों में लगभग 44 करोड़ रुपये के काम शुरू हुए थे और उन कामों को पूरा किया गया था। उसी काम को मुझे आगे बढ़ाना था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लगभग 46 करोड़ रुपये देकर उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में मेरी मदद की और उन्हें क्षेत्र की जनता को समर्पित करने की स्थिति में पहुंचाया। इस तरह अब तक मेरे क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों को मूर्त रूप देने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी भावना भी रही जो यह थी कि खानपूर्ति के लिए सी0एस0आर0 के माध्यम से एक्स-रे मशीन दी गई और अल्ट्रासाउंड मशीन भी दी गई। लेकिन ये केवल खानापूर्ति के लिए दी गई। ये मशीनें साल में आठ-दस बार खराब होती हैं। मेरा आग्रह अधिकारियों से और माननीय मंत्री जी से भी रहेगा कि उन्होंने स्वयं धर्मपुर के सिविल अस्पताल का दौरा किया है। एक लगातार सिक्वेंस बनी है कि ये मशीनें कहां से लाई गई और किस तरह लाई गई। मेरी मांग है कि सी0एस0आर0 के माध्यम से खानापूर्ति के लिए दी गई इन मशीनों को हटाया जाए ताकि जनता विश्वास के साथ अस्पताल में आ सके। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी आश्वासन

दिया है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वहां सी0टी0-स्कैन देने का ऐलान किया है। धर्मपुर और आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, संधोल जिसे हाल ही में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान घोषित किया गया है, इन दोनों बड़े अस्पतालों के लिए एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और सी0टी0-स्कैन की तीनों महत्वपूर्ण मशीनें मुहैया कराई जाएं ताकि ये कार्य सुचारू तौर पर हो सके और सी0एस0आर0 के द्वारा दी गई मशीनों पर निर्भर न रहना पड़े। मेरे क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पिछले छः महीने के अंदर लगभग 60-62 हजार ओ0पी0डी0 तथा इंडोर एडमिशन हुई हैं, जिसमें लगभग ढाई गुना वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि जनता का विश्वास बढ़ा है तथा मुहैया कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाएं काफी हद तक

25.08.2026/1745/ ए0पी0-02

आपस में मैच कर रही हैं। मैं सरकाघाट को भी इसमें शामिल करना चाहता हूं। पहली बार हमारे क्षेत्र में चाहे धर्मपुर हो या सरकाघाट का क्षेत्र, यहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध हुए हैं। पहले इस क्षेत्र के अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर देखने को ही नहीं मिलते थे। इस प्रकार की कोई प्रजाती हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं पाई जाती थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मौजूदा समय में लगभग साढ़े छः सौ स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर मुहैया हुए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक विश्वास जगा है और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग भी बढ़ गई है। अब सरकार के ऊपर यह दबाव आया है कि स्वास्थ्य सेवाओं का इंजन अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के हवाले किया जाएगा तभी स्वास्थ्य सेवाओं के मानकों को अचीव किया जा सकता है। अभी यह संख्या साढ़े छः सौ के आसपास पहुंची है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले सवा साल या डेढ़ साल में लगभग एक हजार स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर उपलब्ध हो जाएं, तभी आम आदमी की पी0जी0आई0 की दौड़ और मेडिकल कॉलेजों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए मैं सरकार, माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि सरकाघाट के अंदर पहली बार छः स्पेशलिस्ट डॉक्टर

मुहैया हुए हैं। इस समय वहां दस डॉक्टर हैं और धर्मपुर क्षेत्र के अंदर चार डॉक्टर हैं। एक मंडप क्षेत्र के अंदर और एक संधोल में है। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, संधोल को घोषित किया गया है, उस एवज में अब उसका कोटा बढ़ाया गया है। वहां नए डॉक्टर चाहिए और धर्मपुर के लिए भी नए डॉक्टर चाहिए। एक बात और है कि यह जो ग्रामीण क्षेत्र को शहर से अलग देखा जाना चाहिए। केवल डॉक्टरों की फैसिलिटी ही नहीं चाहिए बल्कि डॉक्टरों को भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सुविधाएं चाहिए। उन मूलभूत सुविधाओं के लिए सभी एकजुट होकर, चाहे विधायक हों, अधिकारी हों या छोटा कर्मचारी हो, स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए काम करें। इसमें सी0बी0एस0ई0 स्कूल है, इन स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाना चाहिए तथा सिविक बॉडीज जैसी मूलभूत सुविधाएं भी शामिल की जानी चाहिए। जिस तरह से मौजूदा सरकार ने

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

25.08.2026/1750/AT/HK/01

श्री चंद्र शेखर जारी .....

जिस तरह से मौजूदा सरकार ने संधोल तथा धर्मपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिया है, कम से कम पंचायत के दर्जे से ऊपर उठकर अगर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां आना चाहता है, तो एक छोटा-मोटा शहर तो हो, जहां उसे तथा उसके परिवार को न्यूनतम सुविधाएं मिल सकें। यह बात भी मैं इस सभागार में उल्लेखनीय रूप से कहना चाहता हूं। एक बात और है, जिसको मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, इनको दो सालों के अंदर जो सेवा देनी होती है, उस पर भी विचार होना चाहिए। पहले वह मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करने के लिए चाहे पी0जी0आई0 जाता है या आई0जी0एम0सी0 आता है। जब वह स्पेशलिस्ट हो जाता है, तो अचानक से जो मार्केटाइजेशन हुई है, जो आज मंडी बन गई है, पैसे की मंडी बन गई है, उसकी रिफ्लेक्शन स्वास्थ्य सेवाओं में भी दिखाई देती है। दो साल नौकरी करने के बाद वह डॉक्टर अचानक गायब हो जाता है। नज़दीक के किसी बड़े अस्पताल का

बड़ा-सा फट्टा जब वह देखता है और उस फट्टे के अंदर उसे चार लाख रुपये का पैकेज मिलता है, तो वह प्रदेश की जनता और उस जनता के पास, जिसने उससे उम्मीद की थी कि वह गांव के अंदर आकर सेवाएं देगा, वापस नहीं आता है।

इसलिए जो दो साल की सेवाओं का कार्यकाल न्यूनतम रखा गया है, यह विचारणीय विषय है। इसके ऊपर विचार होना चाहिए कि जिस डॉक्टर को स्पेशलाइज्ड करने में इतना पैसा खर्च हुआ है, चाहे वह किसी भी संस्थान के अंदर खर्च हुआ हो, उस डॉक्टर को दो साल नहीं, बल्कि कम से कम आठ साल की सर्विसेज प्रदेश को देनी चाहिए। तब जाकर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में जो गैप आया है, उस गैप को पूरा किया जा सकता है। अन्यथा इस वक्त जिले के अंदर रेडियोलॉजी का कोई डॉक्टर नहीं है, केवल मेडिकल कॉलेज के अंदर है। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट हुआ, उसने दो साल लगाए और उसके बाद उसे साढ़े तीन लाख रुपये का पैकेज मिलता है। यह सामने वालों की दिक्कत नहीं है, यह हमारी दिक्कत नहीं है, अंततः यह जनता की दिक्कत है और इस जनता की दिक्कत को समझाने और दूर करने के लिए हम नाकामयाब हो रहे हैं।

25.08.2026/1750/AT/HK/02

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अंतरिम व्यवस्था की। आंतरिक व्यवस्था के तहत एम0ओ0 को हर बड़े अस्पताल से लिया गया और उन्हें छह महीने से आठ महीने की ट्रेनिंग रेडियोलॉजी की दी गई, ताकि उस गैप को भरा जा सके। हमारी जो मशीनें हैं, चाहे वे अल्ट्रासाउंड की हों या एक्स-रे की मशीनें हों, उनके ऊपर काम करने का एक माहौल और वातावरण उन्हें मिल सके। मैं इसके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यह सरकार की संवेदनशीलता है कि इसके अंतर्गत काम हो रहा है। यह महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं कुछ और बातों का जिक्र करना चाहता हूं। हमारे सामने से कोई नहीं कहेगा कि नैर चौक के अंदर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जो लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर नैर चौक मेडिकल कॉलेज है, वह मध्य क्षेत्र का इलाका है। आई0जी0एम0सी0 और टांडा के बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण मेडिकल संस्थान है, जहां सबसे ज्यादा फुटफॉल और रश है, वह नैर चौक के अंदर है। कुल्लू वहां पर है, मंडी जिले

के दस विधान सभा क्षेत्र हैं, कुल्लू के चार विधान सभा क्षेत्र हैं। यह हमीरपुर के नज़दीक का क्षेत्र भी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमीरपुर के अंदर बहुत आगे बढ़कर और एग्रेसिवली काम किया है। इसलिए अब हमीरपुर का लगता हुआ क्षेत्र भी उस तरफ हो गया है, लेकिन जो कहानी सामने आई है, वह नैर चौक के ऊपर आई है। सभापति महोदय, हिमकेयर के ऊपर बड़ी बातें हुई हैं। यह बहुत अच्छी योजना है।

Chairman : Hon'ble Member, please start toinding-up.

श्री चंद्र शेखरः मौजूदा सरकार इसके ऊपर बहुत गंभीरता से काम कर रही है। लेकिन मैं पिछली सरकार के उस बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम हिमकेयर के ऊपर कुछ जरूर कहना चाहता हूं। मैं उसी संदर्भ में बात करना चाहता हूं। सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश में 135 संस्थान थे, जिन्हें पिछली सरकार ने हिमकेयर के अंतर्गत लिया था और मेरे जिले में 19 थे। अब आप यहां से देखिए कि जिस मेडिकल कॉलेज के आसपास हिमकेयर के अंतर्गत 19 अस्पताल लिए गए, वहां निजी अस्पताल पैदा हुए। लोग उन निजी अस्पतालों पर ज्यादा विश्वास करते थे और नैर चौक मेडिकल कॉलेज के अंदर कम विश्वास करते थे। इसके पीछे एक बड़ी और लंबी स्टोरी है। स्टोरी यह है कि अंदर

25.08.2026/1750/AT/HK/02

डॉक्टर सी0टी0 स्कैन लिखते थे और अस्पताल के गेट के बाहर बड़े-बड़े फट्टे लगे हुए थे। इतने बड़े फट्टे तो मुख्य मंत्री के स्तर के व्यक्ति के भी नहीं लगते हैं, जितने बड़े फट्टे सीटी स्कैन वालों ने लगा रखे थे। तो मॉडल यह था कि अंदर लिखवाओ और बाहर कमाओ। अंदर लिखवाओ और बाहर कमाओ। यही परिस्थिति थी।

आज मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि पहली बार नैर चौक मेडिकल कॉलेज की सुध ली गई है। आज पिछले सात महीने का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं। लगभग डेढ़ लाख लोग अपना इलाज इनडोर में करवा चुके हैं, पिछले छह-सात महीने के अंदर नैर चौक में। इसका मतलब है कि नैर चौक मेडिकल कॉलेज में लोगों का विश्वास जगा है। कम से कम अब एम्स की तरफ जो

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी ......

25.08.2026/1755/AV/yk/1

श्री चंद्र शेखर---------जारी

अब मरीज एम्ज की तरफ जाने की नहीं सोच रहा और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसको नेरचौक मेडिकल कॉलेज में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हुई हैं। पहली बार हुआ कि किसी सरकार ने नेरचौक होस्पिटल को 70 करोड़ रुपये दिए। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी घोषणाएं हैं जोकि जमीन पर उतरेंगी। लेकिन मैं आज की डेट के हिसाब से सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहा हूं। नेरचौक मेडिकल कॉलेज को रोबोटिक सर्जरी के लिए 28 करोड़ रुपये दिए गए। मुझे सदन के साथ-साथ जिला मण्डी तथा कुल्लू के लोगों को भी बताना है कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज में अभी तक 140 सर्जरीज सफलतापूर्वक की जा चुकी हैं। नेरचौक मेडिकल कॉलेज की ये अभी तक की अचीवमैंट्स हैं। इसके अतिरिक्त एम0आर0आई0 के लिए थ्री टेसला मशीन दी गई जोकि मण्डी और नेरचौक के लोगों ने पहली बार देखी। वरना वे हिमकेयर के हिसाब से बड़े-बड़े निजी होस्पिटल्ज के धक्के खाते थे। वहां पर पिछली सरकार के कार्यकाल में केवल 8 एसिस्टेंट प्रोफैसर्ज थे जोकि अभी 24 हैं यानी तीन गुणा छलांग लगी है। वहां पर केवल 17 प्रोफैसर्ज थे और आज की डेट में उनकी संख्या 22 हैं। इसके अतिरिक्त वहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्ज की संख्या 46 थी जोकि वर्तमान में 63 हो चुके हैं। इसी तरह से स्टाफ नर्सिज की संख्या 252 से 340 पहुंच गई हैं। वहां पर पहले सपोर्ट स्टाफ लगभग 500 था, जिसकी संख्या वर्तमान में 575 के करीब हो गई है। वहां पर जो ऊपर से लेकर निचले स्तर तक मैन पावर बढ़ाई गई है उससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आया है। प्रदेश में जब वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे औरे माननीय श्री कौल सिंह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री थे तो उस वक्त नेरचौक मेडिकल कॉलेज आया था। उस समय केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर फर्नांडिस जी की कृपा से यह मेडिकल कॉलेज नेरचौक में स्थापित हुआ था। आज वहां पर अण्डर ग्रेजुएट छात्रों के लिए 34 कमरों का होस्टल तैयार हो रहा है। इसके अतिरिक्त वहां पर एक महीने के अंदर-अंदर कैथ लैब स्टार्ट होने जा रही है। वर्ष 2025 में नेरचौक में एण्डोस्कोपी शुरू की गई तथा वहां पर एडवांस डाइग्नोस्टिक सेंटर ऐस्टेब्लिश हुआ।

25.08.2026/1755/AV/yk/2

नेरचौक मेडिकल कॉलेज के अंदर हाई टैक्नोलॉजी की सी0टी0 स्कैन मशीन इंस्टॉल होगी।

मैं कोई लम्बी बात नहीं करना चाहता बल्कि इतना कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव लाया गया वह इस मन्शा से लाया गया कि हिमकेयर और सहारा योजनाओं के संदर्भ में एक नेरेटिव सैट किया जाए तथा यह बताया जाए कि प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं किया गया। जबकि माननीय सुखविन्दर सिंह सुक्खू के इस युग को यदि याद किया जाएगा तो स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में लाए गए बहुत बड़े परिवर्तन के लिए किया जाएगा। ठीक है, सरकार के समक्ष चुनौतियां बहुत हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है। लेकिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री के साथ पूरा विधायक दल खड़ा है उसमें चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हैं या शिक्षा का क्षेत्र, ऑर्गेनिक खेती या फिर प्रदेश के अंदर बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार मुहैया करवाने की बातें हैं। इन सबके लिए हमारा विधायक दल हमेशा माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ खड़ा है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसलिए आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : नियम-130 के अंतर्गत चर्चा कल भी जारी रहेगी।

अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

यशपाल शर्मा
सचिव

शिमला : 171004
दिनांक : 25.08.2026